शिक्षा निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सहायक सामग्री

(2022-2023)

कक्षा : ग्यारहवीं

राजनीति विज्ञान

मार्गदर्शन:

श्री अशोक कुमार
सचिव (शिक्षा)

श्री हिमांशु गुप्ता
निदेशक (शिक्षा)

डॉ. रीता शर्मा
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल एवं परीक्षा)

समन्वयक:

श्री संजय सुभास कुमार
उप शिक्षा निदेशक (परीक्षा)

श्रीमती सुनीता दुआ
विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

श्री राजकुमार
विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

श्री कृष्ण कुमार
विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

उत्पादन मंडल

अनिल कुमार शर्मा

दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो में राजेश कुमार, सचिव, दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, 25/2, पंखा रोड, संस्थानीय क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा मैसर्स अरिहन्त ऑफसेट, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

ASHOK KUMAR
IAS

सत्यमेव जयते

सचिव (शिक्षा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
दूरभाष: 23890187 टेलीफैक्स : 23890119

Secretary (Education)
Government of National Capital Territory of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054
Phone : 23890187, Telefax : 23890119
E-mail : secyedu@nic.in

Message

Remembering the words of John Dewey, "Education is not preparation for life, education is life itself", I highly commend the sincere efforts of the officials and subject experts from Directorate of Education involved in the development of Support Material for classes IX to XII for the session 2022-23.

The Support Material is a comprehensive, yet concise learning support tool to strengthen the subject competencies of the students. I am sure that this will help our students in performing to the best of their abilities.

I am sure that the Heads of Schools and teachers will motivate the students to utilise this material and the students will make optimum use of this Support Material to enrich themselves.

I would like to congratulate the team of the Examination Branch along with all the Subject Experts for their incessant and diligent efforts in making this material so useful for students.

I extend my Best Wishes to all the students for success in their future endeavours.

(Ashok Kumar)

HIMANSHU GUPTA, IAS
Director, Education & Sports

सत्यमेव जयते

Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Room No. 12, Civil Lines
Near Vidhan Sabha,
Delhi-110054
Ph.: 011-23890172
E-mail : diredu@nic.in

MESSAGE

"A good education is a foundation for a better future."
- Elizabeth Warren

Believing in this quote, Directorate of Education, GNCT of Delhi tries to fulfill its objective of providing quality education to all its students.

Keeping this aim in mind, every year support material is developed for the students of classes IX to XII. Our expert faculty members undertake the responsibility to review and update the Support Material incorporating the latest changes made by CBSE. This helps the students become familiar with the new approaches and methods, enabling them to become good at problem solving and critical thinking. This year too, I am positive that it will help our students to excel in academics.

The support material is the outcome of persistent and sincere efforts of our dedicated team of subject experts from the Directorate of Education. This Support Material has been especially prepared for the students. I believe its thoughtful and intelligent use will definitely lead to learning enhancement.

Lastly, I would like to applaud the entire team for their valuable contribution in making this Support Material so beneficial and practical for our students.

Best wishes to all the students for a bright future.

(HIMANSHU GUPTA)

Dr. RITA SHARMA
Additional Director of Education
(School/Exam)

सत्यमेव जयते

Govt. of NCT of Delhi
Directorate of Education
Old Secretariat, Delhi-110054
Ph.: 23890185

संदेश

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने अपने विद्यार्थियों को उच्च कोटि के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप विद्यार्थियों के स्तरानुकूल सहायक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। कोरोना काल के कठिनतम समय में भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए संबंधित समस्त अकादमिक समूहों और क्रियान्वित करने वाले शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ।

प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की सहायक सामग्रियों में सी.बी.एस.ई. के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। साथ ही साथ मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इन सहायक सामग्रियों में कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री को भी सरलतम रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि शिक्षा निदेशालय के विद्यार्थियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके।

मुझे आशा है कि इन सहायक सामग्रियों के गहन और निरंतर अध्ययन के फलस्वरूप विद्यार्थियों में गुणात्मक शैक्षणिक संवर्धन का विस्तार उनके प्रदर्शनो में भी परिलक्षित होगा। इस उत्कृष्ट सहायक सामग्री को तैयार करने में शामिल सभी अधिकारियों तथा शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी विद्यार्थियों को उनके उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ।

रीता शर्मा

(रीता शर्मा)

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता और अखंडता**] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

शिक्षा निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सहायक सामग्री

(2022-2023)

राजनीति विज्ञान

कक्षा : ग्यारहवीं

निःशुल्क वितरण हेतु

दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित

SUPPORT MATERIAL

POLITICAL SCIENCE

Class XI (2022-23)

TEAM LEADER :

Ms. Renu Kashyap	Vice Principal	SOSE/RPVV, Kishan Ganj

MEMBER :

1. Ms. Nishi Prabha	Lecturer	SOSE/RPVV, Nand Nagri
2. Mr. Prem Kumar	Lecturer	SOSE/RPVV, Sector-10, Dwarka
3. Dr. Alpna Singhal	Lecturer	SOSE/RPVV, Sector-22, Dwarka
4. Ram Swaroop Meena	Lecturer	SOSE/RPVV, Karol Bagh Link Road
5. Ankesh Kumar Meena	Lecturer	SV, New Police Line

विषय–सूची

		पेज नं.
CBSE Syllabus		**xvii**
Course Content		xviii
Question Paper Design (प्रश्नपत्र प्रारूप)		xx
1.	संविधान	1
2.	चुनाव और प्रतिनिधित्व	25
3.	विधायिका	43
4.	कार्यपालिका	65
5.	न्यायपालिका	88
6.	संघवाद	103
7.	स्थानीय शासन	117
8.	राजनीतिक सिद्धांत	135
9.	स्वतंत्रता	146
10.	समानता	162
11.	न्याय	174

12. अधिकार 194

13. नागरिकता 214

14. राष्ट्रवाद 234

15. धर्म निरपेक्षता 248

अभ्यास प्रश्न पत्र 261

अभ्यास प्रश्न पत्र–2022-23 266

POLITICAL SCIENCE (028)

Class XI (2022-23)

Total Marks = 100(80+20)

A.Theory **Max Marks: 80**

Time: 3 hrs.

Part A: Indian Constitution at Work

Units	Contents	Marks
1	Constitution	12
2	Election and Representation	10
3	The Legislature	
4	The Executive	08
5	The Judiciary	
6	Federalism	10
7	Local Governments	
	Total	40

Part B: Political Theory

Units	Contents	Marks
8	Political Theory: An Introduction	04
9	Liberty	10
10	Equality	
11	Justice	08
12	Rights	
13	Citizenship	10
14	Nationalism	
15	Secularism	08
	Total	40

B. Project Work:

20 Marks Grand

Total = 100 Marks

POLITICAL SCIENCE

(Code No. 028) (2022-23)

Rationale

At the senior secondary level, students who opt for Political Science are given an opportunity to get exposed to the diverse concepts of the discipline helping them to be a global citizen and develop skills to understand, apply and evaluate. At this level, there is a need to enable students to have the skills to engage with political processes that surround them and provide them with an understanding of the historical context that has shaped the present. The different courses expose the students to various streams of the discipline of Political Science: Political Theory, Indian Politics and International Politics. Concerns of the other two streams - Comparative Politics and Public Administration- are accommodated at different places in these courses. In introducing these streams, special care has been taken not to burden the students with the current jargon of the discipline. The basic idea here is to lay the foundations for a serious engagement with the discipline and develop competencies related to Political Science to prepare them for higher education, learning and knowledge.

Competencies and Outcomes:

1. Indian Constitution at Work:

1.1 Competency: Understanding, identifying and analyzing the key features, historical processes and working of the Constitution of India.

1.2 Outcomes: The students will:

1.2.1 Understand the historical processes and the circumstances in which the Constitution was drafted.

1.2.2 Be familiar with the diverse perspectives that guided the makers of the Indian Constitution.

1.2.3 Identify key features of the Constitution and compare these to other constitutions in the world.

1.2.4 Analyse the working of the Constitution in real life.

2. Political Theory:

2.1 Competency: Understanding, critically evaluating and applying political theory

2.2 Outcomes: After the course the students will:

2.2.1 Understand different themes and thinkers associated with the real life.

2.2.2 Develop the skills for logical reasoning

2.2.3 Meaningfully participate in the issues and concerns of political life surrounding them.

3. Contemporary World Politics:

3.1 Competency: Understanding, analyzing the Contemporary World Politics

3.2 Outcomes: After the course the students will:

3.2.1 Understand the contemporary world.

3.2.2 Understand the key political events and processes in the post-cold war era.

3.2.3 Analyze various global institutions, processes and events shaping their lives.

4. Politics in India after Independence:

4.1 Competency: Critically evaluate and understand, analyze politics in India after Independence

4.2 Outcomes: After the course the students will:

4.2.1 Understand and analyze constitutional institutions, figures and their working in the post-independence period; political events, trends, other facts and figures and contribution of eminent personalities from the post-independence to contemporary India.

4.2.2 Develop their capacity to link political policies and processes with contemporary realities.

4.2.3Encourage the students to understand and analyse the challenges for contemporary India.

Question Paper Design (2022-23)
POLITICAL SCIENCE (CODE NO. 028)
CLASS XI

TIME: 3 Hours **Max. Marks: 80**

S.No.	Competencies
1	**Demonstrative Knowledge + Understanding** (Knowledge based simple recall questions, to know specific facts, terms, concepts, principles or theories, identify, define, or recite, information) (Comprehension – to be familiar with meaning and to understand conceptually, interpret, compare, contrast, explain, paraphrase information)
2	**Knowledge / Conceptual Application** (Use abstract information in concrete situation, to apply knowledge to new situations; use given content to interpret a situation, provide an example or solve a problem)
3	**Formulation Analysis, Evaluation and Creativity** Analysis & Synthesis- classify, compare, contrast, or differentiate between different pieces of information; organize and/or integrate unique pieces of information from a variety of sources; includes map interpretation

Project Work: 20 Marks

Details of Project Work

1. The Project work will be implemented for 20 Marks.
2. Out of 20 marks, 10 marks are to be allotted to viva voce and 10 marks for project work.
3. For class XII, the evaluation for 20 marks project work should be done jointly by the internal as well as the external examiners.
4. The project can be individual/pair/group of 4-5 each. The Project can be made on the topics given in the syllabus of a particular class.
5. The suggestive list of activities for project work is as follows: -

   Role Play, Skit, Presentation, Model, Field Survey, Mock Drills/Mock Event etc.
6. The teacher should give enough time for preparation of the Project Work. The topics for Project Work taken up by the student must be discussed by the teacher in classroom.

अध्याय-1

संविधान

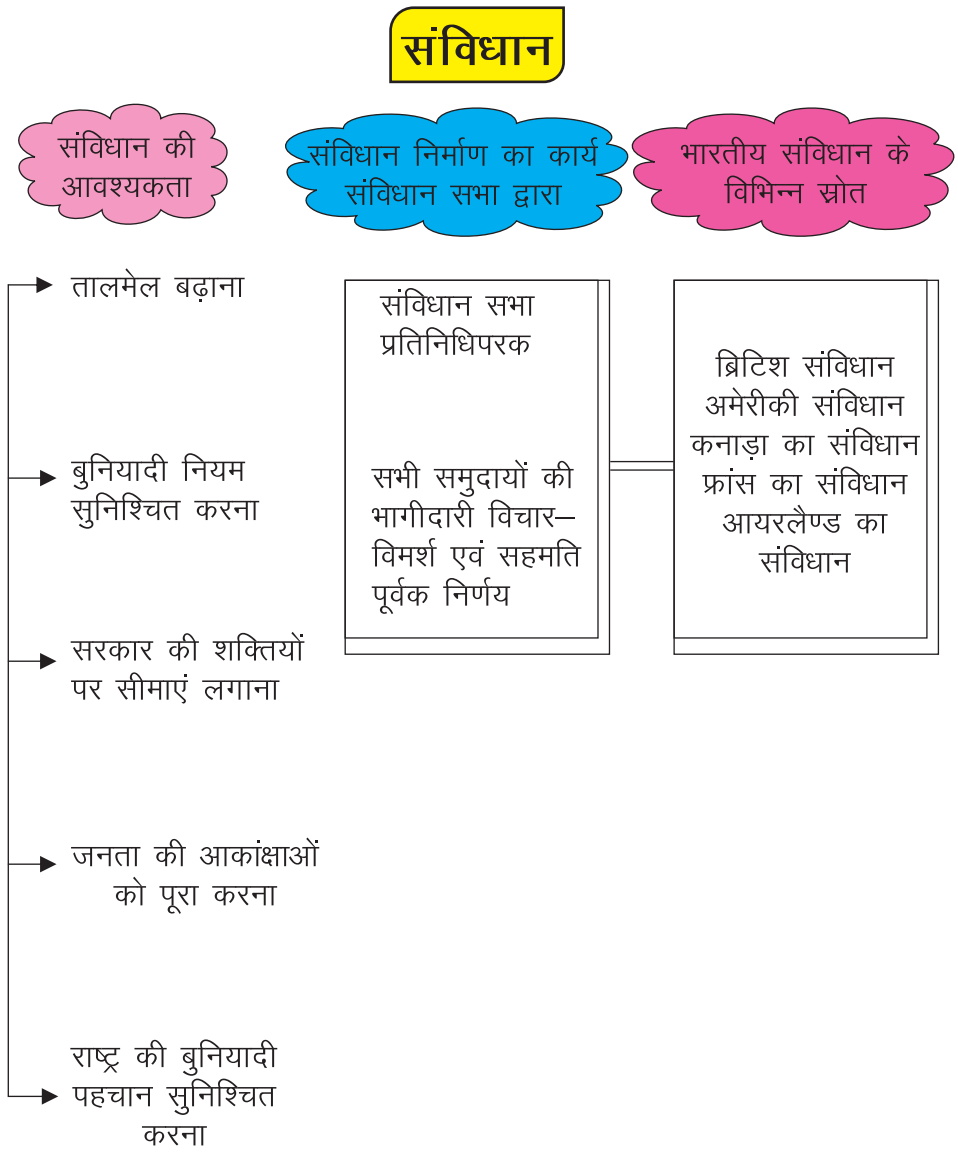
संविधान
संविधान की आवश्यकता
संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा
भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत
तालमेल बढ़ाना
बुनियादी नियम सुनिश्चित करना
सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना
जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना
राष्ट्र की बुनियादी पहचान सुनिश्चित करना
संविधान सभा प्रतिनिधिपरक
सभी समुदायों की भागीदारी विचार–विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णय
ब्रिटिश संविधान
अमेरीकी संविधान
कनाड़ा का संविधान
फ्रांस का संविधान
आयरलैण्ड का संविधान

अध्याय के मुख्य बिन्दुः

संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता, संविधान का निर्माण, संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान की विशेषताएं, व्यक्तिगत उपलब्धि।

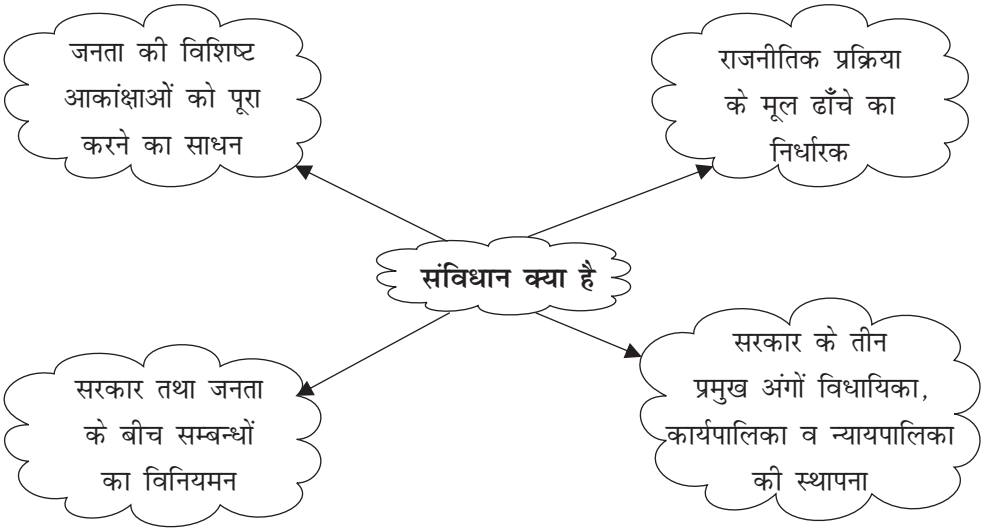

संविधान की आवश्यकताः–

- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है।
- संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है।
- संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।
- संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है।
- एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है।

भारतीय संविधान सभा का निर्माणः–

- जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लार्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की।
- कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार–संविधान निर्माण–निकाय की सदस्य संख्या–389 निर्धारित की गई। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गर्वनरों के अधीन ग्यारह प्रांतो से, 04 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों (दिल्ली, अजमेर–मारवाड, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान) से और 93 प्रतिनिधि–भारतीय रियासतों से लिए जाने थे।
- ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा मे स्थान दिए गए। (10 लाख लोगों पर एक स्थान)
- प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों– मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
- 3 जून, 1947, मांउटबेटन योजना के अनुसार भारत–पाकिस्तान विभाजन तय हुआ, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य–संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई।

संविधान सभा का गठनः–

- संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन–दिन–सोमवार, 09 दिसम्बर 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ।
- 9 दिसम्बर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वही संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चुना गया।
- 13 दिसम्बर 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता–सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।
- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं।

– संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई।
– 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

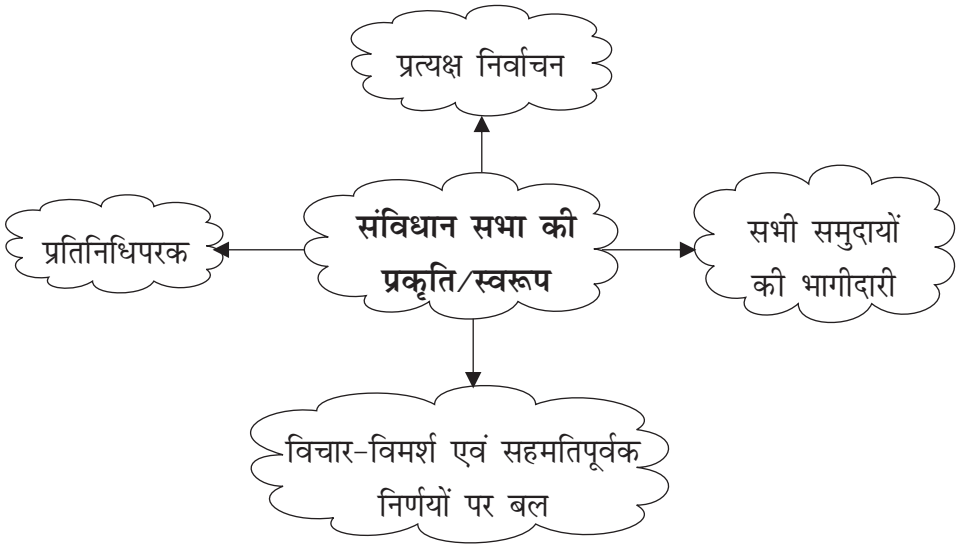

भारतीय संविधान के स्रोतः–

– संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था।
– 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।
– अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई जैसे :–

(क) ब्रिटिश संविधानः

(i) सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला।
(ii) सरकार का संसदीय स्वरूप।
(iii) कानून के शासन का विचार।
(iv) विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी –
कानून निर्माण की विधि।

(ख) अमेरिका का संविधानः

(i) मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना

(ii) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उप राष्ट्रपति का पद

(ग) आयरलैंड का संविधानः

(i) राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान

(घ) फ्रांस का संविधानः

(i) स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त।

(ड.) कनाडा का संविधानः

(i) एक अर्द्ध–संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था)।

(ii) अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त।

इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ (Bouquet) भी कहा जाता है जिसमें विभिन्न देशो से लिए गए सिद्धान्त रुपी पुष्प शामिल है।

संविधान का राजनीतिक दर्शनः–

- संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि।
- संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं।
- हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चल कर उद्देश्य प्राप्त करें।

संविधान का मुख्य सार– संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है

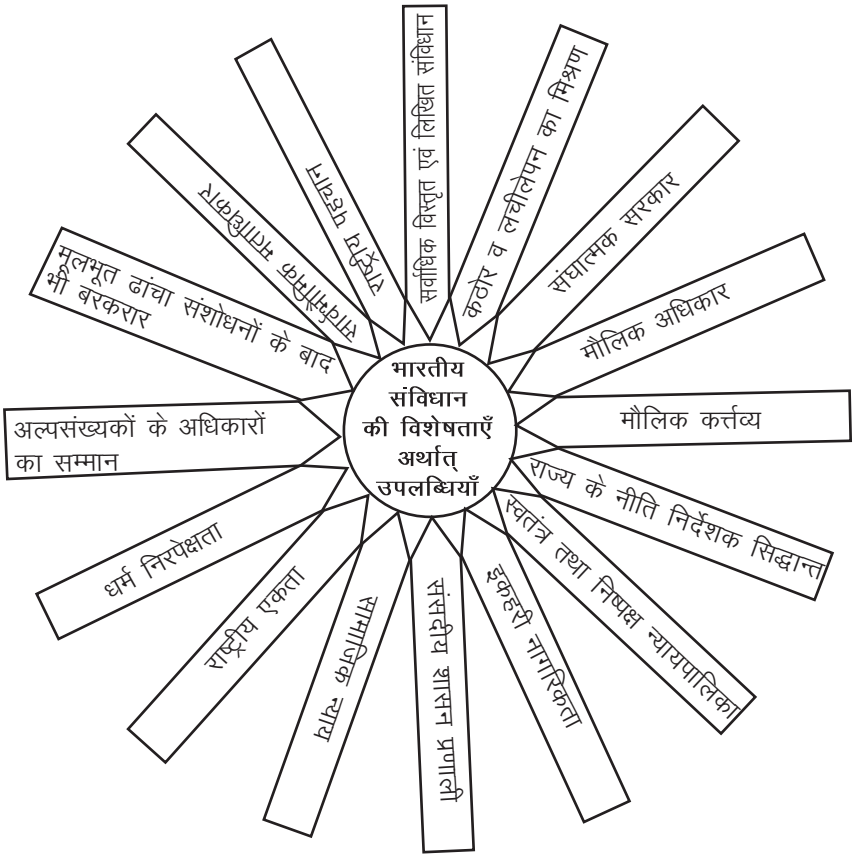

जवाहर लाल नेहरू के अनुसार–''भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊँच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है।''

संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है जैसेः–

- **स्वतंत्रता**
- **सामाजिक न्याय**
- **अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान**
- **धर्म–निरपेक्षता**
- **सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार**
- **संघवाद आदि**

प्रक्रियागत उपलिब्धः–

- संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है।
- संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहती थी। वे समझौतों को महत्व देते थे। (शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्व अनुमति को स्पष्ट करेंगे।)

  संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है।

संविधान की आलोचना के बिंदुः–

- बहुत लंबा तथा विस्तृत–448 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ।
- पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं।
- संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएँः–

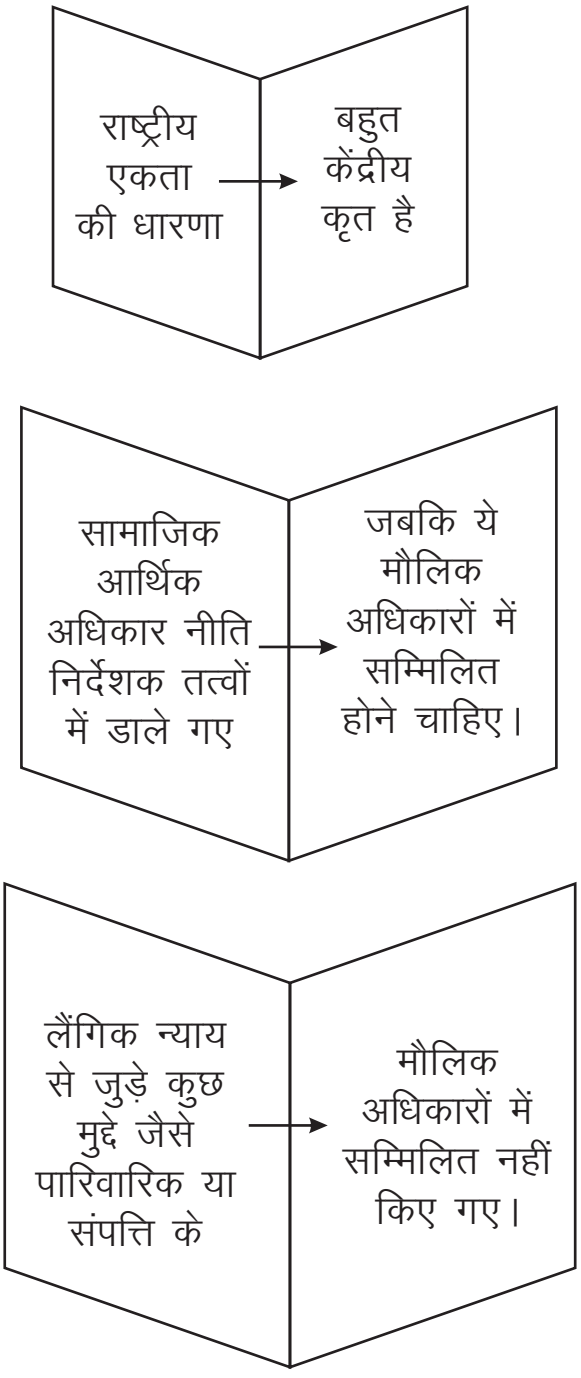

– संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज़ है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते है। संविधान का अंगीकरण 26 नवम्बर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान में जीवंतता है क्योंकि –

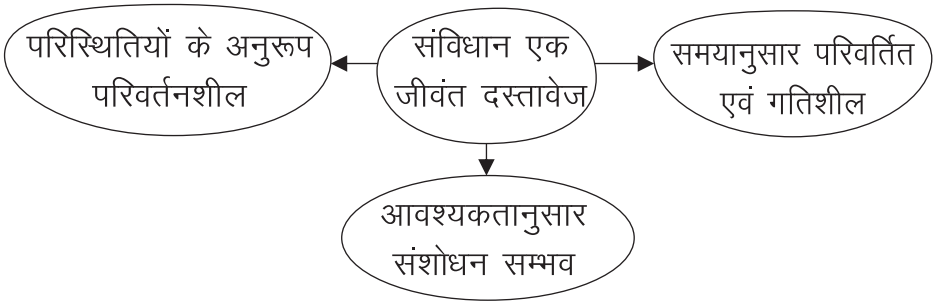

संविधान में संशोधन–

1. संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है।
2. संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है।
3. संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल सरंचना परिवर्तित हो।
4. संशोधनों के मामलें में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण।
5. 1950 में संविधान के लागू होने से अब तक लगभग 105 संशोधन किये जा चुके हैं। इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए है 124 वॉ संविधान संशोधन बिल के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगो को 10% आरक्षाण देने का प्रावधान है।
6. संविधान संशोधन विधेयक के मामलें में राष्ट्रपति को पुर्नविचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है।

संविधान में संशोधन के तरीके

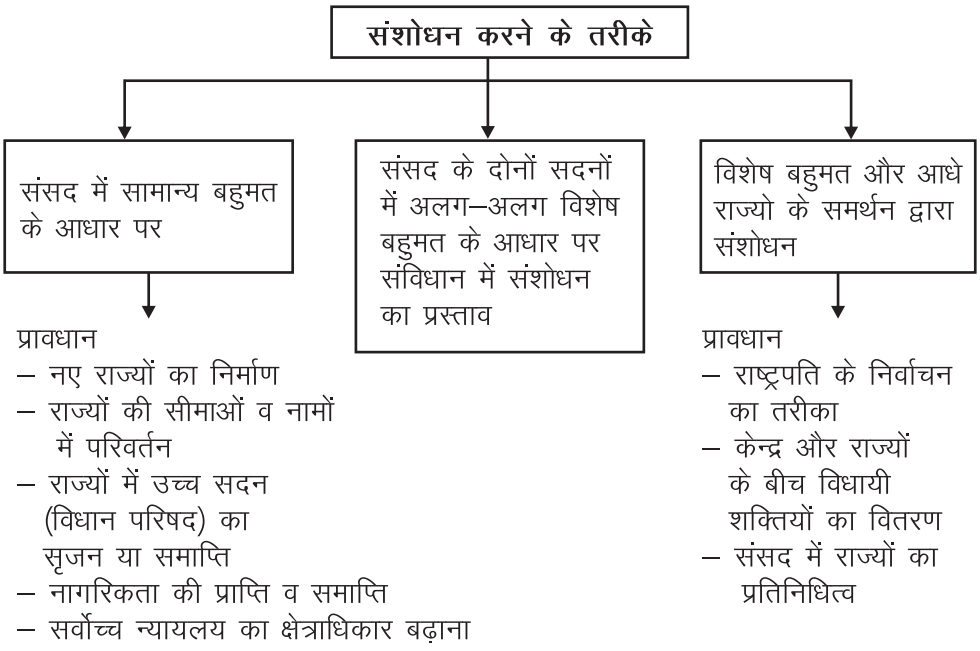

संविधान में इतने संशोधन क्यों?

– हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था पर जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान को सजीव यन्त्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने (लगभग 103) अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकतानुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए।

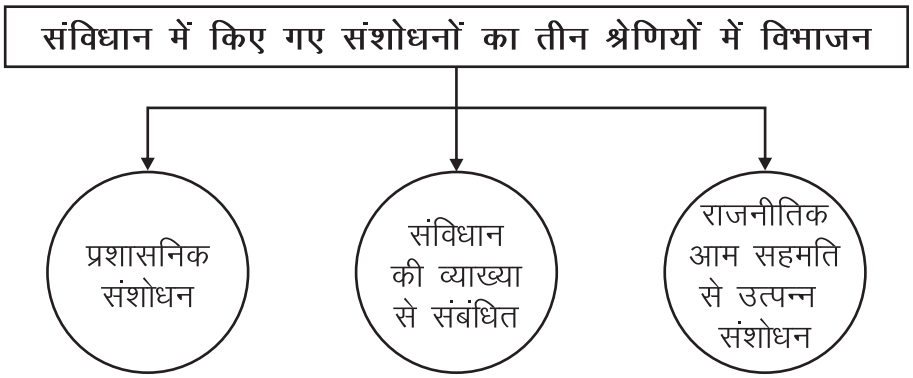

विवादास्पद संशोधन–

– वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो। संशोधन 38वां, 39वां 42वां विवादस्पद संशोधन माने जाते है। ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे।

संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्त–

– यह सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया–

1. संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई।
2. यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर।
3. संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज–

– संविधान एक गतिशील दस्तावेज है।

– भारतीय संविधान का अस्तित्व लगभग 72 वर्षों से है इस बीच यह संविधान अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में इतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है।

– परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रह कर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरता है यहीं उसकी जीवतंता का प्रमाण है।

– समयानुसार परिस्थितियों के बदलनें पर संविधान में परिवर्तन किये जाते है, जो किसी जीवंत दस्तावेज मे ही मुमकिन है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संविधान का कौन–सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद–विवाद के पारित हो गया?
   (क) संसदीय प्रणाली (ख) न्याय पालिका की शक्तियां
   (ग) विकेन्द्रीकृत प्रणाली (घ) सार्वभौमिक मताकिार
2. संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है?
   (क) 4 (ख) 6
   (ग) 7 (घ) 8
3. संविधान सभा का निमार्ण हुआ।
   (क) कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा
   (ख) 1935 में स्थापित प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा
   (ग) माउंटबेटन प्लान द्वारा
   (घ) क्रिप्स मिशन द्वारा।
4. संविधान सभा की प्रकृति थी।
   (क) प्रतिनिधिपरक (ख) स्वेच्छाचारी
   (ग) अधिनायकवादी (घ) इनमें से कोई नही
5. अवशिष्ट शक्तियों के सिद्वान्त को लिया गया हैं?
   (क) अमेरिकी संविधान से (ख) फ्रांस के संविधान से
   (ग) श्रीलंका के संविधान से (घ) कनाडा के संविधान से

अभिकथन एवं तर्क

1. <u>अभिकथन</u> (A) भारत कि संविधान को उधार का थैला कहा जाता है।
   <u>तर्क</u> (R) भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को अन्य देशों के संविधान से लिये गये है।
   (क) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है
   (ख) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है
   (ग) A गलत है और R सही है
   (घ) A सही है लेकिन R गलत है

2. अभिकथन (A) संविधान यह तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

तर्क (R) संविधान कानून एवं नियमों का समुच्च्य है।

(क) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

(ख) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है

(ग) A गलत है और R सही है

(घ) A सही है लेकिन R गलत है

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

(a) डॉक्टर अंबेडकर (b) राजेंद्र प्रसाद

(c) पंडित जवाहरलाल नेहरू (d) सरदार वल्लभभाई पटेल

2. कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं?

(a) जिसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं

(b) जनता के निर्णयों पर आधारित।

(c) जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते

(d) इनमें से कोई नहीं

3. अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए?

(a) 284 सदस्यों ने (b) 288 सदस्यों ने

(c) 290 सदस्यों ने (d) 294 सदस्यों ने

4. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनूसूचियां है?

(a) 8 (b) 10

(c) 11 (d) 12

5. मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया?

(a) ब्रिटेन (b) संयुक्त राज्य अमेरिका

(c) आयरलैंड (d) जापान

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

6. क्रिप्स मिशन ..... वर्ष भारत आया।

7. सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार ..... दिया गया।

8. संविधान सभा का निर्वाचन ..... द्वारा किया गया।

9. संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव ..... ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया।

10. भारतीय संविधान ..... को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया।

निम्नलिखित कथन को सही करके लिखें।

11. समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विकास स्थापित करना संविधान सभा का कार्य है।

12. मौलिक अधिकारों का प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया।

निम्नलिखित कथन बताएं कि सही है या गलत।

13. भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होता है।

14. कानून के शासन का अभिप्राय है सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान है तथा कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा।

15. भारतीय संविधान सभा का निर्माण माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ।

16. भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि परक नहीं थी।

अति संक्षिप्त प्रश्न

17. संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है?

18. क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था?

19. हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है?

20. भारत में राज्य को धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या हैं?

21. किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है।

22. पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है?

23. अनुच्छेद 371 ए क्या है?

24. किसने 19वीं सदी के शुरूआती समय में ही प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध का विरोध किया था?

25. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया था?

26. भारतीय संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे?

27. भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा?

28. फ्रांस के संविधान में भारतीय संविधान में किन प्रावधानों को अंगीकृत किया गया?

29. सुमेलित करें।

ब्रिटेन का संविधान	मूल अधिकार
कनाड़ा का संविधान	कानून का शासन
आयरलैण्ड का संविधान	अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त
अमेरिका का संविधान	नीति निर्देशक तत्व

दो अंकीय प्रश्नः–

1. 'संविधान' क्यों महत्वपूर्ण है?
2. यदि संविधान में मूलभूत कानूनों / नियमों का अभाव होता तो क्या होता?
3. संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए।
4. ''संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है।'' उपर्युक्त कथन को दक्षिण–अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ मे समझाइए।
5. भारतीय संविधान की आलोचनाओं का उल्लेख करें।
6. अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन से उपाय किए गए हैं?
7. भारतीय संविधान की क्या सीमाएं है?
8. संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है?
9. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य लिखो।
10. संविधान के राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते है?
11. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है और उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है?
12. भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई?
13. संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करेगा। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी तय करता है। एक सभ्य समाज के लिए एक संविधान आवश्यक है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धातों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं।

   1. संविधान क्या हैं?

      (A) नियमों का समूह (B) आधारभूत सिद्धांतों का समूह

      (C) दिशानिर्देशों का समूह (D) उपर्युक्त में कोई नहीं

   2. भारतीय संविधान में कानून निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की हैं?

      (A) कार्यपालिका (B) न्यायपालिका

      (C) विधायिका (D) सरकार

   3. कौनसी संस्था लोगों को आधारभूत पहचान प्रदान करती है?

      (A) सरकार (B) कार्यपालिका

      (C) संविधान (D) उपरोक्त सभी

   4. भारतीय संविधान कब बना?

      (A) 24 नवम्बर, 1949 (B) 26 नवम्बर, 1949

      (C) 28 नवम्बर, 1949 (D) 30 नवम्बर, 1949

2. भारतीय संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें सभी वर्गों की सहभागिता हो। वही यह भी आवश्यक है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व नहीं करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। संविधान सभा की असली ताकत ऐसी बातें थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी और इसके सदस्यों ने चर्चा तथा तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। यह बहसें

फ्रांसीसी तथा अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से है।

1. संविधान सभा के कामकाज की शैली किस प्रकार की थी?

   (A) सर्वाधिकारवादी (B) लोकतांत्रिक

   (C) अलगाववादी (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. क्या आप मानते हैं कि संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी?

   (A) सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी

   (B) केवल कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी

   (C) समाज के किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी

   (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार क्या था?

   (A) सैद्धांतिक संगठन (B) संकुचित दृष्टिकोण

   (C) सार्वजनिक विश्वसनीयता (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. संविधान सभा में मतभेदों को किस प्रकार से हल किया गया?

   (A) विवाद द्वारा (B) टकराव द्वारा

   (C) विचार–विमर्श द्वारा (D) उपर्युक्त सभी द्वारा

पाँच अंकीय प्रश्नः –

1. प्रदर्शित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:–

(क) दो मुँह वाला व्यक्ति कौन है? 1

(ख) व्यक्ति के दायीं और बायीं ओर बैठे सदस्य किस–किस विचारधारा के हैं? 2

(ग) दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? 2

छः अंकीय प्रश्नः–

1. एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, सविस्तार समझाइए।
2. भारतीय संविधान सभा की रचना, ब्रिटिश मंत्रीमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार समझाइए।
3. कौन–सी विशेषतायें भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाती है।
4. एक सफल एवं प्रभावी संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का अद्‌भुत समन्वय होता है इस उक्ति को भारतीय संविधान के सन्दर्भ में पुष्ट करें।
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे वर्णित निम्नलिखित शब्दों को सविस्तार समझाइए– (क) न्याय, (ख) स्वतंत्रता, (ग) समानता, (घ) बंधुत्व, (ड.) धर्मनिरपेक्षता, (च) समाजवादी।
6. सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक 'पुष्प–गुच्छ' (BOUQUET) की भांति है जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित हैं।

अथवा

''भारतीय संविधान उधार लिए गये सिद्धान्तों का टोकरा है।'' समझाइए।

उत्तरमाला

1. घ
2. ख
3. ख
4. क
5. घ

अभिकथन एवं तर्क

1. क
2. ख

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. डॉ राजेंद्र प्रसाद
2. जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते।
3. 284 सदस्यों ने
4. 12 अनुसूचियां
5. संयुक्त राज्य अमेरिका
6. मार्च 1942 में
7. कम्युनिस्ट पार्टी को
8. अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
9. जवाहरलाल नेहरू
10. 26 नवम्बर 1949
11. समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विकास स्थापित करना संविधान का कार्य है।
12. मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया।
13. सही
14. गलत
15. गलत
16. गलत
17. संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लोकतांत्रिक आदर्श, मूल्य समाहित किए गए हैं।
18. क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
19. हमारा संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है।
20. धर्म से संबंधित रिवाज जैसे छुआछूत की कुरीतियों को समाप्त करने में, किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे इसके लिए राज्य व धर्म एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।
21. जापान
22. धर्म व राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।

23. अनुच्छेद 371a में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है।

24. राजा राममोहन राय

25. 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।

26. डॉ राजेंद्र प्रसाद

27. भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठक हुई।

28. फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया।

29.

ब्रिटेन का संविधान	कानून का शासन
कनाडा का संविधान	अवशिष्ट शक्तियों का हिस्सा
आयरलैण्ड का संविधान	नीति निर्देशक तत्व
अमेरीका का संविधान	मूल अधिकार

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. इसके अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आपको असुरक्षित महसूस करता। क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। समाज में अराज़कता होती है।

3. (1) मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना, जिससे समाज में एक दूसरें में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने।
   (2) यह तय करना कि समाज में अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

4. (1) दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे–पर्यावरण संरक्षण करना तथा अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना
   (2) इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करें।

5. a) विस्तृत संविधान

   b) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं

   c) उधार मांगा हुआ संविधान।

   d) सबकी नुमाइंदगी नहीं। (कोई दो)

6. a) उचित प्रतिनिधित्व, संसद में सीटों का आरक्षण

   b) सरकारी नौकरी तथा शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण

7. a) राष्ट्रीय एकता की धारणा केन्द्रीकृत

   b) सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाला गया है।

   c) लिंगगत न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे परिवार से जुड़े मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

8. संविधान सिद्धान्तों का समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान न हो और लोगों के अधिकारों का दुरूपयोग न हो।

9. कुछ मौलिक कर्त्तव्य

   a) संविधान का पालन

   b) राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान

   c) देश की एकता व अखण्डता की रक्षा

   d) देश की रक्षा

   e) पर्यावरण को स्वच्छ रखना

   f) सार्वजनिक सम्पति की रक्षा

10. स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, न्याय तथा राष्ट्रीय एकता का अध्ययन ही वास्तव में संविधान के राजनैतिक दर्शन को अभिव्यक्त करता है।

11. भारत के सभी लोगों को जो 18 वर्ष के हो चुके है उन्हें मत देने का अधिकार है।

    सार्वभौम मताधिकार उस समय प्रदान किया गया जब पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

12. 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन तथा 166 बैठकें।

13. 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 11 दिस्मबर 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

   सदस्य संख्या 389, (292+4+93)। 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैंठकें–166।

2. (i) प्रभुसत्ता की कमी।
   (ii) प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण।
   (iii) देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया।
   (iv) संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया।

3. (i) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण– संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा।
   (ii) संवैधानिक निकायों को शक्तिशाली बनाना, जैस–स्वतंत्र चुनाव आयोग।

4. (i) एक सफल संविधान वही हैं जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय) को तरजीह दी जायें।
   (ii) जनता के प्रति जवाबदेही संविधान की सफलता का आधार।
   (iii) सामाजिक समस्याओं का समाधान।
   (iv) समुचित सन्तुलन एवं समन्वय।

5. (i) प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए।
   (ii) बहुसंख्यको से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
   (iii) समान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
   (iv) छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना।
   (v) समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

6. (i) संविधान सभा द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया।
   (ii) विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया।

7. **प्रतिनिधिपरकः**

* सभी समुदायों की भागीदारी
* विचार–विमर्श एवं सहमति पर आधारित
* अप्रत्यक्ष निर्वाचन

8. a) प्रभुत्व संपन्न
   b) समाजवादी
   c) धर्मनिरपेक्ष
   d) लोकतंत्र
   e) गणराज्य
   f) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
   g) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, धर्म)
   h) समानता

9. **भारतीय धर्मनिरपेक्षता**– यह पूरी तरह से राज्य और धर्म का पारस्परिक निषेध नहीं मानती। धर्म पर राज्य का प्रभुत्व नहीं है परंतु धर्म राज्य काज में और राज्य धर्म काज में हस्तक्षेप करेगा अगर कोई धर्म व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाता है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

   पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता– धर्म व्यक्ति का निजी मामला। धर्म व राज्य दोनों एक दूसरें के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे।

10. ऐसे अधिकार जो जीवन के लिए मूल या आवश्यक हो ओर जिन्हें संविधान के द्वारा दिया गया हो।

    महत्व– 1) लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार
    2) सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध
    3) सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा
    4) संविधान के आधार स्तंभ
    5) अल्पसंख्यको में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ता है।

अवतरण आधारित प्रश्नों के उत्तर (चार अंकीय)

1. 1. संविधान नियमों तथा मूल्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है।
2. संविधान में कानून निर्माण की शक्ति विधायिका को प्रदान की गई है।
3. संविधान के माध्यम से समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है।
4. भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना।

2. 1. संविधान सभा के कामकाज की शैली लोकतांत्रिक थी।

2. संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी क्योंकि उसमें समुदायों वर्गों तथा विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व शामिल था।

3. संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार यह था कि सार्वजनिक हित का काम कर रही थी तथा पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर संविधान सभा ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया।

4. संविधान सभा में मतभेदों को आपसी विचार–विमर्श के द्वारा हल किया गया।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. कार्टून – (क) पं. जवाहर लाल नेहरू

(ख) पश्चिमी विचारधारा के लोग
पूर्वी अर्थात् भारतीय संस्कृति के समर्थक

(ग) दोनों में तालमेल स्थापित किया।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. सभ्य समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य संविधान ही प्रदान करता है।

संविधान ही सदस्यों के बीच सहयोग एवं तालमेल स्थापित करता है।

2. (i) ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति–'कैबिनेट मिशन'।

(ii) सदस्यों का चयन – ब्रिटिश प्रान्तों से (292) + देशी रियासतों से (93) + चीफ कमिशनरों से (4) = 389 सदस्य।

(iii) प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों–मुसलमान, सिख और सामान्य में बंटवारा।

(iv) प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना।

(v) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श इसे तय किया गया आदि।

3. संविधान की विशेषताएँ : जो भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाते हैं–

(i) जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, लिखित एक सम्पूर्ण संविधान।

(ii) यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है।

(iii) नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्त्तव्यों की याद दिलाता है।

(iv) स्वतंत्र न्यायपालिका है।

(v) संसदीय शासन व्यवस्था।

(vi) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि।

5. भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय अद्‌भुत है–सैद्धांतिक तौर पर भारत का संविधान कठोर है– अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। (विशेष बहुमत)

– लचीलापन बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास कर के संशोधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के अद्‌भुत समन्वय ने भारतीय संविधान को प्रभावी एवं सफल दोनों बनाया है।

6. न्याय–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना।

स्वतंत्रता–अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भक्ति की स्वतंत्रता।

समानता – सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त या भेदभावों से मुक्ति।

बंधुत्व– देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना।

धर्म निरपेक्षता–सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आजादी।

समाजवादी– सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोकहित कारी कार्य हो। समाज सर्वोपरी।

7. भारतीय संविधान एक 'पुष्प गुच्छ' इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धान्त रूपी फूल शामिल किए गये है। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है।

अथवा

सिद्धान्तों को टोकरे के रूप में देखे तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती है उसी भाँति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में – इंग्लैण्ड अमेरिका, आयरलैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि का उदाहरण देते हुए स्वयं को वर्णन करेगें। जैसे देशों के संविधानिक सिद्धान्तों को लिया गया है जिसे हम उधार ली गई वस्तुओं के रूप में देखते हैं।

1. आवश्यकताओं के अनुरूप
2. परिस्थितियों के अनुरूप
3. आशाओं एवं आक्षांकाओं के अनुरूप

अध्याय 2

चुनाव और प्रतिनिधित्व

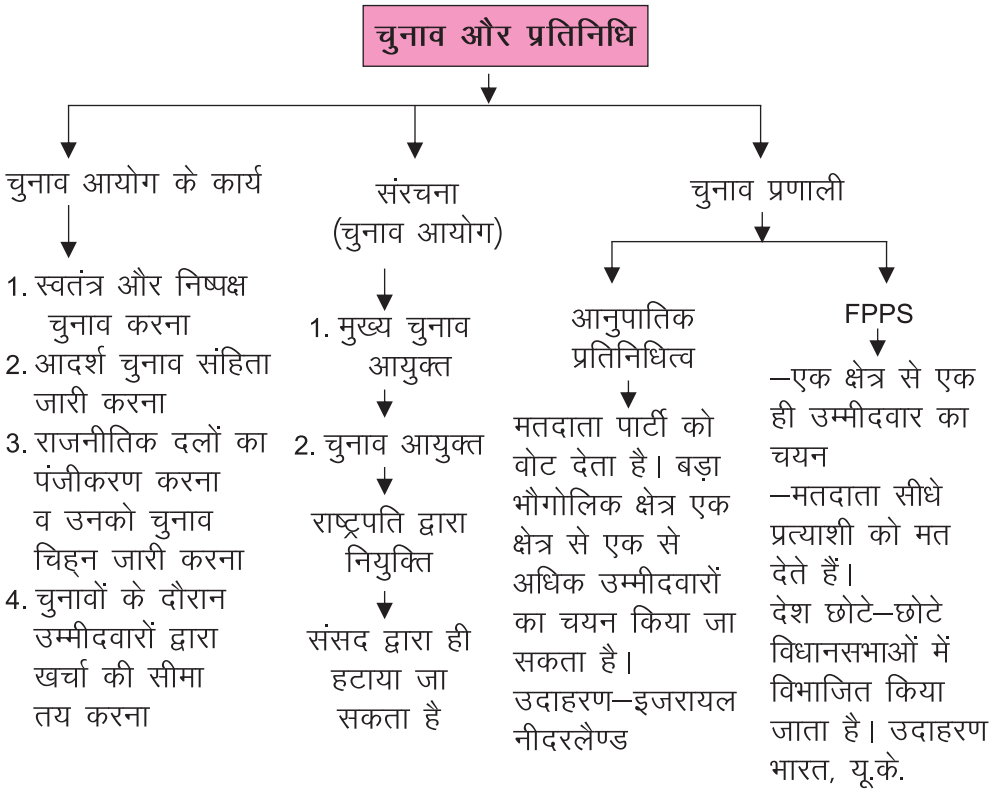

चुनाव और प्रतिनिधित्व

मुख्य बिन्दुः

– लोकतंत्र के प्रकार
– चुनाव और प्रतिनिधित्व
– चुनाव आयोग
– समानुपातिक प्रतिनिधित्व
– निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण
– चुनाव सुधार

प्रतिनिधि → चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुन कर संसद या विधानसभा में भेजती हैं उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं।

हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? विशाल जनसंख्या व बड़े क्षेत्रफल के कारण कानून बनाते समय या निर्णय लेते समय सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते इसलिए लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

लोकतंत्र के प्रकार

- प्रत्यक्ष लोकतंत्रः नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं (हाथ उठाकर) उदाहरणः प्राचीन चूनान, ग्राम सभा
- अप्रत्यक्ष लोकतंत्रः जनता अपने प्रतिनिधि भेजकर सरकार की कार्यवाहियों में भाग लेती हैं जैसेः भारत, इंग्लैंड

चुनाव → जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं।

चुनाव और लोकतंत्रः चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं चुनाव के बिना लोकतंत्र अधुरा हैं और लोकतंत्र का चुनावों के बिना कोई महत्व नहीं है।

भारत में चुनाव व्यवस्था

भारत के संविधान में चुनाव संचालन की व्यवस्था का वर्णन किया गया हैं इसके लिए प्राधिकार (चुनाव आयोग) का गठन और नियमों का वर्णन भी किया गया हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव लड़के की योग्यता, मतदाता की योग्यता व मतगणना की प्रक्रिया का वर्णन किया गया हैं:

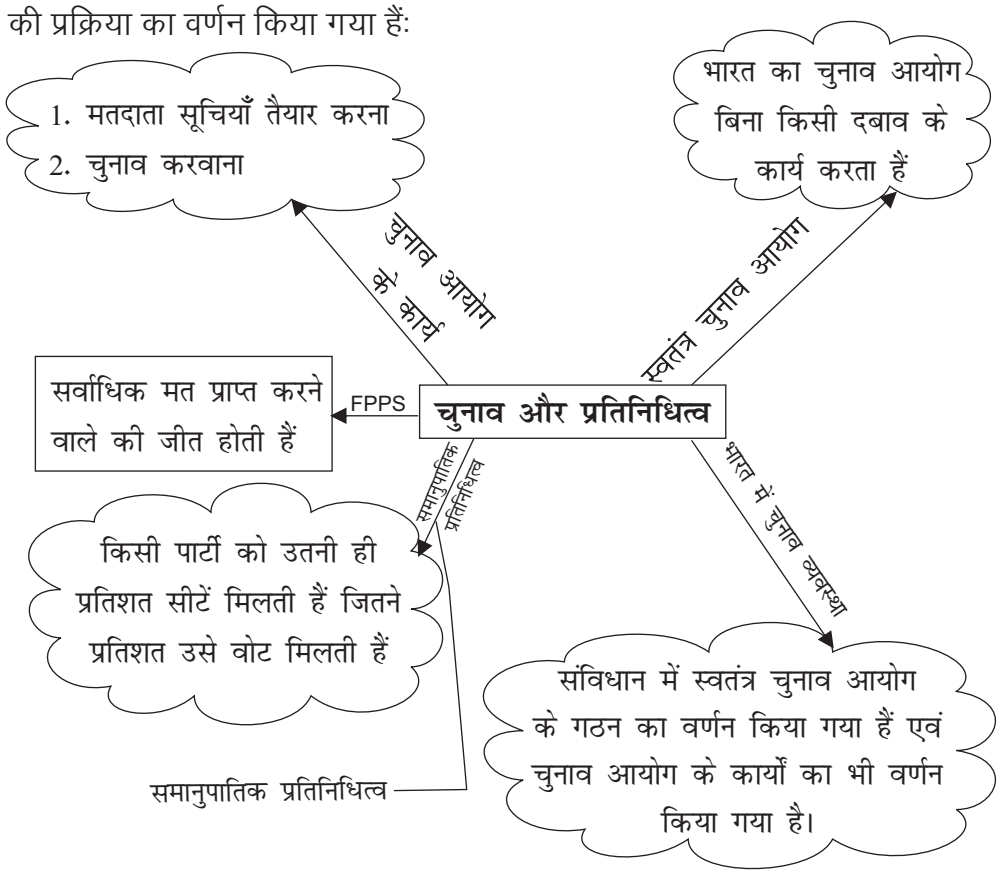

चुनाव आयोग → भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा, जिसमें 3 सदस्य (1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त) होंगे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।

सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली → यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई हैं इसमें पूरे देश को छोटी भोगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी विजेता होता हैं इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी विजयी होता है।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वः

प्रत्येक पार्टी चुनावों में पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती हैं और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती हैं जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता हैं चुनावों की इस व्यवस्था में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलती हैं इस प्रणाली में मतदाता प्रत्याशी को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देता हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार की होती हैं जैसे–इजरायल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता हैं और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दी जाती हैं दूसरा प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में पूरे देश को बहु–सदस्ययी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है।

भारत में 'सर्वाधिक वोट' से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई?

1. यह प्रणाली सरल हैं
2. चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता हैं
3. यह प्रणाली भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए उपयुक्त हैं
4. मतदाता उम्मीदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं यह अवसर अन्य प्रणाली में नहीं मिलता

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण

भारत के संविधान द्वारा संसद या राज्य विधानसभा में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं इस व्यवस्था में सभी वर्गों के मतदाता वोट डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी सामाजिक वर्ग का होगा जिसके आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर 2030 तक कर दिया हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता हैं जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं।

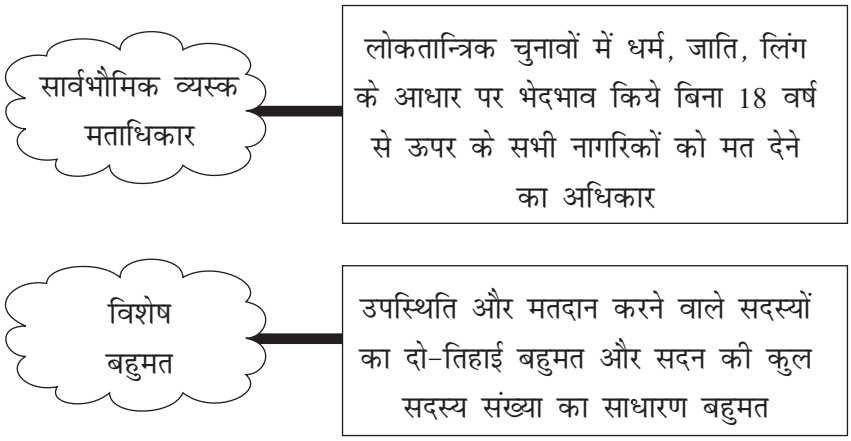

चुनाव सुधारः

चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी भी आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती हर प्रणाली में कुछ–न–कुछ कमियां अवश्य होती हैं लोकतान्त्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाने के प्रयास लगातार करने पड़ते हैं इसे ही चुनाव सुधार कहते हैं, जैसे–भारत में आपराधिक भूमिका वाले लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना।

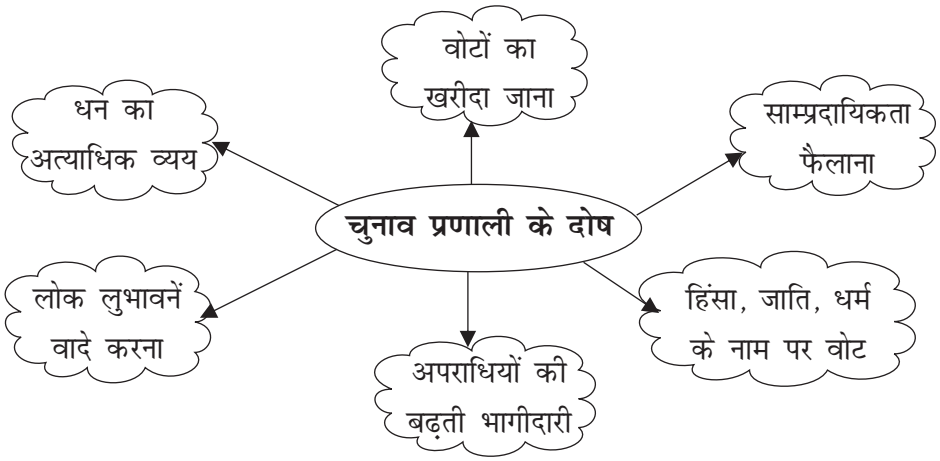

एक अंकीय प्रश्न–

1. भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू होता हैं?

(अ) लोकसभा चुनाव (बी) राज्यसभा चुनाव

(सी) राज्य विधानसभाएं (डी) स्थानीय निकाय चुनाव

2. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता हैं?

(i) प्रधान मंत्री (ii) लोकसभा

(iii) राज्य सभा (iv) राष्ट्रपति

3. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्रित करता हैं?

(i) सुप्रीम कोर्ट (ii) उच्च न्यायालय

(iii) भारत का चुनाव आयोग (iv) संसद

4. वोट का अधिकार ..... है?

(i) कानूनी अधिकार (ii) मौलिक अधिकार

(iii) संवैधानिक अधिकार (iv) वैधानिक अधिकार

5. चुनाव विवादों को कहाँ चुनौती दी जा सकती हैं?

(i) संसद (ii) चुनाव आयोग

(iii) राष्ट्रपति (iv) उच्च न्यायालय

अभिकथन और कारण प्रश्न

1. **अभिकथन (A):** चुनाव आयुक्त बिना किसी दबाव के काम करता है

कारण (R): चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है

(ए) ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है।

(बी) ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।

(सी) ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है।

(डी) ए असत्य हैं, लेकिन आर सत्य है।

2. **अभिकथन (ए):** भारत के लोग सीधे अपना प्रधान मंत्री चुनते हैं

कारण (R): भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

(ए) ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है।

(बी) ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं हैं।

(सी) ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है।

(डी) ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है।

एक अंकीय प्रश्न–

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय हैं?

2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य हैं?
3. निर्वाचन किसे कहते हैं?
4. मतदाता किसे कहते हैं?
5. मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता हैं?

खाली स्थान भरो–

6. स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना ..... की जिम्मेदारी हैं।
7. जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं उसे ..... कहते हैं।
8. 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जब मतदान करता हैं तो उसे ..... कहते हैं।
9. लोकसभा या राज्य विधान सभा लड़ने की न्यूनतम आयु ..... हैं।
10. अनुच्छेद 324(1) के द्वारा भारत में ..... की स्थापना कि गई है।

सही या गलत वाक्य की पहचान कीजिए–

11. समानुपातिक प्रणाली को ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं।
12. प्रथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था में जिस समुदाय या प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता हैं उसे समुदाय के लोग मत देते हैं।
13. चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा परिसीमन आयोग तय करता है।
14. भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता हैं।
15. भारत में राज्य सभा चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई हैं।

प्रश्न संख्या 16–20 बहुविकल्पीय हैं

16. भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हैं

    (क) विधान सभा (ख) संसद (ग) ग्राम सभा (घ) नगर निगम
17. समानुपातिक प्रतिनिधित्व निम्न में से किस देश द्वारा अपनाई हुई हैं

    (क) भारत (ख) इंग्लैंड (ग) अमेरिका (घ) इजरायल
18. लोकसभा में कुल कितनी सटें आरक्षित हैं?

    (क) 131 (ख) 84 (ग) 47 (घ) 125

19. मत देने की उम्र 21 से घटा कर 18 वर्ष कब की गई?

(क) 1984 (ख) 1989 (ग) 1991 (घ) 1995

20 शब्दों में दीजिए। (दो अंकीय प्रश्न)

1. भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे?
2. विशेष बहुमत का क्या अर्थ हैं?
3. राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न कौन आवंटित करता है?
4. राज्य सभा चुनावों में कौन–सी चुनाव प्रणाली अपनाई जाती हैं?
5. भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
6. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अन्तर लिखिए।
7. 'फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट' प्रणाली का क्या अर्थ है?
8. 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' किसे कहते है?
9. गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है?
10. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
11. किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के कौन से दो तत्व है?
12. परिसीमन आयोग से आप क्या समझते है? इसका गठन कौन करता है?
13. भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखे?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' और 'समानुपातिक प्रतिनिधत्व चुनाव व्यवस्था मे ंचार अन्तर लिखिए।
2. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के चार महत्व लिखिए।
3. भारत के निर्वाचन आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
4. प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को समझाइए।
5. लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन–कौन सी योग्यताएं तय की गई है?

6. 'लोकतंत्र में चुनाव का महत्व' विषय पर टिप्पणी लिखिए।

7. पृथक निर्वाचन मण्डल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

8. निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक देखो तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

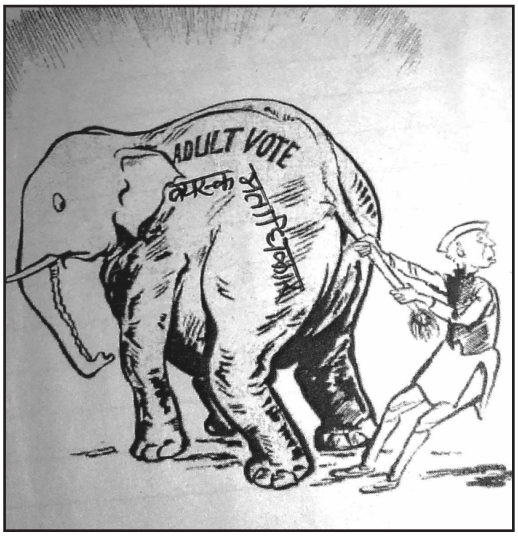

8.1 कार्टून में हाथी किस प्रकार की समस्या की ओर संकेत करता नजर आ रहा है?

(A) विशाल मतदाता (B) विशाल हाथी

(C) विशाल प्रतिनिधि (D) कुछ नहीं

8.2 हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है?

(A) अनियंत्रित भीड़ (B) अनियंत्रित व्यक्ति

(C) अनियंत्रित हाथी (D) कुछ नहीं

8.3 हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम लिखिए।

(A) महात्मा गाँधी (B) पंडित नेहरू

(C) सरदार पटेल (D) नरेन्द्र मोदी

छः अंकीय प्रश्न–

1. भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई छः सुझाव सुझाइए।

2. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए, उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

3. भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए?

4. भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें?

5. ''चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्कें के दो पहलू है।'' इस कथन को समझाते हुए चुनावों का लोकतंत्र में महत्व क्या है? समझाइए।

चार अंकीय प्रश्न–

आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी व्यस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है इसी को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों के नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला–

1. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है?
   (A) 18 वर्ष से उपर सभी को मताधिकार
   (B) 20 वर्ष से उपर सभी को मताधिकार
   (C) 25 वर्ष के उपर सभी को मताधिकार
   (D) 30 वर्ष से उपर सभी को मताधिकार
2. भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है?
   (A) 19 वर्ष (B) 22 वर्ष
   (C) 21 वर्ष (D) 18 वर्ष
3. भारत में सार्वभौमिक व्यष्क मताधिकार कब से लागू हुआ?
   (A) 1950 से (B) 1935 से
   (C) 1960 से (D) 2000 से
4. भारत में आम चुनाव कितने वर्षो में होता है?
   (A) 6 वर्ष में (B) 4 वर्ष में
   (C) 5 वर्ष में (D) 10 वर्ष में

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्न के उत्तरः–

1. (ii) राज्य सभा चुनाव
2. (iv) राष्ट्रपति
3. (iii) भारत का चुनाव आयोग
4. (iii) संविधान अधिकार
5. (iv) उच्च न्यायालय

अभिकथन और कारण आधारित उत्तर

1. A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

2. A गलत है, लेकिन R सत्य है।

एक अंकीय प्रश्न के उत्तरः—

1. ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार के फैसलों में सीधे भाग लेते हैं।
2. ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं तथा वे जनता के नाम पर फैसले लेते हैं।
3. जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं।
4. 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो चुनावों में मत देते हैं।
5. निर्वाचन आयोग
6. निर्वाचन आयोग
7. आम चुनाव
8. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार
9. 25
10. निर्वाचन आयोग
11. गलत
12. सही
13. सही
14. गलत
15. सही
16. ग्राम सभा
17. इजरायल
18. 131
19. 1989
20. उम्र

दो अंकीय प्रश्न के उत्तरः—

1. सुकुमार सेन

2. कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत

3. चुनाव आयोग

4. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

5. श्री राजीव कुमार

6. (i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि भाग लेते है।

   (ii) प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है जबकि अप्रत्यक्ष में जन प्रतिनिधि अपने आपको शासन समझते है।

7. इस प्रणाली का अर्थ यह है कि जो प्रत्याशी चुनावी दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वहीं विजयी होता है।

8. इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जैसे–इज़राइल व नीदरलैंड। तथा कहीं पर पूरे देश को बहु–सदस्ययी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है।

9. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है । इसमें मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है।

10. संविधान में व्यवस्था कि गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जन प्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय–समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए सीटें आरक्षित कर देता है उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।

11. (i) स्वतंत्र चुनाव (ii) निष्पक्ष / पारदर्शी चुनाव

12. भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है उसे परिसीमन आयोग कहते है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

13. उत्तर मुख्य बिन्दुओं में से देखें।

चार अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः–

1. **अन्तर–**

सार्वधिक वोट पाने वाले की जीत	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
(i) देश को छोटे–छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते है।	(i) पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है
(ii) हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है।	(ii) एक से अधिक चुने जाते है।
(iii) मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।	(iii) मतदाता पार्टी को मत देता है।
(iv) प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते है।	(iv) इसमें मतदाता पार्टी को वोट देता है इसलिए प्रत्याशी को नही जानता।

2. (i) सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धान्त लागू होता है।
   (ii) यह लोकतांत्रिक सिद्धान्त के अनुरूप है।
   (iii) व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है।
   (iv) इससे राजनीतिक जागरूकता आती है।

3. (i) मतदाता सूची तैयार करना।
   (ii) चुनाव की तिथि तय करना।
   (iii) चुनाव कराना, निरीक्षण करना।
   (iv) चुनाव परिणाम जारी करना।

4. सम्पूर्ण नगर राज्य के लोग एक खुले स्थान पर एकत्रित होते तथा अपने प्रतिनिधि को हाथ उठाकर चुनते तथा रोजमर्रा के सरकारी फैसला हाथ उठवाकर प्रत्यक्ष रूप से जनता से स्वीकृति प्राप्त करते थे। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते है।

5. (i) भारत का नागरिक हो।
   (ii) आयु 25 वर्ष हो।
   (iii) लाभ के पद पर ना हो।

(iv) पागल या दिवालिया ना हो।

(v) अपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो।

6. लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व है– चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज विश्व में सौ से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।

7. पृथक निर्वाचन मण्डल में–एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते है।

आरक्षित चुनाव क्षेत्र–में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है।

पांच अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः–

1. (क) प्रथम आम चुनाव में अनुभवहीन विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करके सफल मतदान करवाना।

(ख) अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास।

(ग) पं. जवाहर लाल नेहरू।

(घ) 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देना।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः–

1. चुनाव सुधार –

(i) सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएं।

(ii) ससंदीय एवं विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का चुनाव।

(iii) चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण।

(iv) फौजदारी मुकद्दमें वाले की उम्मीदवारी रद्द।

(v) चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो।

(vi) राजनीति दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो।

2. मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति–राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल–छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वेतन–उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के समान होता है।

कार्य– (1) मतदाता सूची तैयार करना, (2) चुनाव कार्यक्रम तय करना, (3) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना (4) राष्ट्रीय एक राज्यपार्टी के रूप में दलों/पार्टीयों का मान्यता देना। (5) चुनावों का निरीक्षण करना। (6) राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना।

3. चुनाव प्रक्रिया– (i) चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना (ii) चुनावों की तिथि, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। (चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केन्द्रों की स्थापना)

4. चुनाव प्रणाली की विशेषताएं–

भारत में 'सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली' को अपना रखा है इसकी विशेषताएं है–

(i) यह सरल है।

(ii) इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाब देह होते है।

(iii) मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है।

(iv) यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धान्त पर आधारित है।

(v) इसमें खर्च कम आता है।

(vi) इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

5. लोकतंत्र में चुनाव का महत्व–

(i) प्रतिनिधि चुनाव जीत कर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते है।

(ii) चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा।

(iii) इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है।

(vi) लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है।

(v) नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही है।

(vi) उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

चार अंकीय उत्तरः–

1. सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार।
2. 18 वर्ष
3. आजादी के पश्चात से ही
4. पांच वर्ष के अंतराल पर

अध्याय 3

विधायिका

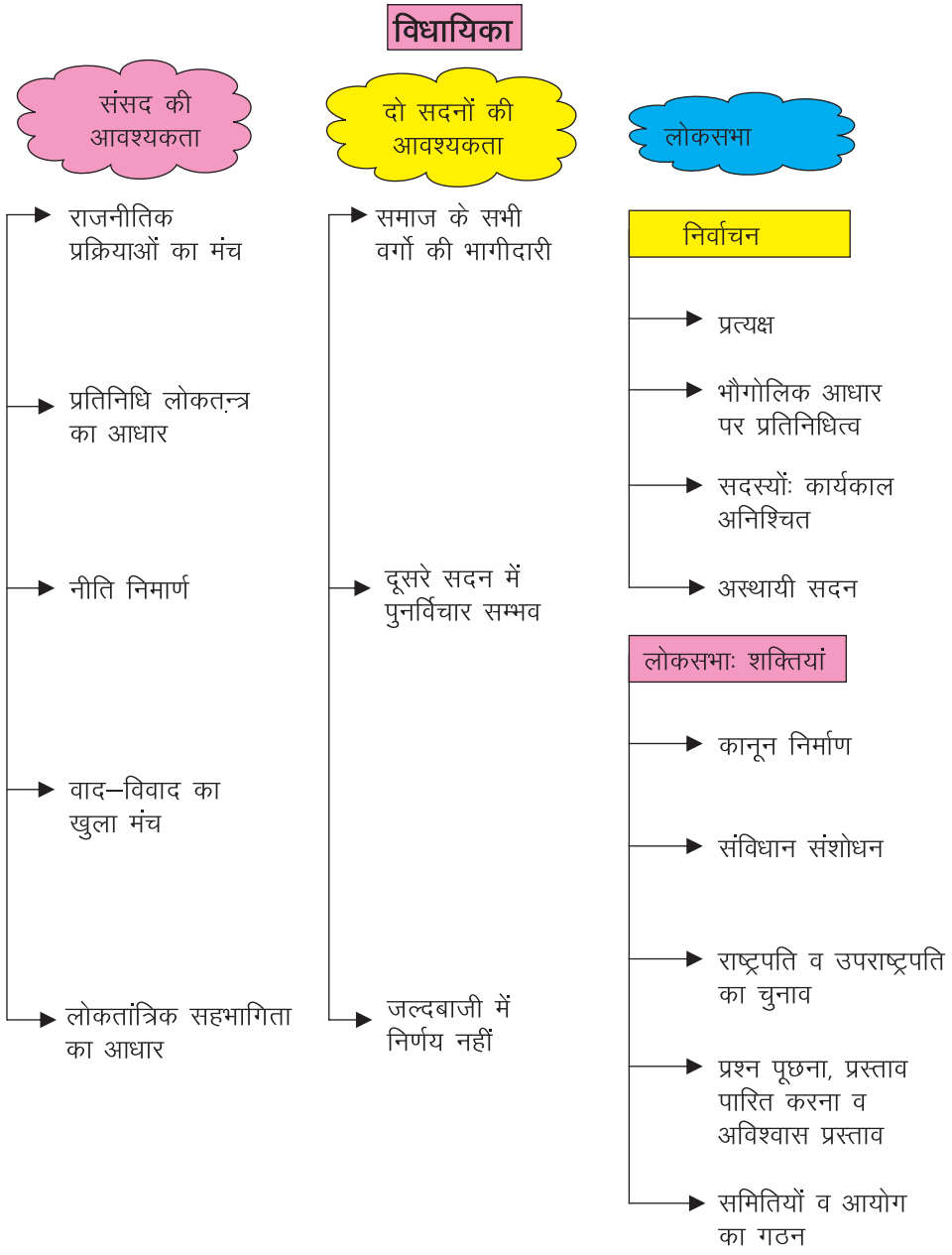
विधायिका
संसद की आवश्यकता
दो सदनों की आवश्यकता
लोकसभा
राजनीतिक प्रक्रियाओं का मंच
प्रतिनिधि लोकतन्त्र का आधार
नीति निमार्ण
वाद–विवाद का खुला मंच
लोकतांत्रिक सहभागिता का आधार
समाज के सभी वर्गो की भागीदारी
दूसरे सदन में पुनर्विचार सम्भव
जल्दबाजी में निर्णय नहीं
निर्वाचन
प्रत्यक्ष
भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधित्व
सदस्यों: कार्यकाल अनिश्चित
अस्थायी सदन
लोकसभा: शक्तियां
कानून निर्माण
संविधान संशोधन
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव
प्रश्न पूछना, प्रस्ताव पारित करना व अविश्वास प्रस्ताव
समितियों व आयोग का गठन

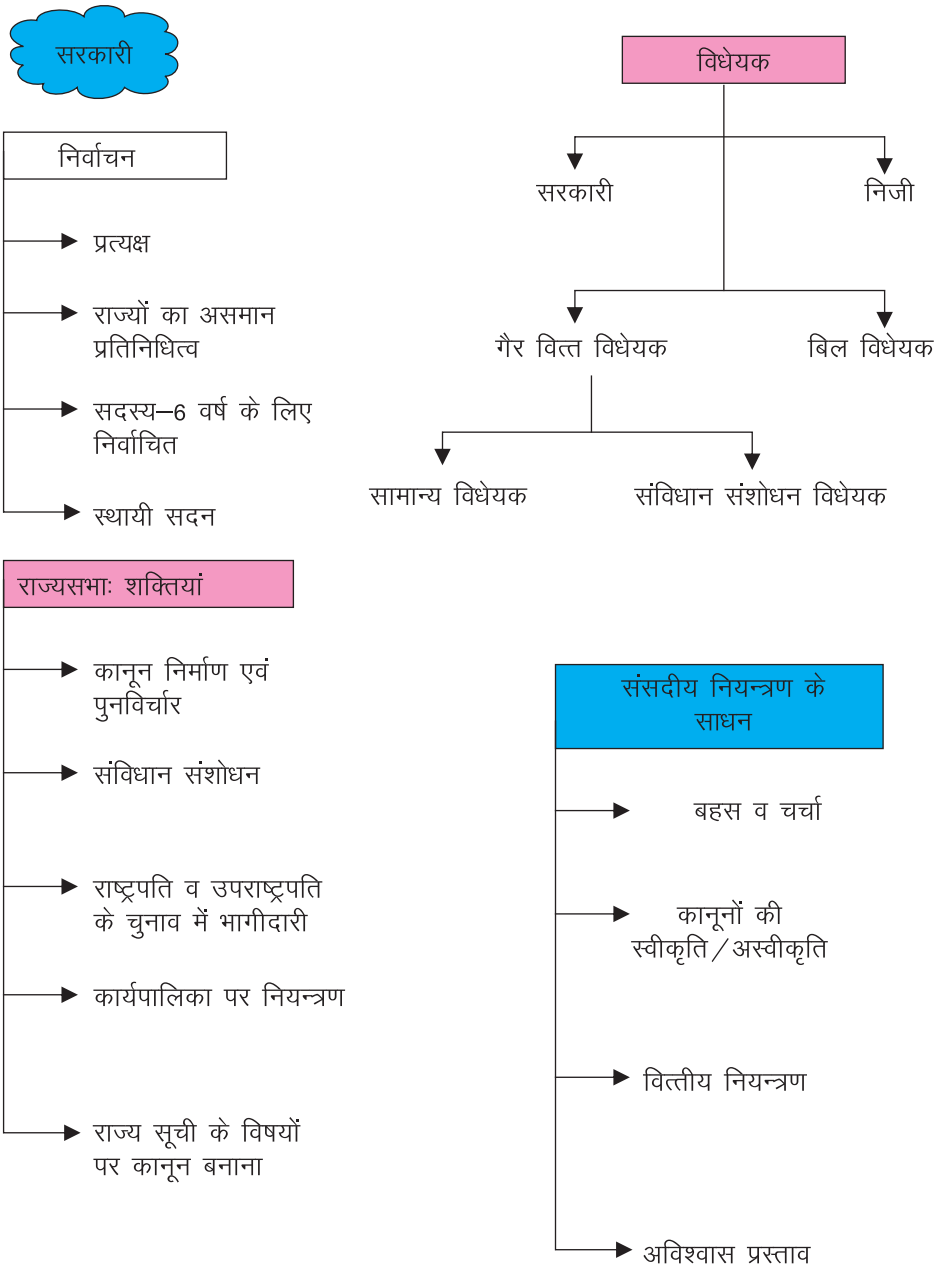
सरकारी
निर्वाचन
प्रत्यक्ष
राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व
सदस्य–6 वर्ष के लिए निर्वाचित
स्थायी सदन
विधेयक
सरकारी
निजी
गैर वित्त विधेयक
बिल विधेयक
सामान्य विधेयक
संविधान संशोधन विधेयक
राज्यसभाः शक्तियां
कानून निर्माण एवं पुनर्विचार
संविधान संशोधन
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी
कार्यपालिका पर नियन्त्रण
राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना
संसदीय नियन्त्रण के साधन
बहस व चर्चा
कानूनों की स्वीकृति/अस्वीकृति
वित्तीय नियन्त्रण
अविश्वास प्रस्ताव

अध्याय के मुख्य बिन्दुः विधायिका की आवश्यकता, संसद के दोनों सदन, संसद के कार्य, कानून निर्माण, संसद की समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण।

विधायिकाः–

– संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, यह राष्ट्रपति और दो सदन, जो राज्य परिषद (राज्य सभा) और जनता का सदन (लोक सभा) कहलाते है, से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं।

– लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित हैं।

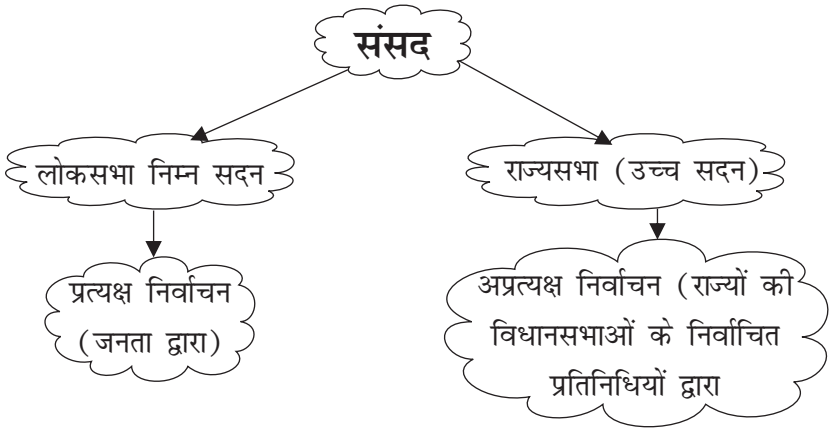

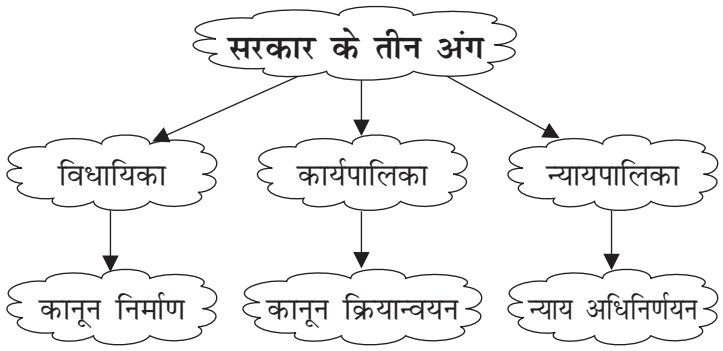

– विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधी बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन्त बनाए रखती है।

– संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में दो सदनों के साथ–साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता हैं

– द्वि–सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गो और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो।

– भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा हैं इसके अधिकतम 250 सदस्य होते है जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 स्दस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिये जाते है।

– अमेरिका के द्वितीय सदन (सीनेट) में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

– राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) 30 वर्ष की आयु का हो।

इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।

– 1951 के जन–प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोक सभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है–

वित्तीय शक्तियांः–

(1) वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है।

(2) संविधान–संशोधन संबंधी शक्तियां।

(3) प्रशासनिक शक्तियां– मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते है।

(4) अन्य शक्तियाँः चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा न्यायधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है।

– लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमे अधिकतम 550 सदस्य हो सकते है। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य है और दो सदस्य

(एंग्लो इंडियन) को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है।

– भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है।

संसद के प्रमुख कार्यः–

(1) कानून बनाना।
(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण।
(3) वित्तीय कार्यः बजट पारित करना
(4) संविधान संशोधन।
(5) निर्वाचन संबंधी कार्य।
(6) न्यायिक कार्य।
(7) प्रतिनिधित्व।
(8) बहस का मंच।
(9) विदेश नीति पर नियन्त्रण
(10) विचारशील कार्य

– लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है।

– मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

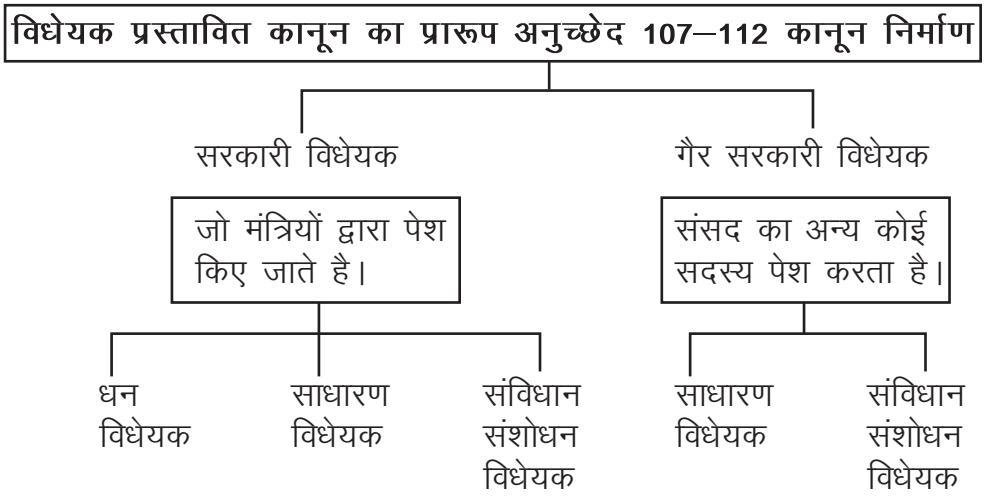

प्रक्रियाः–

(1) प्रथम वाचन।

(2) द्वितीय वाचन (समिति स्तर)

(3) समिति की रिपार्ट पर चर्चा

(4) तृतीय वाचन।

(5) दूसरे सदन में प्रक्रिया।

(6) राष्ट्रपति की स्वीकृति।

संसदीय नियंत्रण के साधनः–

(1) बहस और चर्चा– प्रश्न काल, शून्य काल, स्थगन प्रस्ताव।

(2) कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति।

(3) वित्तीय नियंत्रण।

(4) अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव।

संसदीय समितियांः–

– विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है

वित्तीय समितियांः–

(1) **लोक लेखा समिति**– भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं।

(2) **प्राकलन समिति**– खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है।

(3) **लोक उपक्रम**– सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहे है या नहीं।

विभागीय स्थायी समितियांः–

(1) नियमन समिति।

(2) विशेषाधिकार समिति।

(3) कार्य–मंत्रणा समिति।

(4) आश्वासन समिति।

तदर्थ समितियांः–

– विशिष्ट विषयों की जांच–पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय–समय पर गठन किया जाता है। बौफोर्स समझौतों से संबंधित संयुक्त

समिति। समितियों द्वारा दिये गए सुझावो को संसद शायद ही नामंजूर करती है।

संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है–

(1) संसद का सार्थक व अनुशासित होना।

(2) सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है।

(3) दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52 वां संशोधन किया गया। 91 वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया।

यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद–सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करें अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें उसे 'दलबदल' कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है।

(4) भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य 8 केंद्र शासित इकाईयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया हैं

(5) भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्वि–सदनीय व्यवस्था है।

(6) राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है–

(i) निम्न सदन को विधानसभा।

(ii) उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है।

द्विसदनीय राज्यः–

– उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश, छः राज्य बाकी सभी राज्य एक सदनीय है।

(1) विधानसभा की शक्तियां–

(i) विधायी कार्यशक्ति।

(ii) वित्तीय शक्तियां।

(iii) कार्यपालिका शक्तियां।

(iv) चुनाव संबंधी कार्य।

(v) संविधान संशोधन सबंधी शक्तियां।

(2) विधान परिषद की शक्तियां–

(i) विधायी शक्तियां।

(ii) वित्तीय शक्तियां।

(iii) कार्यपालिका शक्तियां।

दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(क) प्रधानमन्त्री (ख) मुख्यमन्त्री

(ग) राष्ट्रपति (घ) लोकसभा

2. राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य काल होता हैः

(क) निश्चित

(ख) 4 वर्ष

(ग) लोकसभा में बहुमत रहने तक

(घ) कोई नहीं।

3. भारतीय संसद का ऊपरी सदन हैः

(क) लोकसभा

(ख) राज्य सभा

(ग) लोकसभा व राज्यसभा दोनों

(घ) कोई नहीं

4. वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है।

(क) 14 दिन (ख) 18 दिन

(ग) 20 दिन (घ) कोई नहीं

5. अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम हैं:

(क) प्रतिनिधि सभा (ख) सीनेट

(ग) काग्रेस (घ) राज्यसभा

अभिकथन एवं तर्क :

1. अभिकथनः– भारत में अधिक जनंसख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

तर्क : भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों का आवंटन किया गया है।

2. अभिकथनः संसद की समितियों को लघु विधायिकाये कहा जाता है।

तर्कः संसदीय समितियां विधेयक पर जीवंत तथा तर्कपूर्वक विचार–विमर्श करती है।

(a) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

(b) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A गलत है और R सही है

(d) A सही है लेकिन R गलत है

2. अभिकथनः संसद की समितियों को लघु विधायिकायें कहा जाता है।

तर्कः संसदीय समितियां विधेयक पर जीवंत तथा तर्कपूर्वक विचार–विमर्श करती है।

(a) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

(b) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A गलत है और R सही है

(d) A सही है लेकिन R गलत है

एक अंकीय प्रश्न

1. राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है।
   (a) 30 वर्ष
   (b) 35 वर्ष
   (c) 40 वर्ष
   (d) 45 वर्ष
2. कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार है।
   (a) राष्ट्रपति
   (b) लोकसभा अध्यक्ष
   (c) प्रधानमंत्री
   (d) उपराष्ट्रपति
3. भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदाई है?
   (a) राष्ट्रपति
   (b) लोकसभा
   (c) राज्यसभा
   (d) लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों
4. राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
   (a) प्रधानमंत्री
   (b) राष्ट्रपति
   (c) उपराष्ट्रपति
   (d) मुख्यमंत्री
5. राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है।
   (a) कला, साहित्य खेल एवं विज्ञान
   (b) कला, साहित्य, रंगमंच एवं सामाजिक सेवा
   (c) कला, साहित्य, राजनीति एवं समाज सेवा
   (d) कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा

6. विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है।

(a) 10 दिन

(b) 14 दिन

(c) 3 महीने

(d) 6 महीने

7. राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है।

(a) भारत के राज्यों का

(b) संघ एवं राज्यों का

(c) संघ का

(d) कोई नहीं

8. यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी।

(a) राज्यसभा

(b) लोकसभा

(c) लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों

(d) राष्ट्रपति

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

9. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ..... होता है।

10. लोक सभा के पहले अध्यक्ष ..... थे।

11. संविधान का 52वां संविधान संशोधन ..... से संबंधित है।

12. विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक..... कहलाता है।

13. लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ..... करता है।

14. संविधान की 10 अनुसूची में राज्य सभा के सदस्यों की संख्या ..... सुनिश्चित की गई है।

निम्नलिखित कथन बताएं सही है या गलत।

15. संसद में राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।

16. संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

17. मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

18. गैर सरकारी विधेयक वह हैं जो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं।

19. संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट के सदस्यों को राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

20. लोक लेखा समिति यह देखती है कि सरकारी उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं।

निम्नलिखित कथनों को सही करके लिखें।

21. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

22. संविधान संशोधन विधेयक यदि दूसरे सदन में पारित नहीं होता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में उल्लेखित है।

23. सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं यह कार्य लोक उपक्रम समिति का है।

24. विभिन्न विधाएं तथा दैनिक कार्यों के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। इनकी संस्तुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य है।

25. भारतीय संघ में राज्यों की विधानसभाओं में दो सदनों की व्यवस्था अनिवार्य है।

26. कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या मतदान ना करें या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे लोकसभा का नियंत्रण कहा जाता है।

28. संसद का किन्हीं दो समितियों के नाम लिखो।

अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दें।

29. भारतीय संसद का कौन–सा सदन अधिक शक्तियशाली है?

30. वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है?

31. संसद के कौन–से तीन सत्र होते हैं?

32. संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख करें।

33. द्विसदनीय विधायिका का कोई एक लाभ समझाएं।

34. भारतीय संविधान में कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया है?

35. संसदीय नियंत्रण के किन्हीं दो साधनों का उल्लेख करें?

36. अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है?

37. कोई एक तर्क प्रस्तुत करें जिससे राज्यसभा की प्रासंगिकता का महत्व पता चलता है।

38. राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकती है?

निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें।

विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है यह सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केन्द्र है। सदन का इसके तहत विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग इत्यादि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल तथा प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा कसती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

1. विधायिका किस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का मुख्य आधार है?

2. क्या आप मानते हैं कि एक शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है? अगर हां तो क्यों?

3. संसदीय नियंत्रण के किन्हीं दो साधनों का उल्लेख करें।

4. भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक विधायिका को क्यों अपनाया गया है? कोई एक कारण बताएं।

निम्नलिखित अवतरण का पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दें:

विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकांशतः संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशें को सदन में भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों का लघु विधायिका भी कहते है। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है।

1. संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है?
2. संसदीय समितियों में किस सदन के सदस्य होते हैं?
3. संसदीय समितियों का क्या महत्व है?
4. संसदीय समितियों ने विधायिका के कार्यों को काफी कम कर दिया है क्या आप कथन से सहमत हैं?

दो अंकीय प्रश्न–

1. दि–सदनात्मक विधायिका के पक्ष में दो तर्क दीजिए?
2. भारत के किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए जिनमें द्वि–सदनात्मक विधायिका है?
3. राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए?
4. लोकसभा की दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए?
5. वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर है स्पष्ट करें।
6. मिलान करो–

(क)	राज्य सभा में मनोनीत सदस्य	(1)	राज्यसभा
(ख)	निम्न सदन	(2)	लोकसभा
(ग)	ऊपरी सदन	(3)	2
(घ)	लोकसभा में मनोनीत सदस्य	(4)	12

7. दलबदल में क्या अभिप्राय है?
8. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दो योग्यताएं कौन–सी है?
9. राज्यसभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए?
10. किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है?

चार अंकीय प्रश्न–

1. विधायिका / संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केन्द्र है। स्पष्ट करें।
2. लोकसभा किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब है चार तर्क दीजिए।
3. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?

4. यह नहीं है कि लोकसभा महत्वपूर्ण सदन है लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां है जो उसे विशिष्ट बनाती है क्या आप इस कथन से सहमत है?

5. भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई चार चरण बताइए?

पांच अंकीय प्रश्न–

1. भारत के मानचित्र का अध्ययन करें तथा द्वि सदनात्मक विधायिका वाले कोई पांच राज्यों का नाम लिखें।

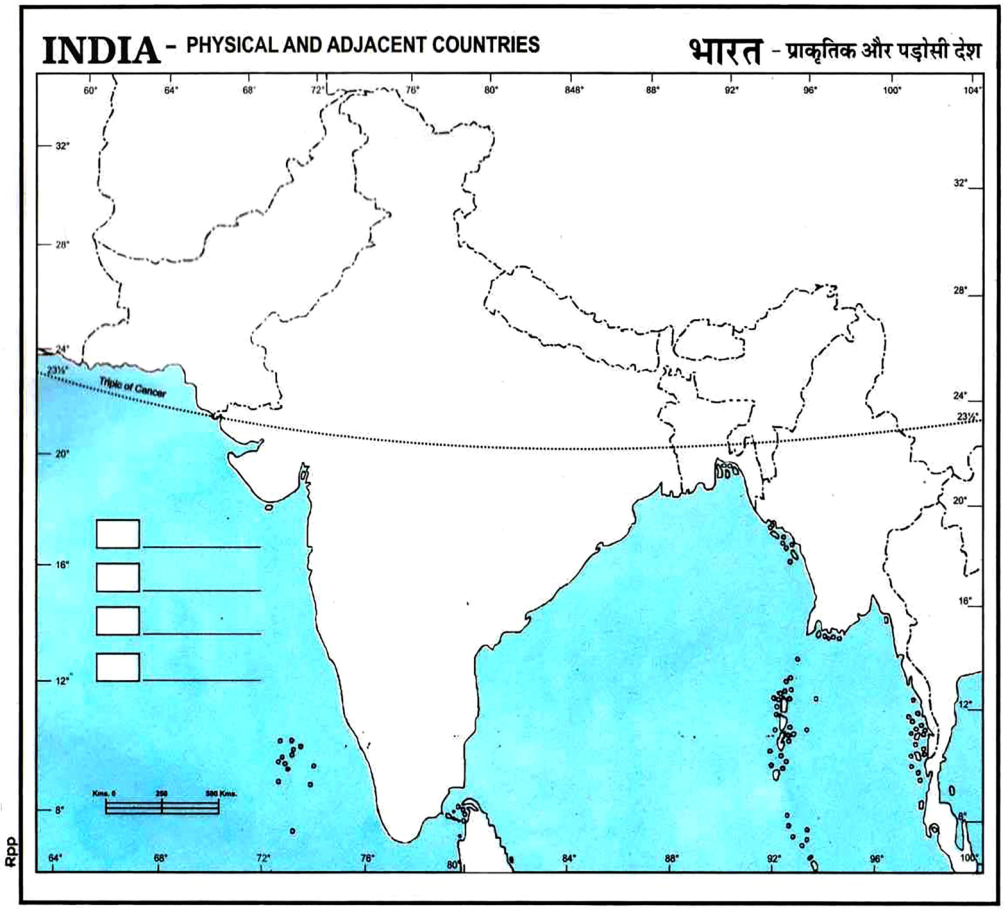

उपरोक्त कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(i) सदन से वॉक आऊट करना क्या एक उचित तरीका है? स्पष्ट करें।

(ii) अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आऊट कर सकते है? (कोई दो कारण)

(iii) सदस्यगण वॉक आऊट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें।

छः अंकीय प्रश्न–

1. लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है।

2. लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत है? कारण सहित उत्तर दें।

3. केवल कानून निर्माण ही नहीं, अपितु संसद अनेक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की सहभागिता का हिस्सा है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए संसद के कार्यो का उल्लेख करें।

4. संसदीय नियन्त्रण के वे कौन–से कारक है जो कार्यपालिका को अपने नियन्त्रण में रखते हैं।

5. प्रश्नकाल प्रशासनिक एवं कार्यकारी एजेन्सी पर नियन्त्रण का महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। स्पष्ट करें।

उत्तरमाला

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (ग)
2. (ग)
3. (ख)
4. (क)
5. (ख)

अभिकथन एवं तर्क

1. (घ)
2. (क)

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. 30 वर्ष
2. लोकसभा अध्यक्ष
3. लोकसभा
4. राष्ट्रपति
5. कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा
6. 14 दिन
7. भारत के राज्यों का
8. लोकसभा
9. 6 वर्ष
10. जीवी मावलंकर

11. दलबदल
12. गैर सरकारी विधेयक
13. लोकसभा अध्यक्ष
14. दसवीं अनुसूची
15. गलत
16. गलत
17. सही
18. सही
19. सही
20. गलत
21. एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं
22. संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है यह सामान्य विधेयक पर होता है।
23. लोक लेखा समिति
24. इनकी संस्तुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है
25. दो सदन की व्यवस्था अनिवार्य नहीं है
26. दलबदल कहा जाता है
27. तेलंगाना
28. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति लोकसभा
29. लोकसभा अधिक शक्तिशाली है
30. द्विसदनात्मक राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक ,महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
31. 3 सत्रः बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र
32. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
33. विधेयक पर पुनर्विचार
34. तीन सूचियों का उल्लेख

35. प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव

36. अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्य सूची के विषय पर यदि परिवर्तन करना है तो राज्यसभा की सहमति लेना आवश्यक है।

37. यह सदन विधायकों पर पुनविचार करता है तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है

38. 6 महीने तक अपने पास रख सकती है।

अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर

1. (A) विधायिका

2. (A) विधायिका

3. (D) उपर्युक्त सभी

4. (B) द्विसदनीय

1. संसदीय समितियों को लघु समिति कहा जाता है क्योंकि इन समितियों में विषय विशेष से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो उस विषय पर बारीकियों से विचार–विमर्श करते हैं।

2. संसदीय समितियों में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं।

3. संसदीय समितियों का महत्व यही है कि इसमें सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व होता है तथा कानून बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना होता है जिसे संसदीय समिति भली–भांति पूरा करती है।

4. क्योंकि संसद के पास समय की कमी होती है। इसीलिए संसदीय समितियों ने विधायिका के कार्यों को काफी कम किया है।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (1) समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है।
   (2) दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार कम करता है।

2. (1) आन्ध्र प्रदेश (2) उत्तरप्रदेश (3) बिहार (4) कर्नाटक

3. राज्यसभा के कुल सदस्य 250 है जिसमें 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।

4. (1) धन विधेयक पेश करना
   (2) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण।

5. संविधान में संशोधन के लिए या सामान्य विधयकों को गैर वित्त विधेयक कहते है जबकि धन संबंधी विधेयकों को वित्त विधेयक कहते है जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का बजट।

6. मिलान करो–

(क) (4)

(ख) (2)

(ग) (1)

(घ) (3)

7. जब कोई सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें और दल की सदस्यता ग्रहण कर लें उसे दलबदल कहते है।

8. (1) वह भारत का नागरिक हो।?

(2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

9. (1) राज्य सभा, राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

(2) राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्र के हित में गठन कर सकती है।

10. जब दोनों में मतभेद हो।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) विधि निर्माण।

(ii) बजट पारित करना।

(iii) सरकार पर नियंत्रण।

(iv) संविधान में संशोधन।

2. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखे।

3. (i) भारत का नागरिक।

(ii) आयु 25 वर्ष।

(iii) पागल व दिवालिया न हो।

(iv) किसी लाभप्रद सरकारी पद पर न हो।

4. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखें।

5. प्रथम वाचन
   द्वितीय वाचन
   तृतीय वाचन
   राष्ट्रपति की स्वीकृति (व्याख्या सहित)।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. 1. तेलंगाना
   2. उत्तर प्रदेश
   3. बिहार
   4. महाराष्ट्र
   5. आंध्रप्रदेश
   6. कर्नाटक

2. (i) नहीं, क्योंकि सदन एक ऐसा मंच है। जहां पर वाद–विवाद चर्चा, बहस व सहमति के आधार पर किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है।
   (ii) अनुशासनहीनता पर ।
   (iii) विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखें।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) प्रश्न, पूरक, प्रश्न , काम रोको प्रस्ताव आदि से
   (ii) अविश्वास प्रस्ताव
   (iii) मंत्रीपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
   (iv) जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि
   (v) लोकप्रिय सदन
   (vi) सदस्य संख्या अधिक

2. (i) जनता के चुने प्रतिनिधि होने के कारण
   (ii) जनहित में कानून बनाना।

(iii) जनआकांक्षाओं एवं भावनाओं से परिचित होना।

(iv) चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेहिता। (व्याख्या सहित)

3. कानून बनाना
कार्यपालिका पर नियंत्रण
बहस व चर्चा
वित्तीय नियंत्रण व अविश्वास प्रस्ताव आदि।

4. विचार विमर्श एवं वाद–विवाद, कानून निर्माण पर सहमति या असहमति अविश्वास प्रस्ताव, आर्थिक नियन्त्रण।

5. जनता के हितों की अभिव्यक्ति सरकार के कार्यो की आलोचना का अवसर निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं की प्रस्तुति।

अध्याय 4

कार्यपालिका

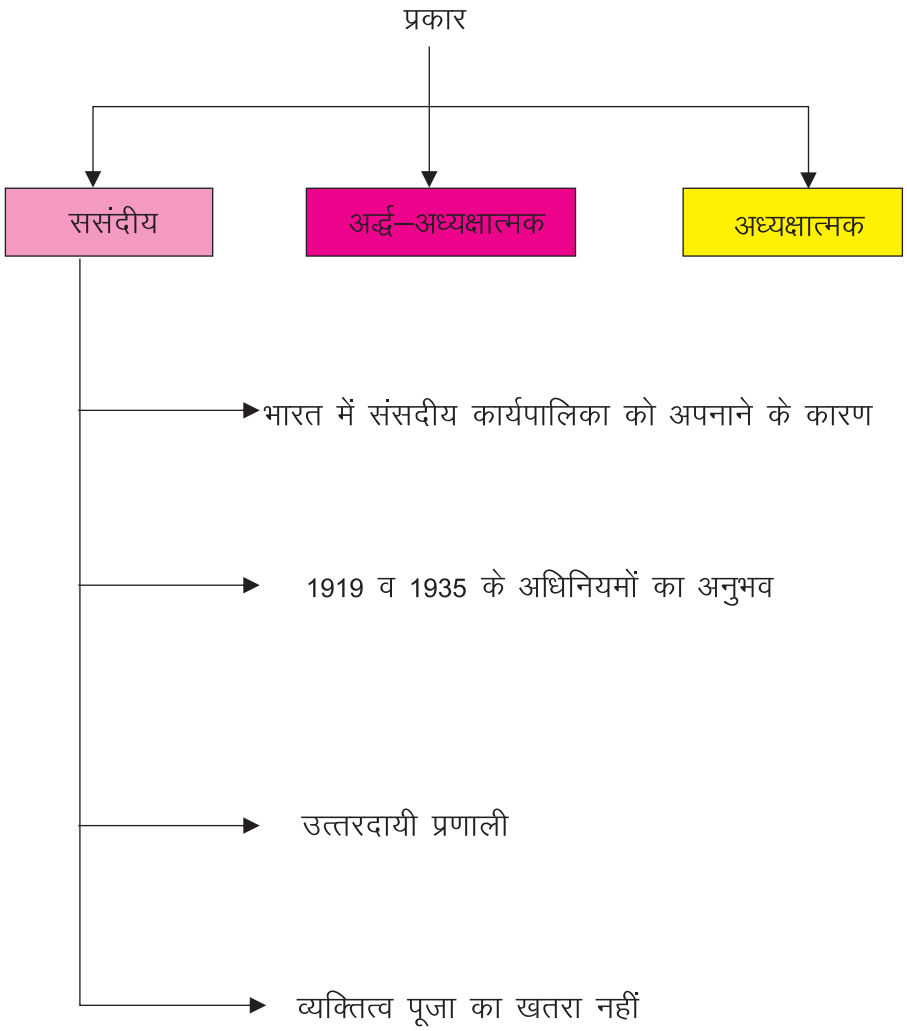

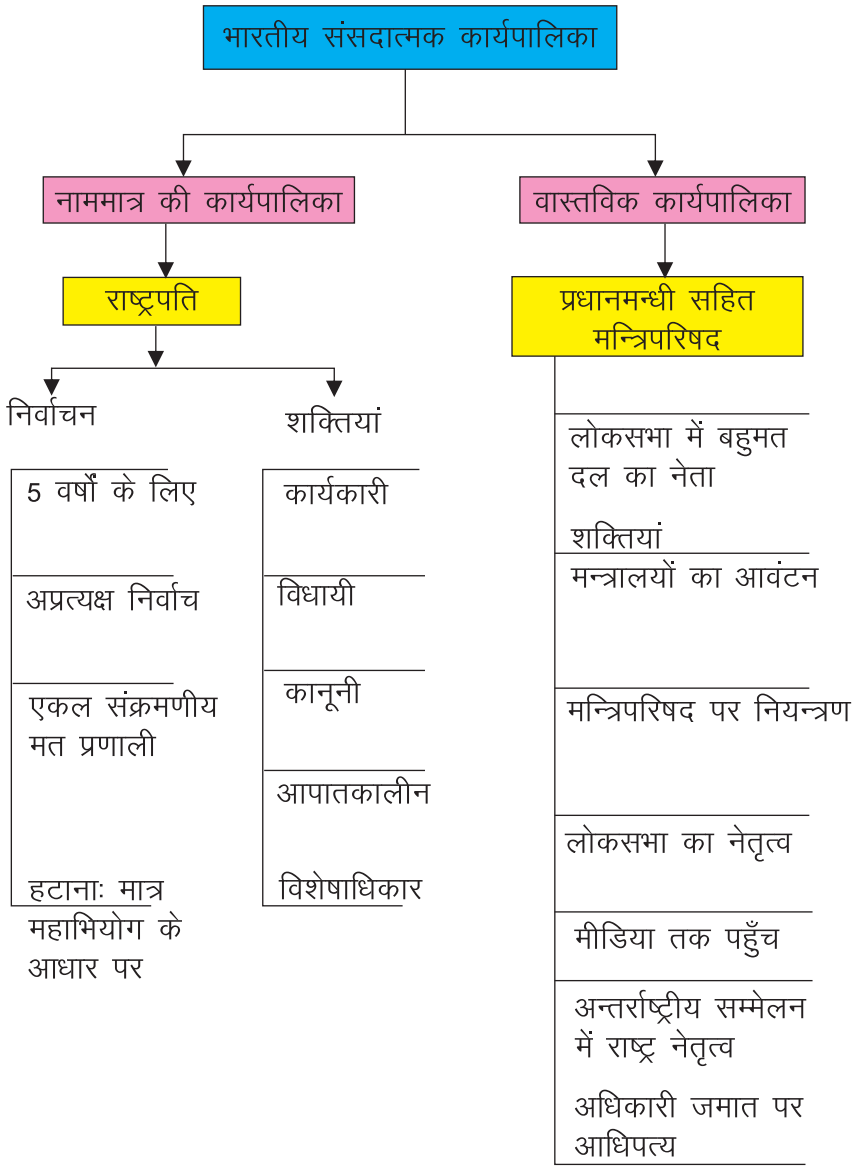
भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका
नाममात्र की कार्यपालिका
वास्तविक कार्यपालिका
राष्ट्रपति
प्रधानमन्धी सहित मन्त्रिपरिषद
निर्वाचन
शक्तियां
5 वर्षों के लिए
अप्रत्यक्ष निर्वाच
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
हटानाः मात्र महाभियोग के आधार पर
कार्यकारी
विधायी
कानूनी
आपातकालीन
विशेषाधिकार
लोकसभा में बहुमत दल का नेता
शक्तियां
मन्त्रालयों का आवंटन
मन्त्रिपरिषद पर नियन्त्रण
लोकसभा का नेतृत्व
मीडिया तक पहुँच
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र नेतृत्व
अधिकारी जमात पर आधिपत्य

अध्याय के मुख्य बिन्दुः 1. कार्यपालिका क्या है? 2. कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार, 3. भारत में संसदात्मक कार्यपालिका, 4. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, 5. प्रधानमंत्री की शक्तियां, 6. स्थायी कार्यपालिकाः नोकरशाही।

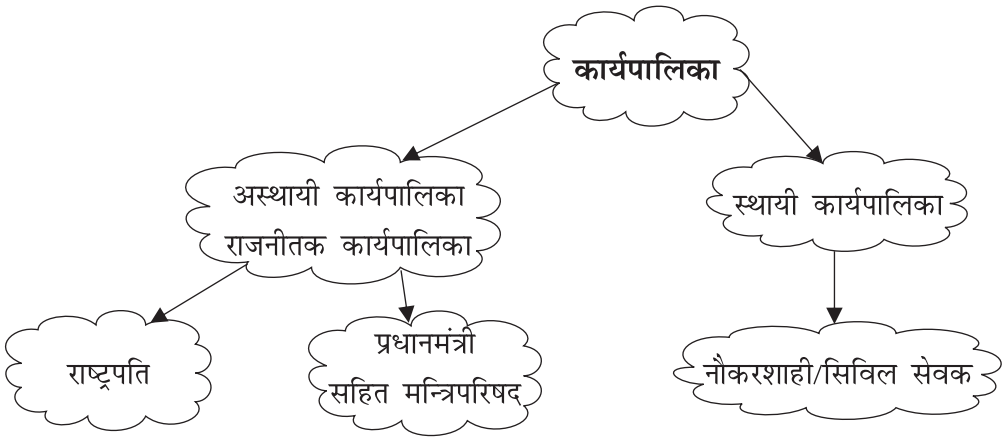

कार्यपालिका के प्रकार

	सामूहिक नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित	
संसदात्मक	**अर्द्ध अध्याक्षात्मक**	**अध्यक्षात्मक**
सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है	राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।	राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है।
वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है।	सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।	राष्ट्रपति सामान्यतया जनता द्वारा निर्वाचित होता है।
वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।	प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।	वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

कार्यपालिका का अर्थः–

- सरकार के उस अंग से है जो कायदे–कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते है।
- सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री य मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आता है।
- राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते है। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते है, स्थायी नही।
- स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते है, को सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक है जैसै IAS, IPS आदि।
- अमेरिका में अध्याक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है।
- कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- फ्रांस में राष्ट्रपति ओर प्रधानमंत्री अर्द्वअध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
- इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- रूस में एक अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।

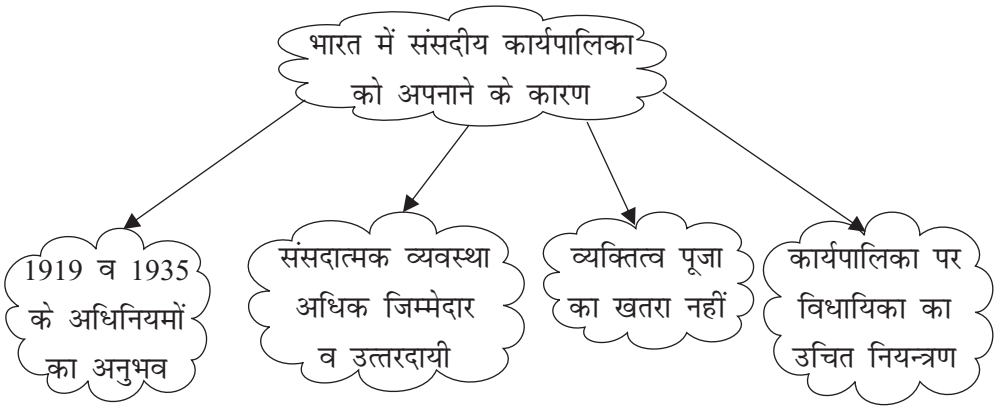

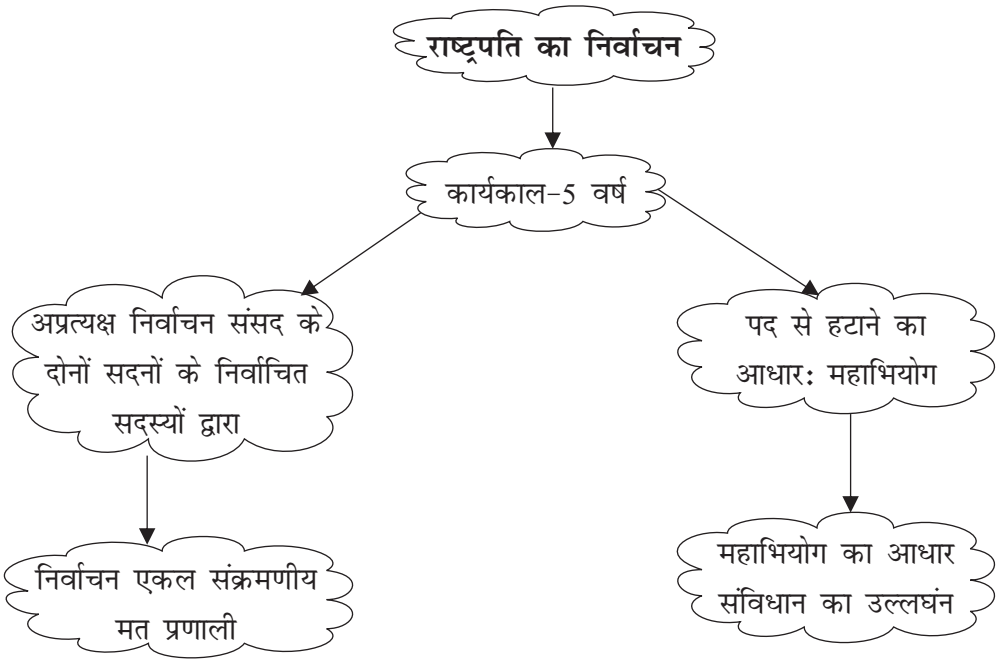

मन्त्रिपरिषद का आकारः संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवंनिश्चित किया गया है। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यस्तर के आधार पर मन्त्रियों का तीन स्तर में विभाजन होता है।

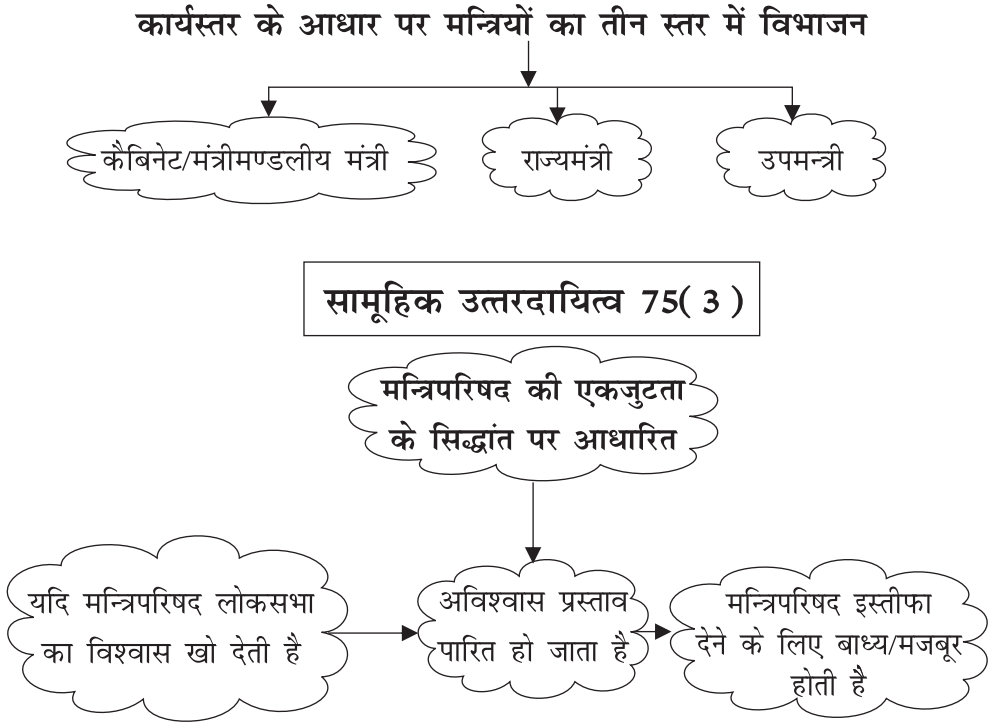

- अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील और लेटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है।
- संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाममात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है।
- अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

भारत में संसदीय कार्यपालिकाः–

- अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ–साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगें हो।

– संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
– भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति, औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते है।

राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितिः–

– एक औपचारिक प्रधान हैः राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी (कानून बनाना) कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकारः–

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

1. सदनों को पुर्नविचार के लिए लौटा सकता है।
2. वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलम्ब।
3. चुनाव के बाद कई नेताओं के दावें के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।

आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है?

– संसदीय व्यवस्था मे, समर्थन न रहने पर, मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।
– राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं।
– भारत का उपराष्ट्रपतिः पांच वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है।

विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति

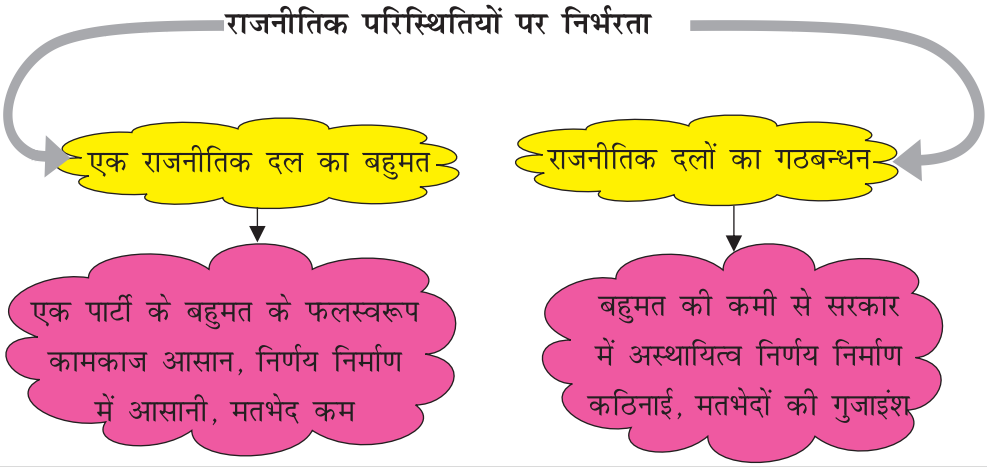

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद

प्रधानमन्त्री पद के लिए योग्यता–

1. वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
2. बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
3. यदि प्रधानमन्त्री बनने के लिए समय वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो छः महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यही स्थिति मन्त्रीयों पर भी लागू होगी।

प्रधानमंत्री पद की शक्तियो में आए बदलावः–

1. प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है।
2. राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है।
3. प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है।
4. सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है।

राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूपः–

- राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो (केन्द्रीय सरकार की सलाह पर) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
- मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केन्द्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है।

स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही):–

कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन, सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते है।

- नौकरशाही में सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।
- भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारे आती जाती रहती है ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करें।
- नौकरशाही के सदस्यों का चुनावः नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी

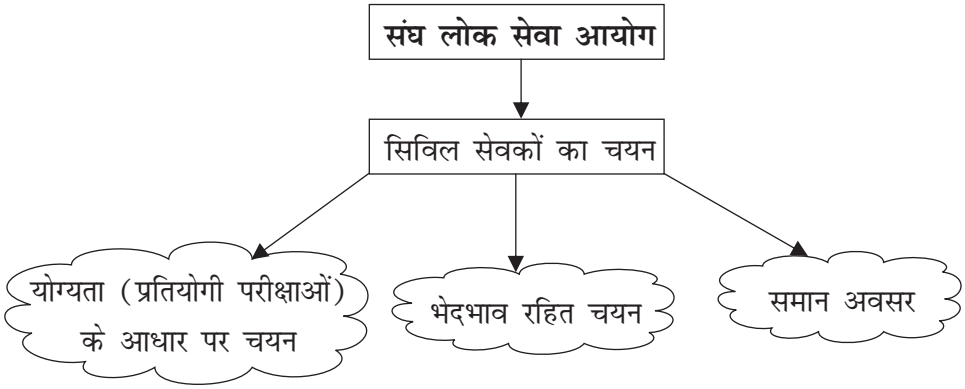

एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को सौंपा गया है।

- ऐसा ही लोकसेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए है जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है।
- लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।
- लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती हैं संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है।

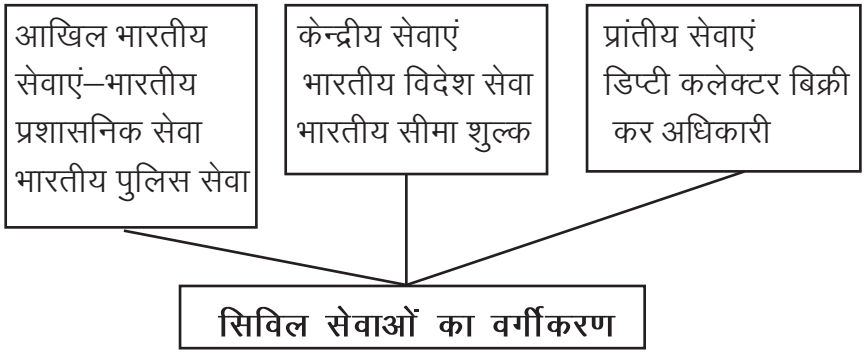

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये समान्यतः आई ए एस स्तर का अधिकारी होता है।

नोटः— पॉकेट वीटो (Pocket Veto) — जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद-III के अर्न्तगत पुर्नविचार को भी नहीं लौटाता है ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता हैं।

   (क) राज्य का प्रधान

   (ख) सरकार का प्रधान

   (ग) राज्य व सरकार दोनों का प्रधान

   (घ) इनमें से कोई नहीं।

2. प्रधानमन्त्री पद के लिए आयु निर्धारित हैं।

   (क) कम से कम 20 वर्ष

   (ख) कम से कम 25 वर्ष

   (ग) कम से कम 30 वर्ष

   (घ) निर्धारित नहीं

3. सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्वान्त आधारित है

   (क) राज्य सभा के सदस्यों की एक जुटता पर आधारित

   (ख) लोकसभा सदस्यों की एक जुटता के सिद्वान्त पर आधारित

   (ग) मन्त्रिपरिषद की एक जुटता के सिद्वान्त पर आधारित

   (घ) उपरोक्त में से कोई नही

4. राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है।

   (क) अभियोग (ख) अभियुक्ति

   (ग) महाभियोग (घ) सभी

5. अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली हैं?

   (क) ससंदात्मक (ख) अध्यक्षात्मक

   (ग) मिश्रित (घ) साम्यवादी

अभिकथन कारणः–

1. अभिकथन : संविधान के 91वे संविधान संशोधन द्वारा मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित किया गया है।

   तर्क कारणः मन्त्रिपरिषद को कार्य–स्तर के आधार पर तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है।

   (क) कथन एवं तर्क दोनों सत्य है तथा तर्क कथन की सही व्याख्या करता हैं।

   (ख) कथन एवं तर्क दोनों सत्य है लेकिन तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

   (ग) कथन गलत है एवं तर्क सही हैं।

   (घ) कथन सही है तर्क गलत है।

2. अभिकथन : अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्तित्व पूजा का खतरा बना रहता है।

   तर्कः अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में उत्तरदायित्व को अपेक्षा स्थायित्व पर बल दिया जाता है।

   (a) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

   (b) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है

   (c) A गलत है और R सही है

   (d) A सही है लेकिन R गलत है

6. भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार है।

   (a) राजनीतिक योग्यता (b) दक्षता एवं योग्यता

   (c) मात्र निर्वाचन (d) कोई नहीं

7. राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं

   (a) संसद के दोनों सदनों के सदस्य

   (b) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य

   (c) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य

   (d) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

8. संविधान के 91 वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया है.....

9. राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है.....

10. राज्यसभा का पदेन सभापति ..... होता है।

11. राष्ट्रपति का निर्वाचन ..... प्रणाली द्वारा होता है।

12. भारतीय विदेश सेवा ..... सेवाओं के अंतर्गत आती हैं।

निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखें।

13. वीटो शक्ति से अभिप्राय है राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति तुरंत देता है।

14. मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. अध्यक्षात्मक कार्यलालिका में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अलग–अलग होता है।

16. भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

निम्नलिखित कथन बताएं सही है या गलत।

17. संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है राष्ट्रपति को चुनना।

18. भारत में निर्वाचित नौकरशाही का सिद्धांत अपनाया गया है।

19. भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है।

20. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दें।

21. कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?

22. कार्यपालिका में मुख्यतः किन–किन लोगों को शामिल किया जाता है?

23. भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है?

24. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।

25. भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेकीय शक्ति है का उल्लेख करें।

26. राष्ट्रपति को विशेषाधिकार की शक्ति से क्या अभिप्राय है?

27. कार्यपालिका तथा राजनीतिक कार्यपालिका में कोई एक अंतर बताएं।

28. पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं?

29. सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है?

30. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

31. जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है?

32. लोक सेवा में दक्षता योग्यता के साथ ही समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान सुनिश्चित किया है।

33. लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है?

34. **निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें:**

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भाग लेती है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थाई कार्यपालिका कहते हैं।

1. राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं?

   (A) सरकार का प्रमुख (B) केवल मंत्री

   (C) सरकार का प्रमुख तथा मंत्रीपरिषद् (D) उपर्युक्त में कोई नहीं

2. स्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है?

   (A) मंत्री (B) नौकरशाही

   (C) प्रधान मंत्री (D) उपर्युक्त सभी

3. कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है?

   (A) कानून निर्माण (B) न्यायिक निर्णय

   (C) नीतियों व कानूनों को लागू करना (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है–

   (A) प्रधान मंत्री (B) मंत्री

   (C) प्रधान मंत्री तथा उसकी मंत्रीपरिषद् (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत–सी कार्यकारी, विधायी, आपात शक्तियां प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है।

1. भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन है?

(A) प्रधान मंत्री (B) राष्ट्रपति

(C) राज्यपाल (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है?

(A) स्पीकर (B) मंत्री

(C) प्रधान मंत्री (D) कार्यपालिका

3. लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है?

(A) राष्ट्रपति (B) प्रधान मंत्री

(C) वित्त मंत्री (D) स्पीकर

4. 'डी फैक्टो' कार्यपालिका का अर्थ है–

(A) वास्तविक कार्यपालिका (B) नाममात्र की कार्यपालिका

(C) नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका (D) उपर्युक्त सभी

दो अंकीय प्रश्नः–

1. कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का वर्णन करों।
2. एकजुटता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है?
4. 'राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है' स्पष्ट करो?
5. ''मंत्रीगण एक साथ तैरते है तथा एक साथ डूबते हैं'' इस कथन का क्या आशय है?
6. प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कैसे?
7. ''राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है''। कैसे?
8. ''भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है'' स्पष्ट करें।

9. 'समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें' इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए है?

10. ''नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है'' क्या आप इस कथन से सहमत है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थाई कार्यपालिका में चार अंतर बताएं।

2. संसदीय कार्यपालिका की चार विशेषताओं का वर्णन करें जो उसे विशिष्ट बनाती है।

3. ''अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है'' कैसे?

4. राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन करो।

5. राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बनाते हैं।

6. ''प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता।'' क्यों?

7. ''प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है'', स्पष्ट करों।

8. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–

(1) चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा हे? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है?

(2) किन्हीं दो नेताओं को पहचाने उनके नाम लिखे।

(3) प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण लिखे।

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–

(1) विश्वास मत से क्या अभिप्राय है?

(2) सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है?

(3) ''विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है।

छः अंकीय प्रश्नः–

1. राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करों।
2. क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है'' तीन उचित तर्क दीजिए।
3. जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

4. आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है?

5. नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है?

6. गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां बढ़ जाती है इसक कथन की तर्क सहित पुष्टि करें।

7. स्वतन्त्र भारत मे अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का आधार दक्षता, प्रशासनिक योग्यता एवं समान अवसर की सुनिश्चितता को ध्यान में रखकर किया गया। ऐसा क्यों?

8. नौकरशाही ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही अपनी दृढ़ मौजूदगी एवं प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया है। व्याख्या करें।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्न के उत्तरः–

1. (ग)
2. (ख)
3. (ग)
4. (ग)
5. (ख)

अभिकथन तर्क

1. ख 2. क

1. राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद
2. 1989
3. जवाहरलाल नेहरू
4. संविधान के उल्लंघन पर
5. संघ लोक सेवा आयोग
6. दक्षता एवं योग्यता
7. संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
8. मंत्री परिषद का आकार
9. महाभियोग

10. उपराष्ट्रपति
11. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
12. केंद्रीय सेवाओं
13. संसद से पारित विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करना
14. कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं
15. राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुख एक ही
16. संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है
17. गलत
18. गलत
19. सही
20. सही
21. सरकार का वह अंग जो कानूनों को लागू करता है।
22. कार्यपालिका में मुख्यतः प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है।
23. भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ अध्यक्ष है जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्र अतिथि के द्वारा बनी अध्यक्ष है।
24. जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है।
25. जब लोकसभा में किसी राजनतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तब प्रधानमंत्री का चुनाव करना।
26. सदन को पुनर्विचार के लिए बिल लौट आना।
27. स्थाई कार्यपालिका में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदाई कर्मचारी सम्मिलित होते हैं वही कार्यपालिका में सरकार के प्रधान तथा उनके मंत्रियों को शामिल किया जाता है।
28. जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और पुनर्विचार को भी लौट आता है तो ऐसी स्थिति में वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है।
29. जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना होता है इसका मतलब यही है कि यदि किसी एक मंत्री के विरूद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है।
30. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
31. भारतीय प्रशासनिक सेवा
32. आरक्षण का प्रावधान
33. प्रधानमंत्री

34. 1. राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान तथा उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है।

2. (A) नौकरशाही

3. कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियां तथा कानूनों को लागू करने का है।

4. राजनीतिक कार्यपालिका का एक उदाहरण है प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्री

35. 1. (D) भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है।

2. (C) प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद

3. (B) प्रधानमंत्री

4. (A) राज्य का प्रमुख व सरकार प्रमुख अलग–अलग

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (संक्षिप्त वर्णन)

2. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देता पड़ता है।

3. जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति
   (1) अध्यादेश जारी कर सकता है।
   (2) यदि देश पर आक्रमण हो जाए।
   (3) यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए।

4. क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है।

5. यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाएं तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र देने को कहता है यदि वह त्यागपत्र न दें तो प्रधानमंत्री स्वंय अपना त्याग पत्र दे देता है और सरकार गिर सकती है।

6. जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है पंरतु जब बहुमत नहीं होता तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते है।

7. क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है इसीलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है।

8. भारत में लोकसेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते है वे अपने–अपने विषय में पारंगत होते है इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में वे राजनीतिज्ञों की सहायता करते है।

9. संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया।

10. हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते है और वे राजनीतिज्ञों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते है।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राजनीतिक कार्यपालिका– 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते।

   स्थाई कार्यपालिका–रिटायरमेंट की आयु तक काम करते है अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते है।

2. – सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री
   – राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा या रानी
   – विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री
   – विधायिका के प्रति उत्तरदायी

3. अध्यक्षात्मक– देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना।

4. विधायी कार्यपालिका, न्याय संबंधी, तीनो सेनाओं का सेनापति।

5. (1) वीटो (2) गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव

6. क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।

7. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाहियों से अवगत कराता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है।

8. राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है
   – मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता
   – नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता
   – मध्यस्थ की भूमिका बन गई है।

5. अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (क) 1. पं. जवाहर लाल नेहरू क्योंकि वो प्रधानमंत्री है

2. अध्यापक की सहायता से पहचानें व उत्तर दें।

3. – क्योंकि वह बहुमत दल का नेता है।

– वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है।

(ख) 1. सदन में बहुमत

2. संसद के प्रति उत्तरदायी

3. क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दें तो फिर से वहीं संकट आ जाएगा।

छः अकीय प्रश्नों के उत्तरः

1. स्थितिः राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, नामपात्र की शक्तियां।

2. हां, क्योंकिः–

(1) संविधान में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 74 (1)

(2) क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है।

(3) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी है।

3. तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियां कम हो जाती है और विचार–विर्मश अधिक हो जाता है।

4. – मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
– अधिकारी वर्ग पर अधिपत्य
– लोकसभा का नेतृत्व
– मीडिया तक पहुंच
– चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार,
– अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
– विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि

5. नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायक, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं (कोई अन्य)।

6. गठबन्धन के दौर में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति का बढ़ना–

   (क) प्रधानमंत्री का चयन (यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता।) उदाहरणों के साथ व्याख्या करें।

   (ख) किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति पर निर्णय लेने की अधिक जिम्मेदारी।

7. दक्षताः ताकि कुशल एवं निपुण कार्यपालिका कार्यों को भली–भांति कर सके।

   प्रशासनिक योग्यताः लोकतान्त्रिक मूल्यों का संर्वद्धन तथा ही सम्भव जब सबको समान अवसर उपलब्ध है।

8. नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन नौकरशाही द्वारा ही सम्भव।

   दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिए उत्तरदायी

   सामाजिक समस्याओं को कुशलतापूर्वक निपटाने में सक्षम।

   सूचना के अधिकार जैसे कदमों ने नौकरशादी को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाया।

अध्याय 5

न्यायपालिका

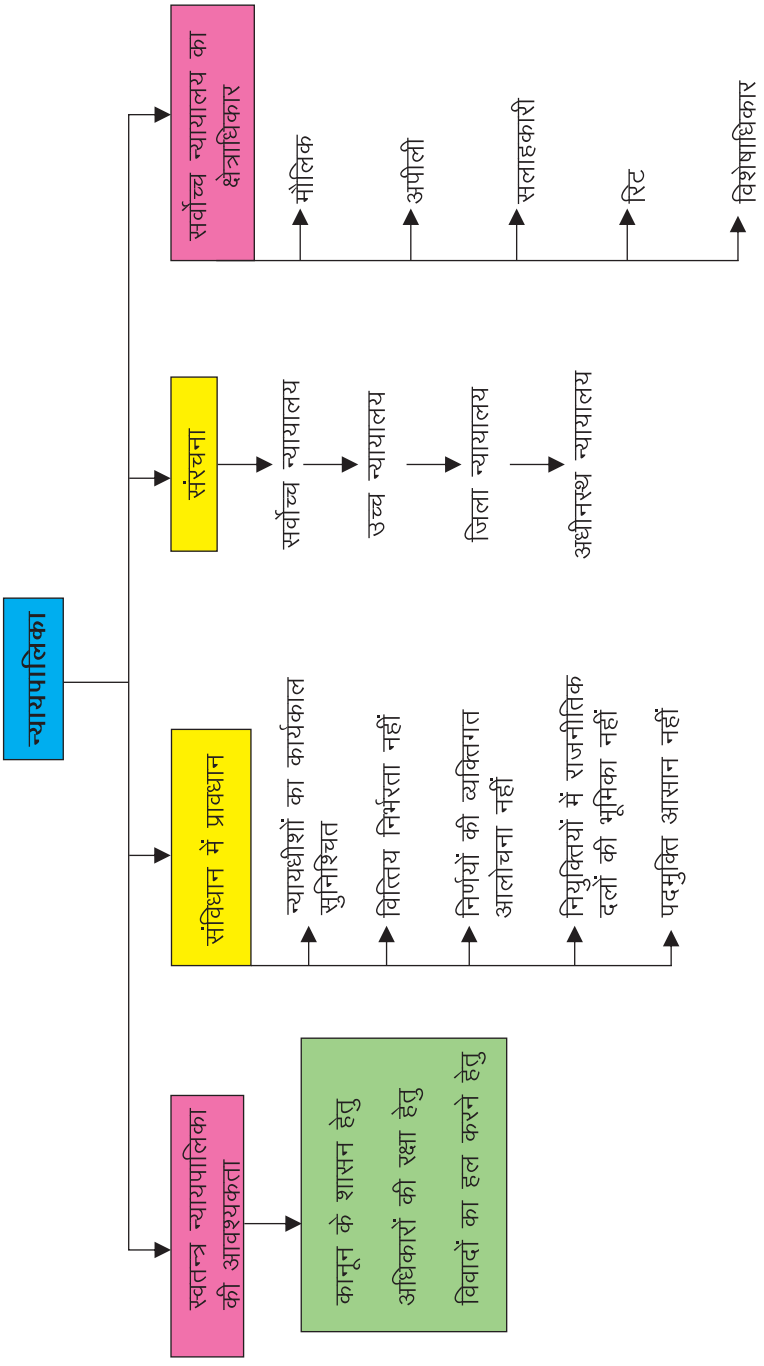

अध्याय के मुख्य बिन्दुः स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, न्यायालय की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायपाकिा तथा अधिकार, न्यायपालिका तथा संसद।

- न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। इसके लिये यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक परम्परा और जनता के प्रति जवाबदेह है।
- विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सकें।
- न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।
- न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निशिचित कार्यकाल होता है। ये सेवा निवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते है। विशेष स्थितियों में न्यायधीशों को हटाया जा सकता है।
- न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।

न्यायधीश की नियुक्तिः–

- मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायधीश– ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते है।
- मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परम्परा भी है कि सर्वोच्च न्यायलय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश चुना जाता है किन्तु भारत में इस परम्परा को दो बार तोड़ा भी गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायलय के अन्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से करता है। ताकि न्यायलय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे।

न्यायपालिका की पिरामिड रूपी सरंचनाः–

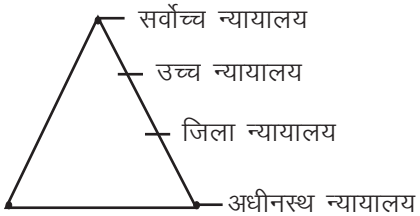

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार–आरम्भिक क्षेत्राधिकार

– **मौलिक अधिकारः** केन्द्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।

– **रिटः** मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित विवाद।

अपीलीय

– दीवानी फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायलयों के मुकदमों पर अपील सुनना।

सलाहकारी

– जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

विशेषाधिकार

– किसी भारतीय अदालत के दिये गये फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई।

– भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जन हित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है।

– 1979–80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायधीश ने उन मामलें मे रूचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवाएँ नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायलय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से–याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी।

– न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतंत्रिक बनाया और कार्यपलिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई।

– चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त ओर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।

– चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अपनी संपति आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

सक्रिय न्यायपालिका का नकरात्मक पहलू:–

– न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा

– न्याायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया जैसे–वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए।

– सरकार का प्रत्येक अंग एक–दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायिक पुनराक्लोकन का अधिकार

– न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरित हो तो उसे गैर–संवैधानिक घोषित कर सकता है।

– संघीय संबंधी (केंद्र–राज्य संबंध) के मामलें में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

– न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती हैं तथा प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है।

– नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।

– जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारी की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है।

न्यायपालिका और संसद–

– भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।

– संपत्ति का अधिकार।

– ससद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में।

– इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।

– निवारक नजरबंदी कानून।

– नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून।

1973 में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय

– संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचें से छेड़–छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढाँचें को नहीं बदला जा सकता।

– संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायलय ने कहा कि यह मूल ढाँचें का हिस्सा नहीं है उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

– न्यायलय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।

– संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते है। संविधान यह व्यवस्था करती है कि न्यायधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है।

– लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है।

प्रश्न

1. कौनसे न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है

   (a) उच्च न्यायालय (b) जिलान्यायालय

   (c) सैनिक न्यायालय (d) कोई नहीं

2. जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गयी?

   (a) अमेरिका (b) दक्षिण अफ्रीका

   (c) भारत (d) जापान

3. भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है

(a) 60 वर्ष (b) 62 वर्ष

(c) 65 वर्ष (d) 70 वर्ष

4. न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख मिलता है।

(a) संविधान के अनुच्छेद 134 में

(b) संविधान के अनुच्छेद 224 में

(c) संविधान के अनुच्छेद 226 में

(d) संविधान के अनुच्छेद 27 में

5. निम्नलिखित में से कौन–सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यकता नहीं है

(a) वह भारत का नागरिक हो।

(b) वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायधीश हो।

(c) वह हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव।

(d) हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक रहा है।

6. अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है।

(a) सर्वोच्च न्यायालय (b) उच्च न्यायालय

(c) उच्च न्यायालय (d) जिला नयायालय

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

7. न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार की .....निधि से प्रदान किए जाते हैं।

8. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो को व्यक्तिगत आलोचना से ..... प्रदान की गई है।

9. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ..... करता है।

10. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के ..... संविधानिक अनुच्छेद में निहित है।

11. भारत का सर्वोच्च न्यायालय ..... स्थित है।

निम्नलिखित कथन बताएं कि सही है या गलत।

12. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है।

13. न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम अमेरिका में मिलता है।
14. सवाच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तिया राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
15. न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन के संविधान में मिलता है।
16. सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
17. भारतीय संविधान, एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना करता है।

निम्नलिखित कथनों का सही करक उन्हे लिखो।

18. उच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
19. सर्वोच्च न्यायालय के आरम्भिक अधिकार से अभिप्राय है दीवाना फौजदारी जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनना।
20. भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया नहीं गया है।

अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

21. सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारीकारिता से आप क्या समझते हैं?
22. कानून के शासन से क्या अभिप्राय है?
23. सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है।
24. सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति से आप क्या समझते हैं।
25. अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय है।
26. न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दीजिए।
27. न्यायिक सक्रियता किस प्रकार न्यायालय को अधिक सक्रिय ,वं क्रियाशील बना रही है
28. जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है
29. भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं
30. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है
31. भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है।
32. भारत के मुख्य न्यायाधीशों को किस प्रकार उनके पद से हटाये का हटाया जा सकता है।

निम्नलिखित अवतरण को पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दे।

I. न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया तथा कार्यपालिका उत्तरदाई बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली भी कहीं अधिक मुक्त और निष्पक्ष बनी। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथपत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

1. न्यायिक सक्रियता है–

   (A) न्यायिक व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण (B) अनेक दुष्प्रभाव है

   (C) अनिवार्य दिशानिर्देश (D)उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. न्यायिक सक्रियता, कार्यपालिका को बनाती है–

   (A) गैर जिम्मेदार (B) उत्तरदायी

   (C) अनुत्तरदायी (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित में से क्या एक रिट का प्रकार है ?

   (A) अधिकार विहिनता (B) गैर न्यायिकता

   (C) अधिकार दृच्छा (D)समाजिकता

4. न्यायपालिका का कौनसा अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?

   (A) अपीलीय अधिकारक्षेत्र (B) रिट अधिकारक्षेत्र

   (C) सलाहकारी अधिकारक्षेत्र (D)उपर्युक्त सभी

दो अंकीय प्रश्नः–

1. जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरम्भ की गई?
2. जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया?
3. जनहित याचिका से किसको लाभ पहुंचता है?
4. न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है?
5. सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है?
6. न्यायपलिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है।

7. अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका है तथा कैसे?

8. कौन–सी दो शक्तियां सर्वोच्च न्यायलय को शक्तिशाली बना देती है?

9. कानून के शासन का क्या अर्थ है?

10. न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अन्तर है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन–सी रिटें जारी कर सकता है, उल्लेख करें।

2. परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करो।

.4. सामूहिकता के सिद्धान्त का क्या अर्थ है?

5. सर्वोच्च न्यायलय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। वर्णन करें।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1.

(1) उपरोक्त चित्र में न्यापालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही हैं। 1

(2) न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ। 2

(3) हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? 2

3. नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वाले को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाला का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके 'जीवन के अधिकार' का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ–सुथरे शहर के अधिकार से ज्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायधीश है। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस 'जनहित याचिका' में जनहित का मुद्दा है या नहीं?

(1) न्यायालय जाने वाले दो पक्ष कौन–कौन है? 1

(2) दोनों पक्षों ने जनहित के आधार पर अपना कौन–कौन सा पक्ष रखा? 2

(3) अगर आप न्यायधीश होते तो क्या निर्णय लेते तथा ये विषय जनहित याचिका का विषय है या नहीं? 2

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय न्यायपालिका की सरंचना पिरामिड के आकार की है वर्णन करो।?
2. सर्वोच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?
3. जनहित यचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है?
4. जनहित यचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकरात्मक पहलू क्यों माना जाता है?
5. भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है?
6. न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है क्या आप इस कथन से सहमत है?
7. न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है। इस कथन को जांचकर तर्कसहित उत्तर दे।
8. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू एवं गतिशील बनाने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है, समझाये।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. सैनिक न्यायालय
2. अमेरिका
3. 65 वर्ष
4. संविधान के अनुच्छेद 134 में
5. वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायधीश हो।
6. सर्वोच्च न्यायालय
7. संचित निधि
8. सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के जजों को व्यक्तिगत आलोचना से उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
9. राष्ट्रपति
10. अनुच्छेद 124
11. दिल्ली
12. सही
13. सही
14. गलत
15. गलत
16. गलत
17. सही
18. उच्चतम न्यायालय के फैसले
19. केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा
20. एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है।
21. दीवाली, फौजदारी, वैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनना।
22. कानून की नजर में सभी लोग समान है तथा सभी पर समान रूप से लागू होगा।

23. कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में।

24. जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

25. सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय भविष्य में भी अन्य न्यायिक निर्णयों के लिए कारगर होंगे।

26. सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक ताकि जांच कर सकता है।

27. न्यायालय ने न्यायिक किसी भी कानून की संवैधानिक ताकि जांच कर सकता है।

28. जनहित से संबंधित मुकदमों में एक व्यक्ति विशेष ही नहीं अपितु एक समूह भी जनहित याचिका दायर कर सकता है।

29. 30 + 1

30. 24 + 1

31. 2.8 lakh

32. न्यायाधीशों के विरूद्ध आरोपों पर

33. संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।

1. (A) न्यायिक सक्रियता ने न्यायालय के अधिकाररों का दायरा बढ़ाया है। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। इस प्रकार की अधिकारों पर मोहर न्यायालय ने लगाई है जिसने न्यायिक व्यवस्था की अधिक लोकतांत्रिक बनाया है।

2. (B) कार्यपालिक उत्तरदाई बनने पर बाध्य हुई है तथा चुनाव प्रणाली को भी अधिक मुक्त तथा निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।

3. (C) न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपति आए और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथपत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

4. (B) रिट अधिकारक्षेत्र

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. 1970 ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा बी. के. कृष्णअय्यर द्वारा।
2. अखबारों के समाचार तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायत की भी जनहित याचिका माना जाने लगा।
3. गरीबों, असहाय, असक्षम निरक्षर लोगों की शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए।
4. न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना।
5. न्यायपालिका से भी चूंक हो सकती है। व्यक्ति को सही न्याय प्राप्त हो।
6. न्यायपालिका रिट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करती है ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है।
7. उच्च न्यायलय रिट जारी कर सकती है।
   किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है उसे लागू होने से रोक सकती है।
8. (1) रिट जारी करने की शक्ति (2) न्यायिक पुनरावालोकन शक्ति
9. गरीब अमीर, स्त्री और पुरूष, अगडे और पिछड़े सभी वर्गों के लोगों पर एक समान कानून लागू हो।
10. – न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है।
    – मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायलय जो आदेश जारी करती है रिट कहलाती है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार पृच्छा उत्प्रेषण वर्णन।
2. (i) सरकार को छूट मिल जाती हैं
   (ii) अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है
   (iii) विधेयक में संशोधन कर सकती है
   (iv) समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा।
3. (i) महाभियोग द्वारा
   (ii) अयोग्यता का आरोप लगने पर
   (iii) विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित
   (iv) दोनो सदनों में बहुमत के बाद
4. (i) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा।

(ii) न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से

(iii) नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धान्त कहते हैं।

5. (i) उच्च न्यायालयो के निर्णय के विरूद्ध

(ii) उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कानूनी व्याख्या से सम्बन्धित

(iii) किसी अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदल कर पुनः फांसी की सजा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवा कर पुनः निरीक्षण कर सकता है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) डाक हडताल

(ii) जनता को सुविधा

(iii) सार्वजनिक हित से सम्बन्धित विभागों को हडताल नहीं करनी चाहिए।

(iv) लोगों की असुविध

(v) दैनिक आवश्यकताओं पर प्रभाव

3. (1) (i) शहर को सुन्दर बनाने हेतु

(ii) झुग्गियों को तोड़ने से रोकने वाले

(2) शहर का सुन्दर बनाकर पूंजी निवेश पर बल, दूसरा पक्ष जीवन के अधिकार की मांग

(3) जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देता, सफाइ का निर्देश दिया जाता ।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. सर्वोच्च
उच्च
जिला न्यायालय
अधिनस्थ

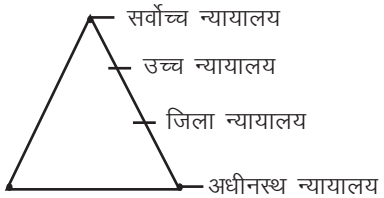

2. प्रारम्भिक (मौलिक, अपीलीय, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन)

3. किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर।

4. (i) न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना।
   (ii) विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाता।
   (iii) न्यायापलिका के पास समय का अभाव
   (iv) न्यायाधीशों की कमी।

5. (i) न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित
   (ii) अच्छा वेतन
   (iii) न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं
   (iv) दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना।
   (v) राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुंचाना
   (vi) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका का हस्तक्षेप नहीं।

6. मौलिक अधिकारों की रक्षक

   न्यायिक पुनरावलोकन

   न्यायिक सक्रियता

   सामाजिक एवं आर्थिक न्याय

   का महत्वपूर्ण निर्धारक

7. कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप, न्यायपालिका के इस कार्य के फलस्वरूप कार्यबोझ अवश्य बढ़ा है लेकिन न्यायपालिका संविधान की संरक्षक भी है।

8. न्यायपालिका महत्वपूर्ण स्तम्भ है, क्योंकि
   (a) लोकतान्त्रिक मूल्यों के संर्वद्धन में सहायक
   (b) सामाजिक आर्थिक न्याय को सुगम बनाना
   (c) मौलिक अधिकारों का संर्वद्धन
   (d) न्यायिक सक्रियता

अध्याय 6

संघवाद

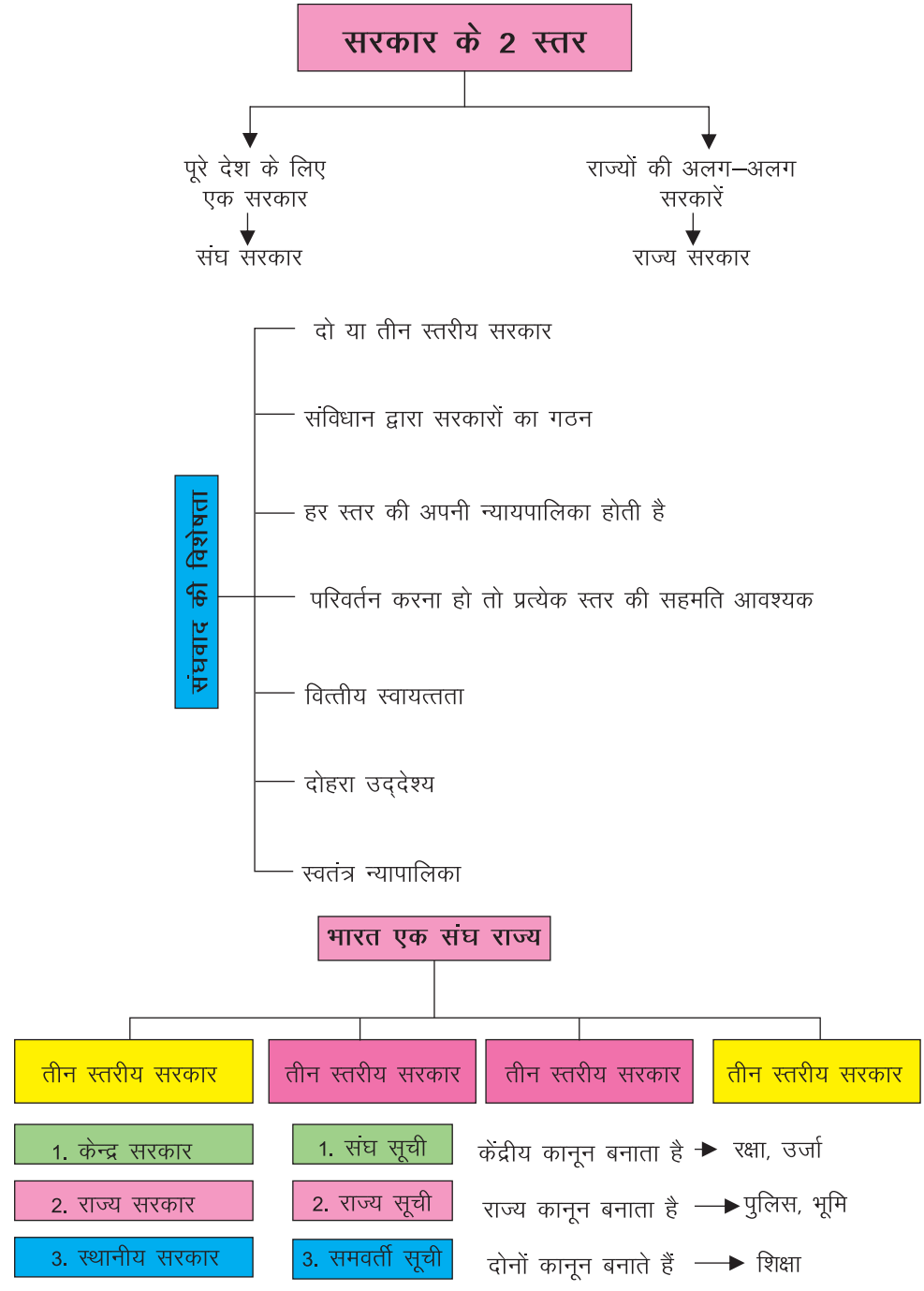

सरकार के 2 स्तर

- पूरे देश के लिए एक सरकार → संघ सरकार
- राज्यों की अलग–अलग सरकारें → राज्य सरकार

संघवाद की विशेषता

- दो या तीन स्तरीय सरकार
- संविधान द्वारा सरकारों का गठन
- हर स्तर की अपनी न्यायपालिका होती है
- परिवर्तन करना हो तो प्रत्येक स्तर की सहमति आवश्यक
- वित्तीय स्वायत्तता
- दोहरा उद्देश्य
- स्वतंत्र न्यापालिका

भारत एक संघ राज्य

तीन स्तरीय सरकार | तीन स्तरीय सरकार | तीन स्तरीय सरकार | तीन स्तरीय सरकार

1. केन्द्र सरकार	1. संघ सूची	केंद्रीय कानून बनाता है → रक्षा, उर्जा
2. राज्य सरकार	2. राज्य सूची	राज्य कानून बनाता है → पुलिस, भूमि
3. स्थानीय सरकार	3. समवर्ती सूची	दोनों कानून बनाते हैं → शिक्षा

अध्याय के मुख्य बिन्दु: संघवाद का अर्थ, भारतीय संघवाद की विशेषता भारतीय संविधान में संघात्मक लक्ष्ण, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, केन्द्र–राज्य संबंध।

संघवाद का अर्थ → संघवाद से आशय संगठित रहने के विचार से हैं (दो या दो से अधिक राज्यों के एक साथ संगठित रहने को ही संघवाद कहते हैं संघीय राज्य की सर्वप्रथम शुरूआत अमेरिका से हुई थी।

संघवाद एक संस्थागत प्रणाली हैं जिसमें दो प्रकार कि राजनीतिक व्यवस्था समाहित होती हैं इसमें एक केंद्रीय स्तर की और दूसरी प्रांतीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती हैं प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में स्वायत्त होती हैं।

केंद्रीय या संघीय सरकार का कार्यक्षेत्र पूरा देश होता हैं और उसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती हैं दूसरी और प्रांतीय सरकारों का कार्य क्षेत्र अपना प्रान्त होता हैं और राज्य सूची के विषयों पर ही ये कानून बनाते हैं केंद्र व राज्य के मध्य टकराव रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती हैं।

भारत में संघवाद

भारत के सर्विधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया हैं

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान अनेक नेता यह चाहते थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों या विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय स्तरों में बांटना जरूरी होगा भारतीय समाज में क्षेत्रीय व भाषायी विविधता हैं अतः प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए।

भारतीय संघवाद के अनुसार भारत में एक संघीय (केंद्रीय) सरकार, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अपने अपने विषयों पर कार्य करती हैं भारतीय

संविधान में सभी की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा दिया हुआ हैं

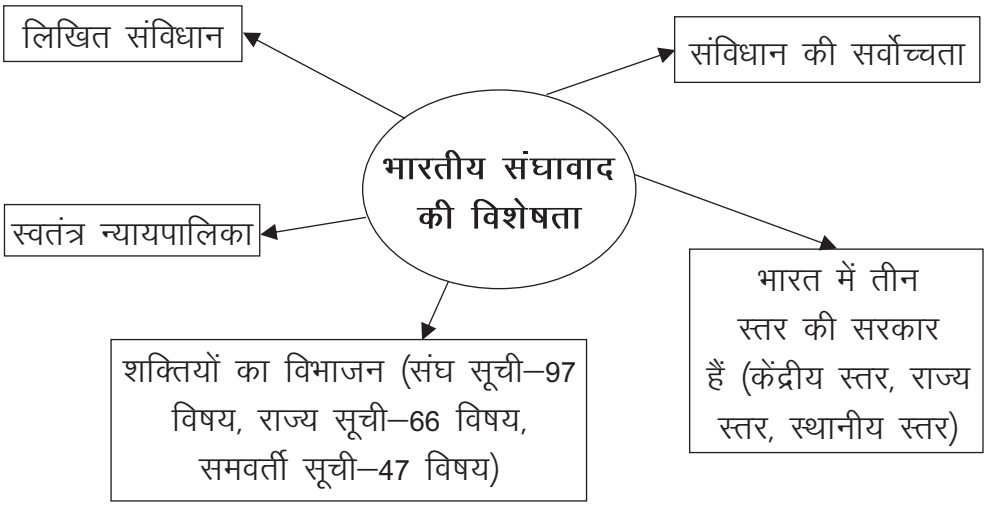

शक्ति विभाजन

भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों का वर्णन किया गया हैं पहली केंद्रीय सरकार जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण देश होता हैं दूसरी सरकार राज्य स्तर की सरकार होती हैं जिसका कार्यक्षेत्र केवल राज्य तक ही सीमित होता हैं दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इसके कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट वर्णन किया गया हैं

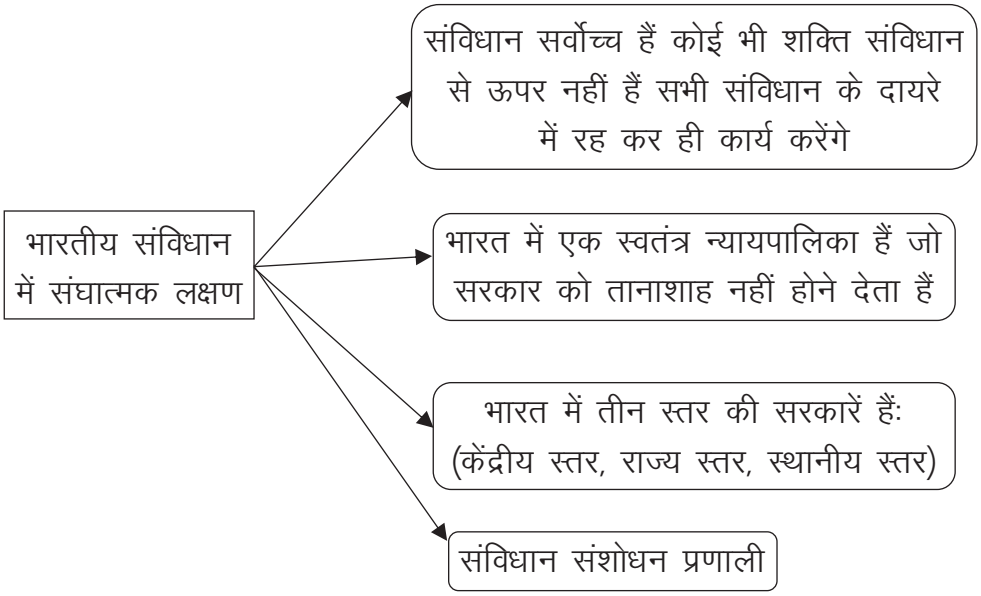

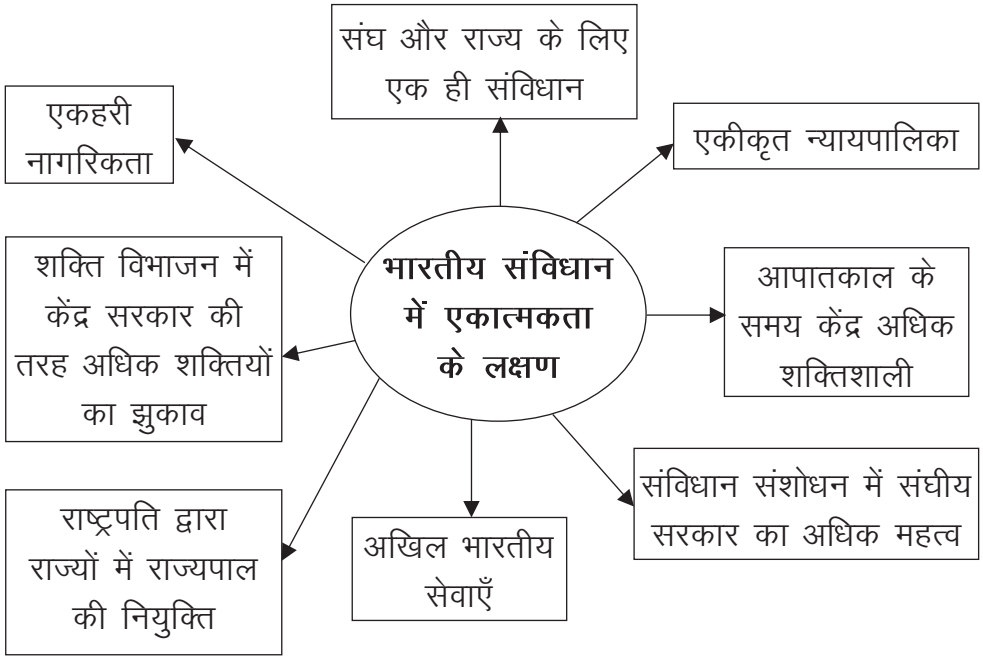

भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों?

भारत एक विशाल एवं विविधताओं से भारा हुआ देश हैं संविधान निर्माताआं को यह आशा थी कि इतने विशाल देश को सशक्त केंद्रीय सरकार द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता हैं देश में आजादी के समय 500 से अधिक देशी रियासतें थी जिनका विलय सक्त केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जा सका था।

भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव–

भारत के संविधान ने केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जबकि राज्यों में शासन चलाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं इस वजह से समय समय पर राज्य अधिक स्वायत्ता व शक्तियों की मांग करते रहते हैं इस वजह से केंद्र व राज्यों में तनाव व संघर्ष उत्पन्न होता हैं।

केन्द्र–राज्य संबंध

1. राज्य समय–समय पर केंद्र सरकार और अधिक अधिकारों व स्वायत्ता की मांग करते रहते हैं जो निम्न रूपों में हैं:

   (क) **वित्तीय स्वायत्ताः** राज्यों के आय के साधन सीमित हैं और संसाधनों पर नियंत्रण भी सीमित ही हैं अतः राज्य सरकार आय के मामलों में और अधिक स्वायत्ता की मांग करते रहते हैं।

(ख) **प्रशासनिक स्वायत्ताः** राज्य सरकार दैनिक प्रशासन के मामलों में और अधिक स्वायत्ता चाहते हैं राज्य केंद्र सरकार से और अधिकार व शक्तियां चाहते हैं।

(ग) **सांस्कृतिक और भाषाई मुद्देः** काफी राज्य हिंदी भाषा का विरोध करते हैं तथा उनके राज्य में प्रचलित भाषा को ही प्रोत्साहन देते हैं।

2. राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासनः

(क) राष्ट्रपति राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर देता हैं जो राज्यों के दैनिक कार्यों में कई बार अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं।

(ख) केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव डालकर राज्यों में अनुच्छेद 356 के माध्यम से अनुचित राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।

3. नए राज्यों की मांगः भारतीय संघीय व्यवस्था में समय–समय पर नवीन राज्यों की मांग उठती रहती हैं जिसे राजनैतिक कारणों से संघ व राज्यों में तनाव बढ़ता है।

4. अन्तर्राज्यीय विवादः

(क) संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद होता रहता हैं जैसे बेलगांव को लेकर कर्नाटक व महाराष्ट्र में सीमा विवाद।

(ख) दो या दो से अधिक राज्यों में नदियों के पानी के बंटवारें को लेकर विवाद होता रहता हैं, जैसे–कर्नाटक व तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है।

5. **विशिष्ट प्रावधानः** संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 (झ) तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशेष दर्जा दिया गया हैं।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है?

   (i) दोहरी नागरिकता

   (ii) बहु नागरिकता

   (iii) एकल नागरिकता

   (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. केन्द्र–राज्य संबंधी की समीक्षा के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया था?

   (i) शाह आयोग

   (ii) सरकारिया आयोग

   (iii) गोस्वामी आयोग

   (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है?

   (i) मुख्यमंत्री

   (ii) प्रधानमंत्री

   (iii) उच्च न्यायालय

   (iv) राज्यपाल

4. अन्तर्राज्यीय विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास है?

   (i) राज्यपाल

   (ii) संसद

   (iii) सुप्रीम कोर्ट

   (iv) राष्ट्रपति

अभिकथन और कारण प्रश्न

1. दावा (ए): भारत के राज्यों का किसी भी समय विलय किया जा सकता है।

   कारण (R): संसद के पास भारत राज्यों का विलय करने की शक्ति है।

   (ए) ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है।

   (बी) ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है

   (सी) ए सच है, लेकिन आर गलत है।

   (डी) ए गलत है, लेकिन आर सच है।

2. अभिकथन (A): भारत में सरकार के तीन स्तर हैं।

   कारण (R): भारत में संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है

   (ए) ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है

   (बी) ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है

   (सी) ए सच है, लेकिन आर गलत है

   (डी) ए गलत है, लेकिन आर सच है।

प्रश्न संख्या 1 से 5 में खाली स्थान भरिए:

1. भारतीय संविधान में संघवाद के लिए ..... शब्द का प्रयोग किया गया है।
2. संघवाद का अर्थ ..... हैं।
3. केंद्र व राज्यों के मध्ये उठे विवादों का समाधान ..... द्वारा किया जाता है।
4. समवर्ती सूची पर कानून बनानें का अधिकार ..... हैं।
5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अनुच्छेद ..... के अंतर्गत होता हैं।

प्रश्न संख्या 6 से 10 के उत्तर 20 शब्दों में दीजिए

6. भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया?

7. सरकारिया आयोग कब बनाया गया?

8. अनुच्छेद 371 से संबंधित किसी एक राज्य का नाम लिखो?

9. राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ?

10. स्वायत्ता का क्या अर्थ होता है?

प्रश्न संख्या 11 से 15 में सही या गलत वाक्य पहचानों

11. जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हैं।

12. विश्व में संघवाद सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था।

13. भारत के संविधान में केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्यों को अधिक अधिकार दिए हुए हैं।

14. संसद भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती हैं।

15. भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान हैं।

दो अंकीय प्रश्नः–

1. मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया?
2. संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई?
3. अनुच्छेद–1 क्या दर्शाता है?
4. शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है?
5. अवशिष्ट शक्तियां कौन–सी है?
6. राज्य स्वायतता की मांग किस आधार पर करते है?
7. सरकारिया आयोग में मुख्य प्रावधान क्या रखा गया है?
8. अर्न्तराज्यीय विवादो के दो उदाहरण दीजिए।
9. सरकारिया आयोग कब व किसके द्वारा गठित किया गया।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. ज्यादा स्वायतता की चाह में प्रदेशों ने कौन–कौन सी मांग उठाई?

2. भारतीय संविधान की चार संघात्मक विशेषताएं बताइये?

3. भारत संविधान की चार एकात्मक विशेषताएं लिखे?

4. बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं है?

5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए।

6. राज्यपाल की भूमिका केन्द्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं फिर राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा होती है अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यो में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

1. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
2. राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है।
3. राज्यपाल किसका एजेण्ट होता है।
4. राज्य का प्रमुख कौन होता है।

5. दिए गए अवतरण को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो–

जहाँ एक ओर राज्य अधिक स्वायतता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केन्द्र के साथ विवाद की स्थिति में रहते है, वही दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में सीमाओं से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते है। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते है अतः इनका सर्वोतम समाधान केवल विचार–विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।

(i) केन्द्र तथा राज्य में किस कारण से विवाद रहता है?

(A) आपातकाल के लिए (B) वित्त को लेकर

(C) भाषा को लेकर (D) धर्म को लेकर

(ii) राज्यों में आपसी विवाद का कोई एक कारण बताइए–

(A) सीमा को लेकर (B) जाति को लेकर

(C) धर्म के कारण (D) वित्त के कारण

(iii) कानूनी विवादों का कौन हल कर सकता है?

(A) संसद (B) राष्ट्रपति

(C) प्रधान मंत्री (D) न्यायपालिका

(iv) जल विवाद को कौन हल करता है?

(A) राज्य (B) संसद

(C) राष्ट्रपति (D) न्यायपालिका

6. कार्टून का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देः–

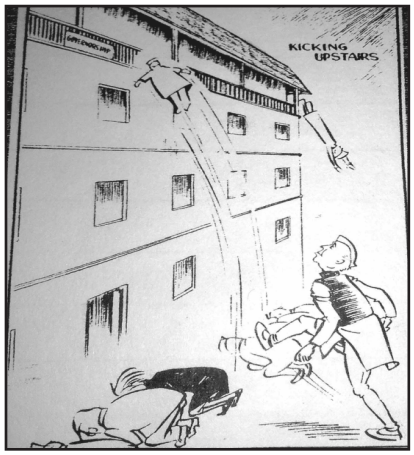

(i) राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

(A) प्रधानमंत्री (B) राष्ट्रपति

(C) संसद (D) मुख्यमंत्री

(ii) कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है?

(A) राष्ट्रपति की मर्जी (B) परीक्षा के द्वारा

(C) योग्यता आधारित (D) चुनाव द्वारा

(iii) क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है?

(A) हाँ (B) नहीं

(C) कभी–कभी (D) कभी नहीं

(iv) राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है?

(A) 5 वर्ष (B) 6 वर्ष

(C) 8 वर्ष (D) 4 वर्ष

7. मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें और पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दें–

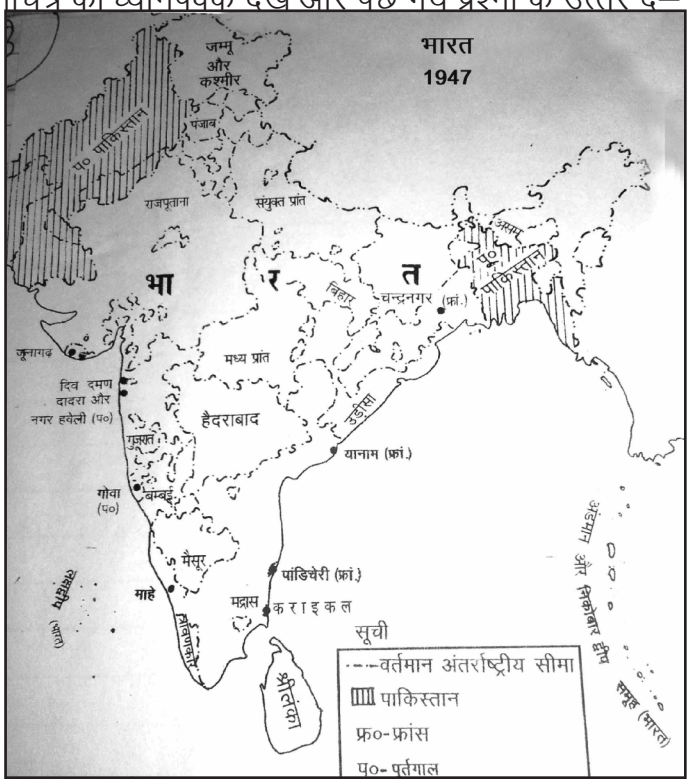

(i) भारत के मानचित्र में दो रियासतों के नाम लिखों–

(A) भोपाल, त्रावणकोर (B) जयपुर, राजस्थान

(C) चंडीगढ़, हरियाणा (D) पंजाब, हिमाचल

(ii) दो राज्यों के नाम लिखो जिनका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ है?

(A) हिमाचल, मैसूर (B) मद्रास, मैसूर

(C) हिमाचल, जम्मू (D) उत्तराखण्ड, झारखण्ड

(iii) एक गैर हिन्दी भाषी राज्यों का नाम लिखो–

(A) आन्ध्रप्रदेश (B) हरियाणा

(C) पंजाब (D) हिमाचल

(iv) भारत की एक रियासत जिसका विलय 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ

(A) दिल्ली (B) जम्मू एवं कश्मीर

(C) जयपुर (D) बिकानेर

(v) भारत की एक रियासत जिसमें सैन्य कार्यवाही द्वारा विलय हुआ–

(A) हैदराबाद (B) जूनागढ़

(C) पंजाब (D) हरियाणा

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संवधिान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक इसकी आत्मा है।
2. संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन करो।
3. स्वायतता और अलगाववाद का क्या अर्थ है।

उत्तरमाला

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. (iii) एकल नागरिकता
2. (ii) सरकारिया आयोग
3. (iv) राज्यपाल
4. (iii) सुप्रीम कोर्ट

अभिकथन और कारण उत्तरः

1. A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है
2. A सत्य है, परन्तु R असत्य है।
1. यूनियन
2. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं
3. उच्चतम न्यायालय / न्यायपालिका
4. केंद्र व राज्य दोनों को
5. 356
6. अत्याधिक विविधता एवं विशाल जनसंख्या के कारण
7. 1983
8. मणिपुर
9. 1954
10. स्वयं का शासन
11. गलत
12. सही
13. गलत
14. सही
15. गलत

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. कर्नाटक, तमिलनाडु
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारो का अपना क्षेत्र अधिकार।
3. भारत राज्यों और केन्द्र प्रशासित राज्यों का एक संघ (यूनियन) है।
4. (i) कार्यपालिका की शक्तियों का बँटवारा, विधानपालिका, न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है।
   (ii) संघ, राज्य, समवर्ती सूची में अपने विषय है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार बनाता है
5. वे विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में नही दिया गया।
6. राज्य स्वायतता की मांग भाषा, आय, वित्तीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति।
7. केन्द्र, राज्य, सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर।
8. सीमा विवाद नदी जल बंटवारा विवाद, जैसे– पंजाब, हरियाणा।
9. जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया द्वारा।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. – नदी जल बंटवारा
   – सीमा विवाद, नए राज्यों की मांग
   – आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता, संसाधनों पर अधिकार

2. (i) शक्तियों का विभाजन
   (ii) स्वतंत्र न्यायपालिका
   (iii) द्विसदनीय विधायिका
   (iv) संविधान

3. (i) इकहरी नागरिकता
   (ii) केन्द्र के पास अधिक सर्वोच्चता
   (iii) एकीकृत न्यायपालिका
   (iv) आर्थिक दृष्टि से भी राज्य दुर्बल।

4. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, केन्द्र सरकार के लिए कार्य राष्ट्रपति शासन लगवाने का अधिकार, विधेयक को कानून बनाने पर विवाद, केन्द्र के ऐजेन्ट के रूप में कार्य।

5. अनुच्छेद 356, राज्य में आन्तरिक शांति भंग होने पर सरकार के पास बहुमत न रहने पर आर्थिक संकट आने पर।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) वित्तीय, कानून बनाने के विषय, आपातकाल की शक्ति
   (ii) नदी जल वितरण विवाद
   (iii) न्यायपालिका, विचार विमर्श, पारस्परिक विश्वास

2. – राष्ट्रपति के द्वारा
   – जब चाहे जिसे राज्यपाल बना दे, जब चाहे हटा दे, या दूसरे स्थान पर भेंज दे।
   – हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तथा केन्द्र सरकार की इच्छा से की जाती हैं

3. (i) भोपाल, त्रावणकोर
   (ii) उतराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना
   (iii) आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक (कोई एक)

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. इकहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्यों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग आदि।

2. (i) संघ सूची – राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इसमें लगभग 99 विषय हैं, जैसे– रक्षा, विदेष, रेल, बन्दरगाह, बैंक, खनिज आदि।
   (ii) राज्य सूची – साधारणतय क्षेत्रिय महत्त्व के विषय लगभग 66 विषय है, जैसे– पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि।
   (iii) समवर्ती सूची – लगभग 47/52 है, जैसे– फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि।

3. (i) स्वायतता अधिक अधिकार प्राप्त करना, अलगाववाद–केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार
   (ii) राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप न करना।
   (iii) अलगाववाद ने केन्द्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता न देना, विकास संबंधी योजनाएं न बनाना।

अध्याय 7

स्थानीय शासन

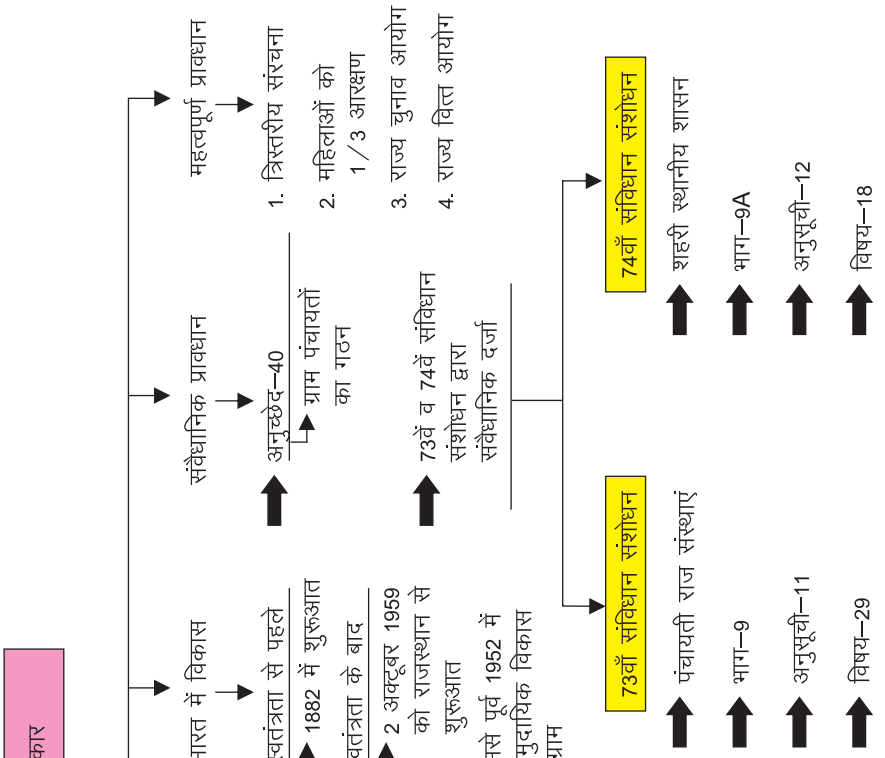

मुख्य बिन्दुः

हमें स्थानीय सरकार की आवयश्कता क्यों?

भारत में स्थानीय सरकार का विकास?

73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन।

73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन का क्रियान्वयन (Implementation) और चुनौतियां)

– **स्थानीय शासनः** गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते है। यह आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।

– **लोकतंत्र का अर्थ है** सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए।

– आम जनता राज्य, सरकार या केन्द्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है।

केन्द्रीय सरकार
↓
राज्य सरकार
↓
स्थानीय सरकार
↓

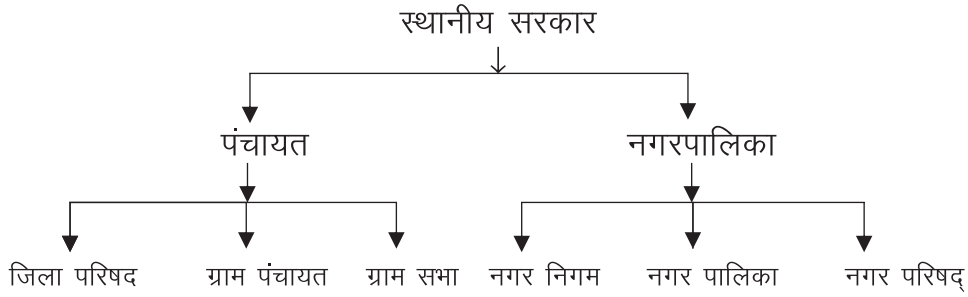

- हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों?
- मजबूत लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम करने के लिये।
- स्थानीय स्तर की राजनीतिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु।
- सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधियों तक पहुंच हेतु।
- कार्य को सफल व तीव्र गति से करने हेतु (जन कल्याणकारी कार्य)
- आपसी सामन्जस्य व सफल प्रशासन हेतु।
- **भारत में स्थानीय शासन का विकासः** प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय, ''सभा'' के रूप में मैजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद आस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें ''मुकामी बोर्ड'' कहा जाता था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतो में ग्रम पंचायते बनी।

  जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है।

महात्मा गांधी जी ने भी ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने व सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात की व इसको एक कारगर साधन बताया।

- **स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासनः** संविधान के 73 वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम'' इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत 1959 की सिफारिश की गई। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। सन् 1987 के बाद

स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरूआत हुई।

- सन् 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।
- ब्राजील के संविधान में प्रांत संघीय जिले तथा नगरपालिका परिषद् की व्यवस्था है।
- संविधान का 73वां और 74 वां संशोधनः सन् 1992 में ससंद ने 73वां और 74 वां संविधान संशोधन पारित किया।
- 73वां संवैधानिक संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।
- 73वां संशोधन– 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानः–

(1) **त्रि–स्तरीय ढांचाः** अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रि–स्तरीय ढांचा है।

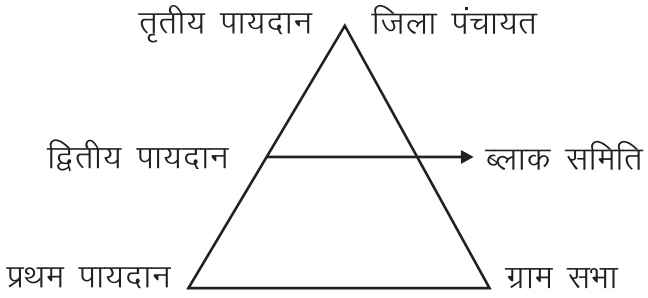

(2) **चुनावः** पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि पांच साल की होती है।

(3) **आरक्षणः**

- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।
- यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) को भी सीट में आरक्षण दे सकती है।

इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही है।

- भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73 वें संविधान के प्रावधानों से दूर रखा गया परन्तु सन् 1996 में एक अलग कानून बना कर पंचायती राज के प्रावधानों में, इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया।
- **राज्य चुनाव आयुक्तः** प्रदेशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी।
- **राज्य वित्त आयोगः** प्रदेशों की सरकार के लिए जरुरी है कि वो हर पांच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनायें। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शायन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा।
- **74वां संशोधनः** 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से है अर्थात् नगरपालिका से।

  शहरी इलाकाः (1) ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो (2) कामकाजी पुरूषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो (3) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

  विशेषः अनेक रूपों में 74 वें संविधान संशोधन में 73वे संशोधन का दोहराव है लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 73 वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74 वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं।

  73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयनः (1994–2020) इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव अनेकों बार हो चुके है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर भारी बढोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आत्म विश्वास में काफी वृद्धि हुई है।
- **विषयों का स्थानांतरणः** संविधान के संशोधन ने 29 विषय को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतो से संबंधित है।

स्थानीय शासन के विषय–

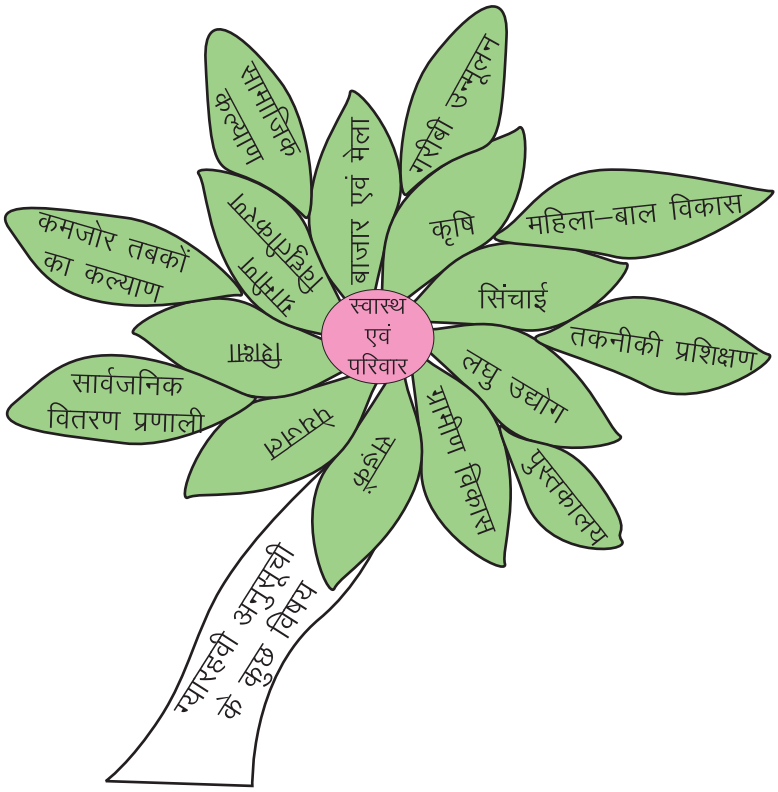

स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं–

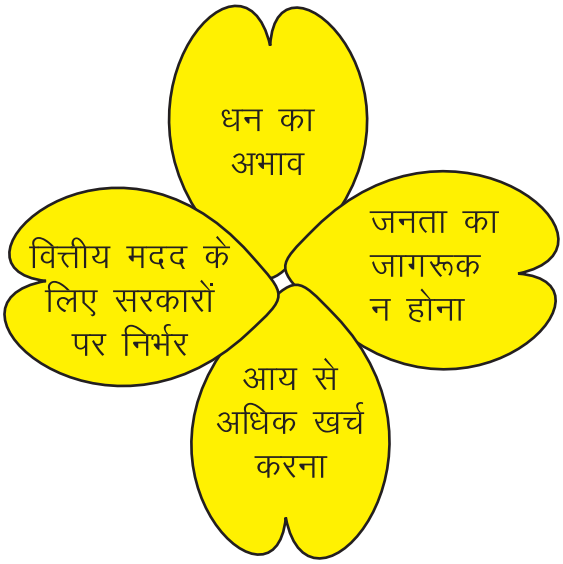

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत किस राज्य से हुई ?

   (अ) आन्ध्रप्रदेश (ब) राजस्थान

   (स) बिहार (द) उड़िसा

2. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता हैं?

   (अ) 10 अप्रेल (ब) 14 अप्रेल

   (स) 24 अप्रेल (द) 20 अप्रेल

3. पंचायती राज से सम्बन्धित कौनसा अनुच्छेद है?

   (अ) अनुच्छेद 243 (ब) अनुच्छेद 324

   (स) अनुच्छेद 124 (द) अनुच्छेद 73

4. पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?

   (अ) कृषि उत्पादन में वृद्वि

   (ब) प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

   (स) आर्थिक विकास

   (द) लोगों को राजनितिक रूप से जागरूक करना

5. भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई?

   (अ) कलकत्ता (ब) मृदास

   (स) बोम्बे (द) दिल्ली

6. शहरी स्थानीय शासन से सम्बन्धित कौनसा संविधान संशोधन है?

   (अ) 73 वाँ (ब) 74 वाँ

   (स) 92 वाँ (द) उपर्युक्त में कोई नहीं

7. निम्नलिखित में से किस राज्य में पचायती राज संस्थाएं नहीं है।

(अ) नागालैण्ड (ब) राजस्थान

(ब) बिहार (द) तमिलनाडू

8. जिला परिषद व ग्राम पंचायत के मध्य निम्नलिखित में से क्या स्थित है?

(अ) मण्डल पंचायत (ब) ब्लॉक समीति

(स) ग्राम सभा (द) उपर्युक्त सभी

9. निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है?

(अ) ग्राम पंचायत (ब) ब्लॉक पंचायत

(स) A व B दोनों (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

10. निम्नलिखित कथनों में कौनसा कथन सही है?

(अ) ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है।

(ब) पंचायत समीति की अध्यक्षता चैयरमैन द्वारा की जाती है

(स) जिला परिषद की अध्यक्षता चैयरमैन द्वारा की जाती है।

(द) सरपंच व चैयरमैन का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है।

11. ग्राम पंचायतों के आय स्रोतों में निम्नलिखित में कौनसा नहीं है?

(अ) सरकारी किराया (ब) घरेलू कर

(ब) आय कर (द) भूमि पर स्थानीय कर

12. किस समूह के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण का प्रावधान है?

(अ) अन्य पिछडे वर्ग (ब) अनुसूचित जाति

(स) अनूसूचित जनजाति (द) महिला

13. पचांयती राज चुनावों में भाग लेने के लिए कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है?

(अ) 21 वर्ष (ब) 18 वर्ष

(स) 25 वर्ष (द) 30 वर्ष

14. 73 वाँ संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव किस राज्य में सर्वप्रथम हुए?

(अ) आन्ध्र प्रदेश (ब) राजस्थान

(स) मध्य प्रदेश (द) कर्नाटक

15. पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य स्त्रोत क्या है?

(अ) स्वैच्छिक अनुदान (ब) सम्पति का

(स) स्थानिय का (द) सरकारी अनुदान

16. 73 वाँ संविधान संशोधन से संविधान में कौनसी अनुसूची शामिल की गई ?

(अ) 6 वीं (ब) 7 वीं

(स) 9 वीं (द) 11 वीं

17. स्थानीय सरकार के विकास में निन्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?

(अ) विलियम बैंटिक (ब) लॉर्ड रिपन

(स) लॉर्ड डफरिन (द) लॉर्ड मेमो

18. 1989 में पी. के चुंगन समीति ने निम्नलिखित में से किसे संवेधानिक दर्जा देने की सिफारिस की?

(अ) स्थानीय शासन (ब) चुनाव आयोग

(स) लोकपाल (द) वित्त आयोग

19. स्थानीय शासन कौनसे स्तर पर कार्य नहीं करता?

(अ) राज्य स्तर (ब) जिला स्तर

(स) ब्लॉक स्तर (द) ग्राम स्तर

20. स्थानीय स्वशासन का प्रमुख उदेश्य क्या हैं?

(अ) राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढाना

(ब) लोगों को वित्त उपलब्ध कराना

(स) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

(द) (अ) तथा (स) दोनों

एक अंकीय प्रश्नः–

1. स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की तथा कब? सही विकल्प चुनें।
   (क) पंचायत समिति, 1979 (ख) ग्राम समिति 1969
   (ग) भुंगन समिति, 1989 (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. स्थानीय शासन की विचारधारा का विचार किस देश से ग्रहण किया गया।
3. संविधान का 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया?
4. स्थानीय शासन संविधान की ..... सूची का विषय है?
5. त्रिस्तरीय ढांचे से क्या अभिप्राय है?
6. ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है?
7. ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते है?
8. पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए ..... प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है?
9. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार पंचायतों को दे सकती है? सही विकल्प चुनें।
   (क) अनुच्छेद 243 (ख) अनुच्छेद 143
   (ग) अनुच्छेद 75 (ग) अनुच्छेद 150
10. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? सही विकल्प चुनें।
    (क) मुख्य चुनाव आयुक्त (ख) प्रधानमंत्री
    (ख) सरपंच (घ) राज्य के चुनाव आयुक्त
11. नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु ..... होनी चाहिए।
12. निम्नलिखित को सही करके लिखिये।
    (i) 73वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्धन केन्द्र के स्थानीय शासन से जुड़ा है।
    (ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए उनकी मांग के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।
    (iii) 74वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है।

13. **'सही' व 'गलत' का चयन करें:**

(i) कृषि व सिंचाई ग्यारहवीं अनुसूची के विषय हैं (.....)

(ii) शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण ग्यारहवी अनुसूची के विषय में नहीं आते। (.....)

(iii) सभी प्रदेशों व पंचायती राज व्यवस्था में त्रि–स्तरीय ढांचा हैं (.....)

(iv) धन अभाव स्थानीय शासन के समक्ष एक समस्या है। (.....)

दो अंकीय प्रश्नः–

1. भारत में स्थानीय शासन के अधिक मजबूत न होने के दो कारण लिखिए।
2. ''शहरी इलाका'' शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. ग्राम पंचायतों के क्या–क्या कार्य हैं? किन्हीं दो का उल्लेख करो।
4. पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? स्पष्ट करो।
5. स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ हुए है?
6. स्थानीय शासन अपना कार्य उतनी दक्षता से नहीं कर पाता, जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी? क्यों?
7. राज्य का वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या है?
8. अभी हाल में नगर निगम के कुछ रिक्त स्थानों पर चुनाव हुए हैं आप के विचार से ये चुनाव कराए जाने का क्या कारण रहा होगा?
9. पंचायती निकायों की व्यवस्था हमारे देश में प्राचीनकाल में भी थी। वर्तमान समय में इनकी कार्यप्रणाली में क्या सुधार हुए हैं?
10. नगर – निगम का मुखिया क्या कहलाता है? इसका कार्य काल लिखें।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. स्थानीय शासन का क्या महत्व है?
2. नगर निगम तथा नगरपालिकाओं के चार कार्य लिखें।
3. मेयर कौन होता है?
4. इस समय दिल्ली में कितने नगर निगम हैं? इतने निगमों के बनाए जाने का क्या कारण है?

5. नगर निगम आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में कहां तक सफल रहे है?

6. पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन–कौन सी समस्याएं है?

7. ''स्थानीय संस्थाएं स्वायत्त नहीं है इसीलिए यह कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पाती'' आपके विचार से क्या यह कथन सत्य है? कैसे?

8. ''लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है'' इस कथन को स्पष्ट करें

9. ''स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरूष सत्तात्मक समाज ले रहा हैं''? क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क दीजिए।

10. जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव का होना तय है? क्या आप इस विचार से सहमत है? स्पष्ट करें।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. ''गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कारगर साधन है। विकास के हर पहलू में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो सके। समूचे भारत की आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर राज्य एक गणराज्य होगा।''

   (क) ''सत्ता के विकेन्द्रीकरण'' से क्या अभिप्राय है?

   (ख) गणराज्य से क्या अभिप्राय है?

   (A) राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाना

   (B) राज्य का मुखिया का चयन वंशानुगत होना

   (C) शासन में जनता की भागीदारी होना

   (D) उपरोक्त सभी

   (ग) पंचायतों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? कोई दो सुझाव दीजिए।

(घ) ''आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए'' इस कथन से क्या अभिपाय है?

पाँच अंकीय प्रश्नः–

चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें–

पाठ्यपुस्तक
पृष्ठ संख्या 188

(1) इस चित्र में जो लिखा है उससे आप क्या समझ पा रहे है?

(2) स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? कैसे?

(3) इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

छः अंक के प्रश्न–

1. स्थानीय शासन से क्या अभिपाय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2. पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यदि आप जिला कलैक्टर होते तो आप गांवों की किन–किन समस्याओं का समाधान करते?
3. यदि स्थानीय निकाय न होते तो नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान हो पाता या नहीं? क्यो?
4. नगर निगम को आय कहां से प्राप्त होती है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? क्यों?
5. यदि आप अपने गांव की सरपंच होतीं तो समाज आपके कार्यों में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता? तब आप उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पातीं?

उत्तरमाला

बहुविकल्पीय प्रश्नः—

1. B, राजस्थान
2. C, 24 अप्रेल
3. A, अनुच्छेद 243
4. B लोगों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना
5. B मद्रास
6. A, 73वां संविधान संशोधन
7. A, नागालैण्ड
8. B, ब्लॉक समिति
9. A, ग्राम पंचायत
10. A, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है
11. D, स्थानीय भूमिकर
12. D, महिला
13. A, 21 वर्ष
14. A, आन्ध्रप्रदेश
15. D सरकारी अनुदान
16. D, 11वीं अनुसूची
17. D, लॉर्ड मेयो
18. A, राज्य स्तर
19. D, A तथा C दोनों

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. थुंगन समिति, 1989
2. ब्राजील
3. 1992, 1993
4. राज्य सूची
5. ग्राम पंचायते निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद ऊपरी स्तर पर

6. वे सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं।

7. 5 वर्षों

8. 1 तिहाई

9. अनुच्छेद 243

10. राज्य के चुनाव आयुक्त

11. 21 वर्ष

12. (i) 73वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है।
(ii) 74वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।

13. (i) सही
(ii) गलत
(iii) सही
(iv) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. जातिवाद, गुटबाजी, सांप्रदायिकता

2. (i) जनसंख्या कम से कम 5000, (ii) 75% से अधिक कामकाजी पुरूष खेती बाडी से अलग काम करते हो, (iii) जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

3. सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण आदि।

4. आज अनेकों महिलाएं सरपंच तथा मेयर जैसे पदों पर आसीन है उनमें पहले से ज्यादा शक्ति तथा आत्मविश्वास आया है। महिलाओं की राजनीतिक समझ में वृद्धि हुई है।

5. नागरिकों की समस्याओं के समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाते है। नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है।

6. धन का अभाव रहता है। आय के अनुपात में खर्च अधिक है इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।

7. 5 वर्ष के लिये स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना।

8. ये स्थान कई कारणों से रिक्त हुए होंगे।
   – किसी निगम पार्षद की मृत्यु के कारण
   – किसी निगम पार्षद का दल बदल लेने के कारण
   – किसी निगम पार्षद का विधायक बन जाने के कारण

9. प्राचीनकाल में भी स्थानीय संस्थाएं थी परन्तु वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। आज ये संस्थाएं अधिक उत्तरदायी है और जनता के प्रति जवाबदेह भी।

10. मेयर या महापौर, 1 वर्ष

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते है तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाती है।

2. सफाई का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, पेयजल की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सड़कों का निर्माण व मरम्मत, शमशान घाटों की व्यवस्था आदि।

3. नगर निगम के सदस्यों का मुखिया होता है।

4. इस समय दिल्ली में तीन नगर निगम है, उत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनकी समस्याएं भी। एक नगर निगम सबकी समस्याओं का समाधान उतनी कुशलता से नहीं कर पा रहा था जितना तीन नगर निगम कर पा रहें हैं।

5. नगर निगम जनता की समस्याओं का समाधान उस हद तक नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। आज भी सड़कें टूटी रहती हैं कूड़े के ढेर जगह–जगह देखे जा सकते हैं। पानी, बिजली की समस्या का समाधान किया जा चुका है परंतु फिर भी गर्मी के दिनों में इन दोनों से ही आम नागरिकों को जूझना पड़ता है।

6. धन की समस्या, जनता का जागरूक न होना, राजनीतिक हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होना,।

7. हाँ, यदि ये संस्थाएं स्वायत्त हो जाएं तो नागरिकों की समस्याएं जल्दी सुलझेंगी और ये संस्थाएं जनता के प्रति उत्तरदायी भी होंगी।

8. नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की सार्थक भागीदारी कर सकता है। तभी सरकार जवाबदेह होगी।

9. अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं या महिला को पद पर आसीन करा कर परिवार का मुखिया या पुरूष उसके बहाने फैसले लेता रहता है।

10. हाँ, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को संविधान ने अनिवार्य बना दिया था इसके साथ ही, अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। इससे स्थाानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए। कभी–कभी इससे तनाव पैदा होता है और सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है।

चार अंकीय प्रश्न का उत्तरः–

1. (क) सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अर्थ है सत्ता जनता तक पहुंचे जैसे गांधी जी चाहते थे कि ग्रामोदय की विचारधारा सत्ता की विकेन्द्रीकरण है। स्थानीय स्तर की समस्याएं स्थानीय स्तर पर सुलझ जाएं।

   (ख) गणराज्य से अभिप्राय है जहां राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है यदि स्थानीय शासन को स्थानीय जनता तक पहुंचाया जाएगा तो हर ग्राम एक गणराज्य बन जाएगा।

   (ग) – उन्हें धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

   – जनता को जागरूक होना चाहिए।

   (घ) इसका अर्थ है समस्याओं के समाधान स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो सकें। आम जनता की पहुँच वहाँ तक है।

पांच अंकीय प्रश्न का उत्तरः–

1. (क) इसक अर्थ है ये हमारा गांव है और इसमें हमारा राज होना चाहिए।

   (ख) हां, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं का समाधान अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्याओं से अवगत होते हैं।

(ग) कभी–कभी धन की समस्या, सरकार का हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः–

1. स्थानीय शासन स्थानीय मामलों की देखभाल करती है नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। इससे नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है।
2. गांवों के स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। इसके तीन स्तर है। (छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा)
3. छात्र अपने विवेक से उत्तर देगा।
4. नगर निगम बहुत से कर लगाता है जैसे गृहकर, जल कर, साप्ताहिक बाजारो में सामान बेचने वालों पर कर, आदि राज्यों से अनुदान प्राप्त करके भी नगर निगम धन प्राप्त करते हैं। नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है।
5. छात्र अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय 8

राजनीतिक सिद्धांत

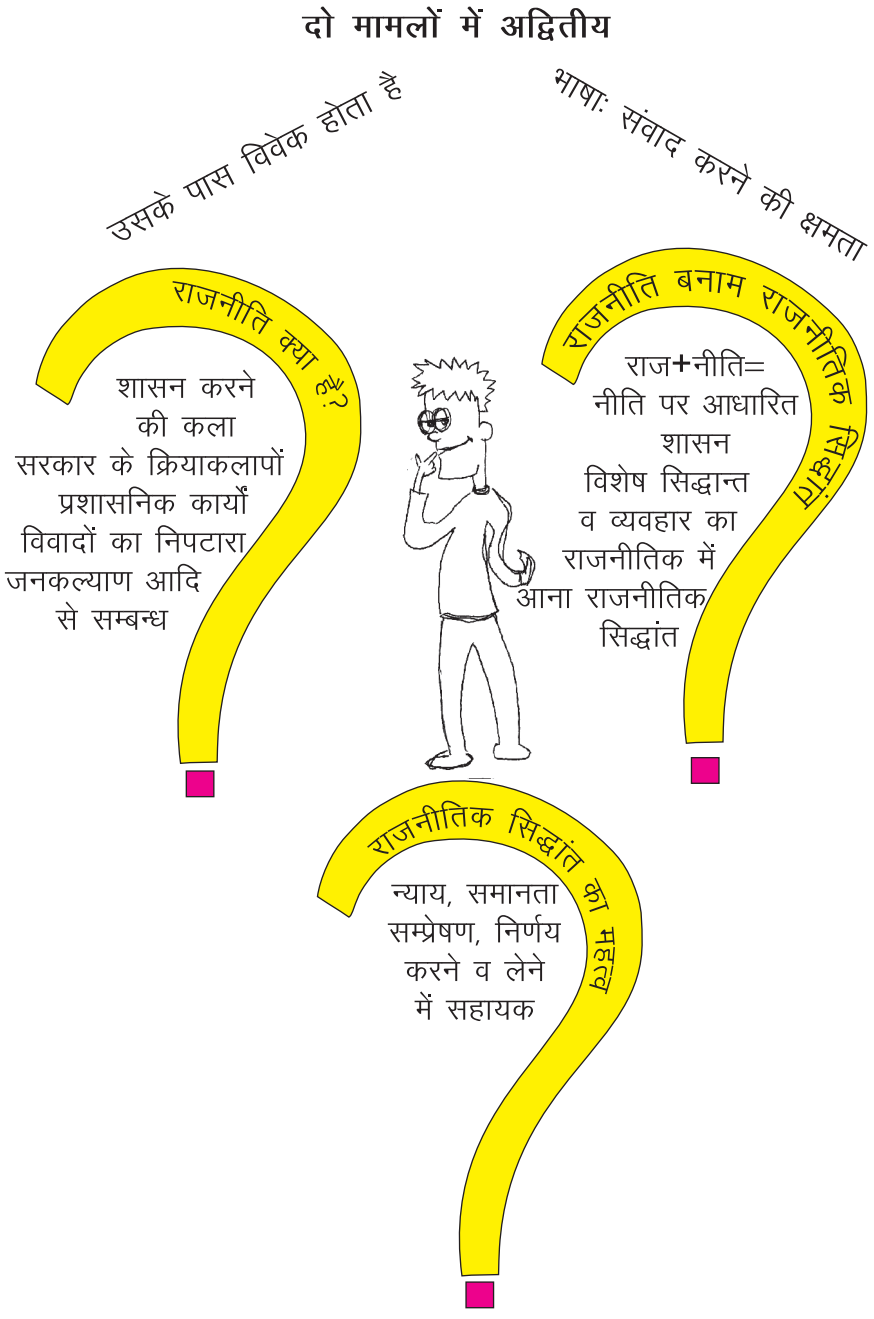

मुख्य बिन्दुः

– राजनीतिक क्या है?

– राजनीतिक में हम क्या पढ़ते हैं?

– राजनीतिक सिद्धान्तों को व्यवहार में उतारना।

– हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?

– राजनीति बनाम राजनीति सिद्धांत।

– राजनीति सिद्धांत का महत्त्व।

राजनीति क्या है?

– राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग–अलग मत है। सामान्य तौर पर–

(i) राजनीति शासन करने की कला है।

(ii) राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है।

(iii) राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है।

(iv) राजनीति भागीदारी करना सिखाती है लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है, आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है।

(v) जनकल्याण से इसका सम्बन्ध है।

(vi) राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण व अविभाज्य अंग है।

राजनीतिक सिद्धान्त में हम क्या पढ़ते है?

– राजनीतिक सिद्धान्त में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते है जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष आदि।

– निश्चित मूल्यों व सिद्धान्तों को पढ़ते है जिनके द्वारा नीतियां निर्देशित होती है।

राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना–

– राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहा, राजनीतिक सिद्धांतों

जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग कर, इन्हें अपनाना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते है, हम यह समझ सकते है कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते है, राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है यह मनुष्य से संबधित है उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है अतः हम कह सकते है कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है।

हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?

1. भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए।
2. बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए।
3. एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए।
4. मत देने के लिए।
5. समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए।
6. आन्दोलनों को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए।
7. वाद–विवाद, तर्क–वितर्क, लाभ–हानि का आंकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए।
8. शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए।
9. नीति बनाने के लिए।
10. लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने हेतु।
11. अधिकार एंव कर्त्तव्यों को समझने के लिए।
12. भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए।
13. अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।
14. विभिन्न शासन प्रणालियों के अध्ययन हेतु।
15. एक छात्र होने के नाते।

राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत

राजनीति व राजनीतिक सिद्धान्त दो अलग–अलग धारणाएं है।

राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राज + नीति अर्थात नीति पर आधारित शासन, नागरिक या व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष सिद्धांत अथवा व्यवहार का प्रयोग राजनीत के अंतर्गत आता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया सरकार बनाने की प्रक्रिया सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि।

राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य–नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीकें से आंकने का प्रशिक्षण देना है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है– राजनीतिक सिद्धांत में हम 'समानता', 'आजादी' या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते है।

ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है।

दूसरी ओर राजनीति विज्ञान व राजनीति भी दो अलग–अलग धारणाएं है। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यह नैतिकता पर आधारित है जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। इतना होने पर भी इन्हें सिक्के के दो पहलू के रूप में माना जा सकता है।

राजनीतिक सिद्धांत का महत्व–

– न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास

– तर्कसंगत व प्रभावी ढंग से सम्प्रेषण

– कुशल व प्रभावी राजनीति निर्णय लेने में सहायक

– अन्तर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने हेतु।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्नः–

1. कथनः राजनीति विज्ञान व राजनीति दो अलग–अलग विचारधारा हैं।

   कारणः राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पहले हुआ यह नैतिकता पर आधारित है। राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है।

   (A) कथन व कारण दोनों गलत है।

   (B) कथन सही है, कारण भी सही है। कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   (C) कथन सही कारण गलत है।

   (D) कथन व कारण दोनों सही है परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा।

2. कथनः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है।

   कारणः राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से न्याय समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास होता है।

   (A) कथन सही कारण गलत है।

   (B) कथन गलत, कारण सही है।

   (C) कथन व कारण दोनों सही हैं। कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा।

   (D) कथन व कारण दोनों सही हैं कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

3. राजनीति क्या है?

   (A) शासन करने की कला

   (B) सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है

   (C) प्रशासनिक संचालन के विषयों को हल देती है

   (D) उपरोक्त सभी

4. राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है?

   (A) सरकार व नागरिक

   (B) नागरिक व मतदाता

   (C) राज्य व सरकार

   (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. व्यवहारपरक राजनीतिक सिद्धांत किस शताब्दी की उपज है?

(A) 18वीं शताब्दी (B) 20वीं शताब्दी

(C) 16वीं शताब्दी (D) 21वीं शताब्दी

6. 'रिपब्लिक' पुस्तक किसने लिखी?

(A) अरस्तु (B) महात्मा गांधी

(C) अंबेडकर (D) प्लेटो

7. 'थ्योरी' (Theory) शब्द का उद्‌भव 'Theoria' शब्द से हुआ यह किस भाषा का शब्द है?

(A) संस्कृत (B) लैटिन

(C) यूनानी (D) फ्रेंच

8. मनुष्य अद्‌वितीय हैं क्योंकि वेः

(A) राजनीति में भाग लेते हैं

(B) वे आपस में लड़ते हैं

(C) उनके पास एक–दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विवेक और भाषा है

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

एक अंकीय प्रश्नः–

9. राजनीतिक सिद्धांत क्या है? समझाइए।

10. गांधी जी की पुस्तक 'हिन्द–स्वराज' में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है?

11. राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है?

12. राजनीतिक विज्ञान व राजनीति में कोई एक अन्तर लिखें?

13. हमें राजनीतिक सिद्धान्त क्यों पढ़ना चाहिए?

14. राजनीतिक सिद्धान्त का मुख्य विषय क्या है?

15. राजनीति क्या है? (निम्न में से सही को अंकित करें)

(i) राजनीति शासन करने की कला है।

(ii) राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है।

(iii) राजनीति जन कल्याण से संबंधित है।

(iv) उपरोक्त सभी

16. राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं ....., ..., ... तथा ..... । (कोई चार पहलू लिखें)।

17. वाक्य कों सही करके लिखें–

लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी नहीं है।

18. राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत दो अलग–अलग धारणाएं हैं। (सही / गलत)

19. राजनीतिक सिद्धांत भावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक है? (सही / गलत)

दो अंकीय प्रश्नः–

1. 'राजनीति' का अर्थ स्पष्ट करें।
2. राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो क्षेत्रों को समझाइए। वर्णन कीजिए।
3. किन्हीं चार राजनैतिक विद्वानों के नाम लिखिए।
4. राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के किन–किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं?
5. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? कोई दो कारण लिखिए।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. 'राजनीति विज्ञान, विज्ञान है भी और नहीं भी।' इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए।
2. किसी देश में लोकतंत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। कैसे?
3. 'राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम–कदम पर प्रभावित करती है। स्पष्ट कीजिए।

4. चार अंकीय प्रश्नः–

राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाएँ। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आँकने का प्रशिक्षण देता है।

4.1. राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्य कौन–कौन से हैं?

(A) शिक्षा, नैतिकता (B) आदर्श, सत्यता, ईमानदारी

(C) स्वतंत्रता, समानता और न्याय (D) समानता, धर्मनिरपेक्षता, मित्रता

4.2. राजनीतिक सिद्धांत किस को आंकने का प्रशिक्षण देता है?

(A) आर्थिक व राजनीतिक घटनाओं को

(B) शैक्षिक व विदेशी घटनाओं को

(C) सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को

(D) विदेशनीति व सामाजिक नीतियों को

4.3. नागरिकों को तर्क संगत ढंग से सोचने, सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण देना किसका उद्देश्य है?

(A) राजनीतिक सिद्धांत का (B) आर्थिक सिद्धांत का

(C) राल्स के न्याय सिद्धांत का (D) सामाजिक न्याय के सिद्धांत का

4.4. मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए किन–किन राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखा जाता है।

(A) वर्तमान के सभी चिन्तक (B) आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख चिन्तक

(C) भूतकाल (अतीत) के चिन्तक (D) अतीत और वर्तमान के प्रमुख चिन्तक

छः अंकीय प्रश्नः–

1. राजनीतिक सिद्धान्त में हम क्या–क्या पढ़ते है? लिखिए।
2. राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएं लिखिए।
3. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? सविस्तार समझाइए।
4. 'राजनीतिक सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है।'' कैसे? तर्क सहित सिद्ध कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (B) कथन सही है, कारण भी सही है। कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. (D) कथन व कारण दोनों सही हैं। कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
3. (D) उपरोक्त सभी
4. (C) राज्य व सरकार
5. (B) 20वीं शताब्दी
6. (D) प्लेटो
7. (C) यूनानी
8. (C) उसके पास एक–दूसरे के साथ संवाद करने के लिये विवेक और भाषा है।
9. राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है।
10. स्वराज के अर्थ की विवेचना पर।
11. आम लोग राजनीति को अच्छा नहीं मानते।
12. राजनीतिक विज्ञान निश्चित आदर्शों पर आधारित है जबकि राजनीति स्वार्थ व अवसरवादिता पर आधारित है।
13. इससे राजनीतिक नियमों/सिद्धांतों, समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का ज्ञान होता है। जो लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।
14. राज्य व सरकार
15. (4) उपरोक्त सभी।
16. स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र (पाठ में वर्णित अन्य)
17. लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है।
18. सही।
19. सही।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राजनीति शब्द की उत्पति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिस का शाब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है।

2. (i) राज्य और सरकार का अध्ययन।

   (ii) शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन।

3. अरस्तु, प्लेटो, रूसों, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, एवं डॉ. अम्बेडकर।

4. राजनीतिक सिद्धांत में मुख्यतः सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता समानता न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि का अध्ययन किया जाता है।

5. 1. शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए।

   2. अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए। (अन्य कोई पॉइंट)

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. **राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान है**– जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनका तर्क है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें प्रयोग संभव है। इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है तथा इतिहास एवं समस्त विश्व इसकी प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

   राजनीति विज्ञान, विज्ञान नहीं है– जो लोग इसे विज्ञान नहीं मानते उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त स्पष्ट नहीं हैं। राजनीति में समान कारण होते हुए भी राजनीति विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं निकलते। इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है। इसकी कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होती। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना सम्भव नहीं।

2. राजनीति सिद्धान्त उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएँ बनती हैं। राजनीति सिद्धान्त विभिन्न धर्मों के अंतर्संबंधों की व्याख्या करते हैं।

   ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं।

3. दैनिक जीवन में व्यक्ति कदम–कदम पर स्वतंत्रता एवं समानता के लिए संघर्ष करता नजर आता है। उदाहरण कही पानी के लिए सार्वजनिक नल पर पानी भरना हो चाहे समान रूप से मंदिर में प्रवेश को लेकर हो

4.1. (B) स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य।

4.2. (C) सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को।

4.3. (A) राजनीतिक सिद्धांत का

4.4. (D) अतीत और वर्तमान के प्रमुख राजनीतिक चिंतक।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राजनैतिक सिद्धान्त में हम–समाज में आए परिवर्तनों, आन्दोलनों, विकास तथा विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते है तथा अन्य कारण।

2. स्वतंत्रता, समानता पूर्वाग्रहों का त्याग करना, देश का विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के मार्ग निर्देशन देना आदि। अन्य कारण।

3. (i) जागरूक बनाने के लिए।
   (ii) भविष्य की समस्याओं के सफल समाधान कर्ता तैयार करने के लिए।
   (iii) समाज में एकता कायम करने के लिए।
   (iv) तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार करना, आदि।

4. राजनैतिक सिद्धान्त स्वतंत्रता व समानता से संबंधित प्रश्नों के सरल एवं सहज उत्तर प्रस्तुत करता है। यह सम्पूर्ण मानव समाज के विकास एव सभ्यता के उदाहरण प्रस्तुत करतो हुए सभ्य मानव बनने का मार्ग सुझाता है तथा गलत रास्ते पर जाने के परिणामों से अवगत करता है।

   यह स्वतंत्रता एवं समानता को अपनाने वाले राष्ट्रों की समृद्धि एवं सफलता की कहानी के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व से गुलामी एवं असफलता को समाप्त करने का रास्ता दिखाता है।

अध्याय 9

स्वतंत्रता

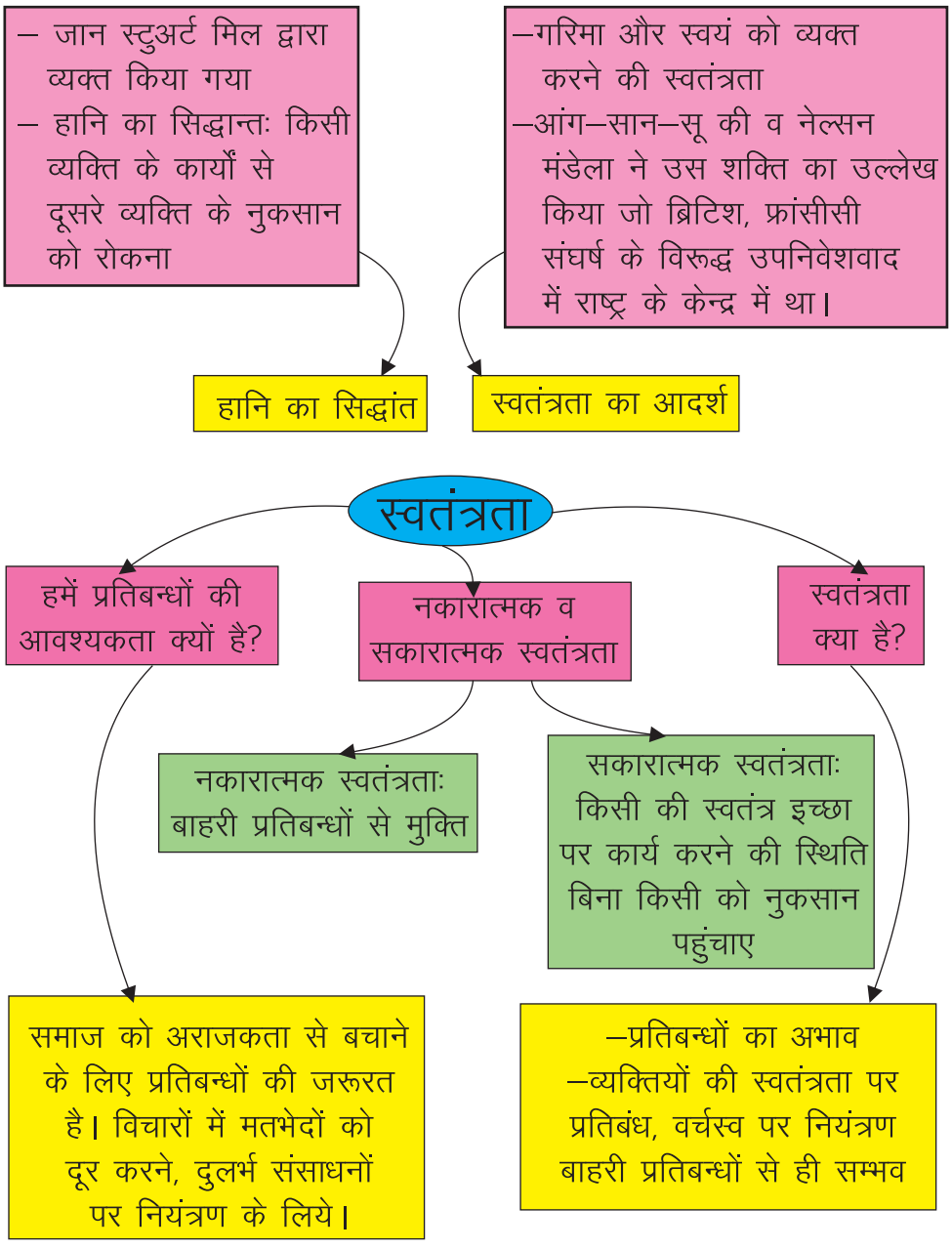

स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है।

मुख्य बिन्दुः

– स्वतंत्रता का आदर्श

– स्वतंत्रता क्या है?

– स्वतंत्रता का आदर्श प्रतिबंधों के स्रोत

– प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों?

– हानि सिद्धांत।

– स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीडम)

– नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। (दो आयाम)

स्वतंत्रता का आदर्शः

नेल्सन मंडेला की पुस्तक 'लॉंग वाक टू फ्रीडम' तथा आँग सान सू की पुस्तक 'फ्रीडम फ्रॉम फीयर' स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं। गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है।

स्वतंत्रता क्या है?

- सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रुप में माना जाता है। इसे मानव के 'जो चाहे सो करे' के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। (बाहरी प्रतिबंधों का अभाव)
- हाब्स ने इसे अर्थात ' जो चाहों सो करो' की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है।
- दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।
- वार्कर के अनुसार, 'व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है।
- स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा + तर्कसंगम बंधन।
- बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मण्डेला तथा आंग सान सू, की आदि

व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक व दमनात्मकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया।

स्वतंत्रता के प्रकार

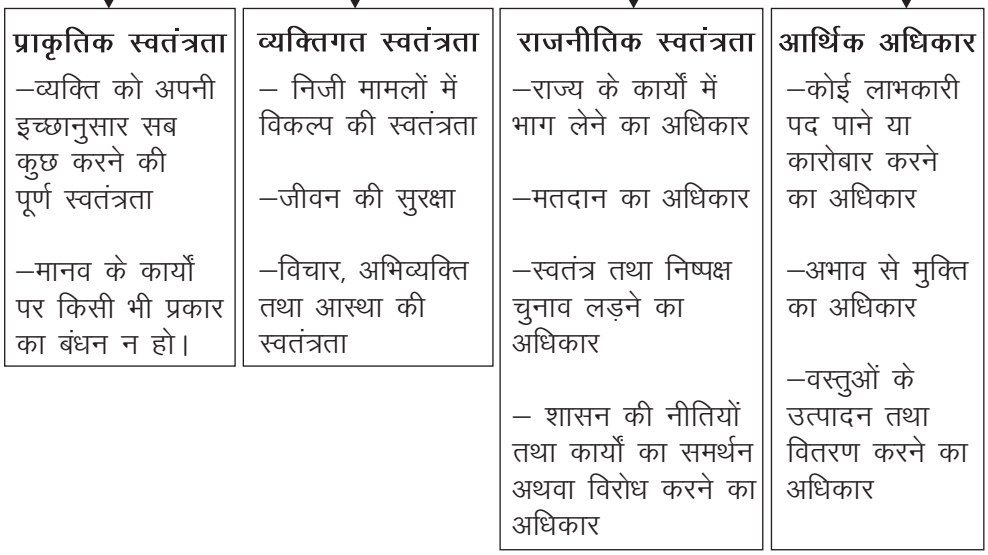

उदारवादी बनाम मॉर्क्सवादी धारणाः–

- ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते है और मानते है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है।
- सकारात्मक उदारवादी (हॉब्स लॉक तथा लास्की) समर्थन करते है कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता हैं। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन।
- उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते है। वे आमतोर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते है।
- मार्क्सवादी (समाजवादी) सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते है।
- स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जुआ समाज में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते है। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के

स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है।

आदर्श प्रतिबंधों के स्रोतः–

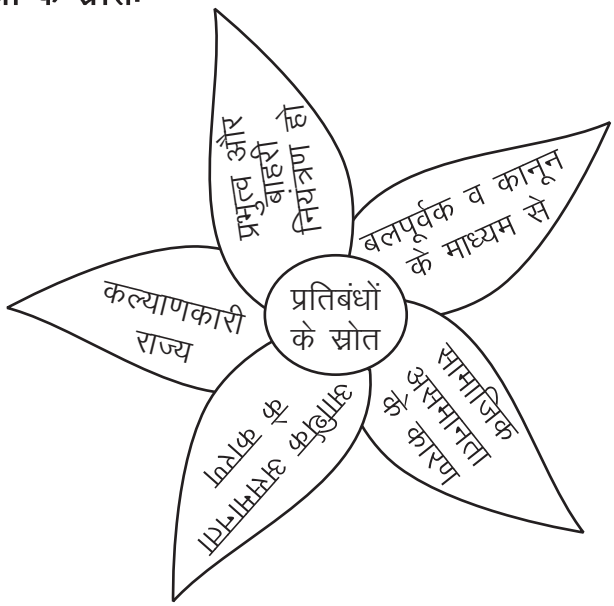

प्रतिबंधों की आावश्यकताः–

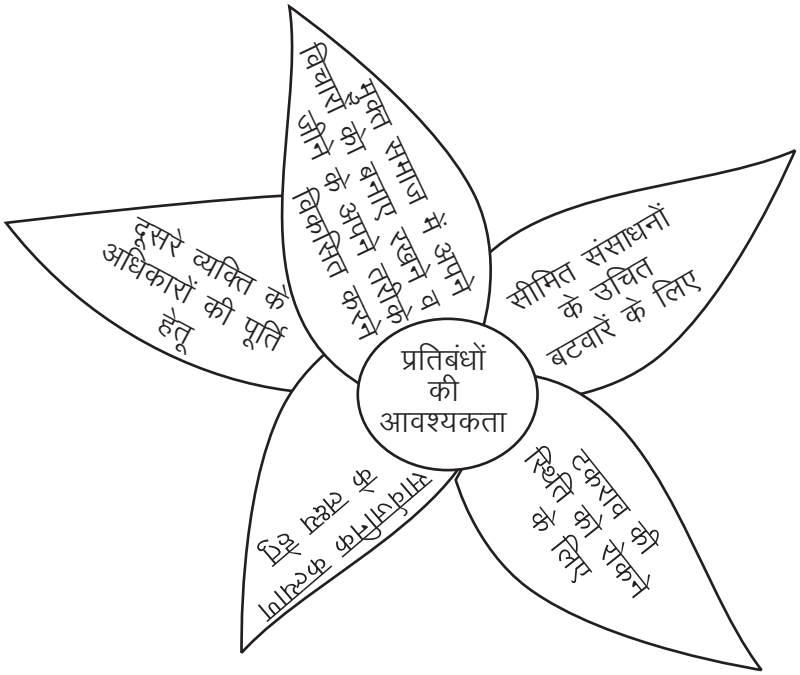

हानि का सिद्धांतः

''किसी के कार्य करने के स्वतत्रंता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है।''

जे. एस. मिल ने यहां एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा 'स्वसंबंध' और 'परसंबंध' के रूप में। स्वसंबंध जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के उपर पड़ता है। 'परसंबंध जिसमें करने वाले कार्य का प्रभाव अन्य बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ता है। यदि उन कार्यों से दूसरों को कोई बड़ी हानि पहुंच रही हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्य उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है।

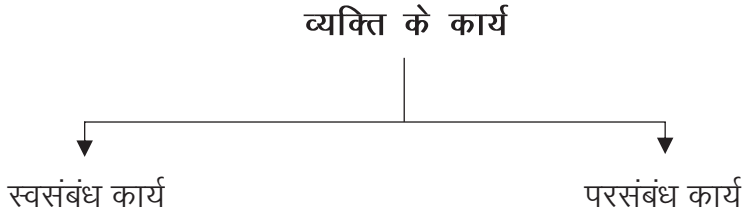

राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है।

स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीडम)

स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीमड) हम प्रायः स्वतंत्रता संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हुए देखते हैं परंतु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर है जिन्हें समझना आवश्यक है। लिबर्टी लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है 'मुक्त व्यक्ति की स्थिति'। जबकि स्वतंत्रता (लिबर्टी) अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना है जिसका अर्थ है 'मुक्त राज्य'।

(लिबर्टी) व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति है, जबकि फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। फ्रीडम, लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। फ्रीडम व्यक्ति के राज्य के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबंध संकल्पना है। राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है।

स्वतंत्रता (फ्रीडम)

– एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति

– कार्य करने की शक्ति

– कुछ करने के लिए स्वतंत्रता

स्वतंत्रता (लिबर्टी)

– स्वतंत्र इच्छा की अवस्था।

– निर्णय लेने की शक्ति।

– किसी से स्वतंत्र।

इन दोनों संकल्पना के मध्य एक सामान्य विशेषता यह है कि यह दोनों संबंधित हैं, अर्थात एक–दूसरे की प्राप्ति में बाधा मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त दोनों अपने बोध के संदर्भ में नैतिक अनुरूपता का पालन करते हैं।

स्वतंत्रता के आयामः–

– स्वतंत्रता के दो आयाम है– (i) नकारात्मक व (ii) सकारात्मक

– **नकारात्मक स्वतंत्रता**– नकरात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते है। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो।

– समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ.ए. हायक आदि।

– **सकारात्मक स्वतंत्रता**

- नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सकें।
- यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबन्ध अनिवार्य है।
- मानव समाज मे रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते है। इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए।
- तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति।
- समर्थक है टी.एच.ग्रीन व प्रो. ईसाह बर्लिन' की।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताः–

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है।
- जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'आन लिबर्टी' में सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हो।
- चार सबल तर्कः–
    1) कोई भी विचार पूरी से गलत नहीं होता। उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है।
    2) सत्य स्वंय से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है।
    3) जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है।
    4) आज जो सत्य है, वह हमेशा सत्य नही रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नही है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप में समस्या का समाधान बन जाते है तथा तत्कालीन मांग को पूरा कर देते है लेकिन समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है।

स्वतंत्रता की रक्षा के उपायः–

- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
- मौलिक अधिकरों का प्रावधान
- कानून का शासन
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- शक्तियों का विकेन्द्रीकरण
- शक्तिशाली विरोधी दल
- आर्थिक समानता
- विशेषाधिकार न होना
- जागरूक जनमत

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. कथनः– किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिये अधिकार जरूरी होते हैं।

   कारणः– भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है।

   (A) कथन गलत है कारण सही हैं।

   (B) 'कथन' व 'कारण' दोनों सही हैं कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   (C) कथन सही कारण गलत

   (D) उपरोक्त सभी सही

2. 'लिबर्टी' शब्द की उत्पत्ति, किस भाषा के शब्द से मानी जाती है?

   (A) स्पेनिश

   (B) ग्रीस

   (C) लैटिन

   (D) फ्रेंच

3. नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?

   (A) प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता

   (B) प्रतिबंधों का अभाव

   (C) प्रतिबंधों की अधिकता

   (D) उपरोक्त सभी

4. सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं?

   (A) प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता

   (B) परिस्थिति के अनुसार प्रतिबंध

   (C) राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

   (D) आर्थिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर रोक

5. 'लिबर' (Liber) शब्द का क्या अर्थ है?

(A) वैश्विक स्वतंत्रता

(B) आर्थिक स्वतंत्रता

(C) राजनीतिक स्वतंत्रता

(D) पूर्ण स्वतंत्रता

6. स्वतंत्रता के दो आयाम कौन–कौन से हैं?

(A) एकात्मकता तथा नकारात्मकता

(B) सकारात्मकता तथा बहुलवाद

(C) नकारात्मक तथा सकारात्मक

(D) उपरोक्त सभी

7. स्वतंत्रता (लिबर्टी) का अर्थ है?

(A) स्वतंत्रता की अवस्था

(B) निर्णय लेने की शक्ति

(C) किसी से स्वतंत्र

(D) उपरोक्त सभी

8. निम्नलिखित का मिलान करें (1+1+1+1+1)

(A) नेल्सन मंडेला	(i) हिन्द स्वराज
(B) आंग सान सू की	(ii) रामायण रिटोल्ड
(C) गांधी जी	(iii) लॉंग वॉक टू फ्रीडम
(D) जॉन स्टुअर्ट मिल	(iv) फ्रीड़म फार फीयर
(E) ओब्रे मेनन	(v) आन लिबर्टी

9. स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है?

10. प्रतिबंधों के स्रोत क्या है?

11. नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते है?

12. एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है?

13. जान स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है?

14. नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है।

15. आंग सान सू ने किस देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

16. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए।

17. भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है?

18. ''तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता परन्तु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा।'' यह कथन किसका है और इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं गई है?

19. स्वतंत्रता संबंधी नेताजी सुभाष चन्द्र जी के विचार क्या है?

20. 'स्वराज' शब्द से क्या अभिप्राय है?

21. स्वतंत्रता की एक विशेषता का वर्णन कीजिए?

22. लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था?

23. सलमान रुश्दी की ..... पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया?

24. निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की रक्षा के कौन–कौन से उपाय हैं?

(क) कानून का शासन (ख) आर्थिक समानता

(ग) जागरूक जनमत (घ) उपरोक्त सभी

25. कथन को सही करके लिखेंः गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी नहीं है।

26. प्रतिबंधों के निम्नलिखित स्रोत हैंः

(क) कल्याणकारी राज्य

(ख) प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण हो

(ग) बलपूर्वक व कानून के माध्यम से

(घ) सामाजिक असमानता तथा सभी

27. राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों में इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है। (सही / गलत बताइये)

28. 'हानि के सिद्धांत' का संबंध हैः

(क) प्लेटो (ख) अरस्तु

(ग) जे एस मिल (घ) कार्ल मार्क्स

दो अंकीय प्रश्नः–

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते है?
2. राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट कीजिए?
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अपने विचार दीजिए?
4. नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए?
5. आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
6. स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है?
7. फिल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में विधवाओं पर फिल्म बनानें से किस आधार पर रोका गया? यह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन था?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है?
2. सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है?
3. स्वतंत्रता के चार लक्षणों का वर्णन करो?
4. जॉन स्टुअर्ड मिल के 'हानि सिद्धान्त' का वर्णन करो?
5. निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएः

   सकारात्मक स्वतंत्रत के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्रत हो सकता है, समाज से बाहर नहीं और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते है जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंधनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नही। नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ–साथ चलती है और एक–दूसरे का समर्थन करती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करें।

5.1 सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है?

(A) प्रतिबन्धों का होना (C) अराजकता

(B) प्रतिबन्धों को न मानने की स्वतंत्रता (D) सरकार की स्वतंत्रता

5.2 नकरात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है?

(A) राज्य की संप्रभुत्ता (C) सबकी मनमानी

(B) आपसी सामान्जस्य (D) प्रतिबन्धों का अभाव

5.3 क्या दोनों स्वतंत्रताएं आमतौर पर साथ–साथ चलती हैं ('हाँ' अथवा 'ना')

(A) हाँ (B) ना

5.4 सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल–––––– में ही स्वतंत्र हो सकता है।

(A) घर में (C) समाज में

(B) देश में (D) कार्यस्थल में

छः अंकीय प्रश्नः–

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइये।

2. हमें प्रतिबंधों की आदत को विकसित क्यों नहीं होने देना चाहिए? ऐसा आदत किस प्रकार से स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है? व्याख्या कीजिए।

उत्तरमाला

1. (B) कथन व कारण दोनों सही हैं, कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. (C) लैटिन
3. (B) प्रतिबन्धों का अभाव।
4. (A) प्रतिबन्धों के साथ स्वतंत्रता
5. (D) पूर्ण स्वतन्त्रता
6. (C) नकारात्मक तथा सकारात्मक
7. (D) उपरोक्त सभी
8. (A-iii), (B-iv), (C-i), (D-v), (E-ii)

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

9. अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न होंगे तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
10. कानून द्वारा, बल के आधार पर,
11. एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अबाधित रूप से व्यवहार कर सके।
12. आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा प्रतिभा का विकास करना।
13. दो भागों में – स्वसंबद्ध कार्य, परसबंद्ध कार्य
14. 'लॉग वाक टू फ्रीडम' (स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा)
15. म्यांमार में
16. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का केन्द्र बिन्दू व्यक्ति है। व्यक्ति को अधिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना।
17. स्वराज की अवधारणा।
18. यह कथन 'वाल्तेयर' का है और इसमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'की बात कही गयी है।
19. ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है– जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियो और पुरूषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो।
20. स्वराज का अर्थ 'स्व' का शासन भी हो सकता है और 'स्व' के उपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है।
21. उचित बंधनों का होना।
22. 'स्वराज' मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा''।
23. 'द सेटानिक वर्सेस'
24. उपरोक्त सभी
25. गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है।
26. सामाजिक असमानता तथा सभी।
27. सही
28. (ग) जे एस मिल

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. मनुष्यों का व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। भोजन, वस्त्र, शादी–विवाह, रहन–सहन आदि मामलों में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए।

2. राज्य के नागरिकों को–
   - अपनी सरकार में भाग लेना।
   - मताधिकार का प्रयोग करना।
   - चुनाव लड़ना आदि।

3. राष्ट्र को विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। जिससे नागरिकों अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथ राजनैतिक विकास कर सके।

4. एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है। ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए।

5. – अपनी रूचि व योग्यातानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
   – देश में उद्योग–धंधों को चलाने की स्वतंत्रता।
   – धन का उत्पादन व वितरण ठीक ढंग से हो।
   – बेरोजगारी न हो।

6. स्वतंत्रता अभिप्राय व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। इसका आशय व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, जिसमें व्यक्ति की रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास हो सकें।

7. – भारत की दशा का बुरा चित्रण होना।
   – विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
   – काशी नगरी की बदनामी होना।

   यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन था।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है जिनके अंतर्गत व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। हॉब्स के

अनुसार ''ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ है– सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव।'' जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियमों, उपनियमों तथा कानूनों के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता। संक्षेप में कहा जाए तो नकरात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे ताकि मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो जबकि सकरात्मक स्वतंत्रता के पोषक राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इससे व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करता है।

नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियंत्रित स्वतंत्रता है।

नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव तथा उचित बंधनों का अस्तित्व है।

नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों की स्वतंत्रता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की स्वतंत्रता है।

नकारात्मक स्वंतत्रता में एक व्यक्ति कुछ कह सकता है, परन्तु सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमा में रहकर ही कुछ कर सकता है।

2. सामाजिक प्रतिबंध – सामाजिक प्रतिबंध का आषय है कि समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हों, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। बिना प्रतिबंधों के स्थिति अराजकता की हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी।

सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जो प्रतिबंध जोर–जबरदस्ती यानी बलपूर्वक लगाए जाते हैं, जिसमें शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं, हैं जैसे– तानाशाही शासन व्यवस्था में। जबकि लोकतंत्रिक देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना लोगों को उचित परिस्थितियाँ देना है। अतः वह सामाजिक प्रतिबंध जो व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं जो व्यक्तिगत समूहों तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू होते हैं।

3. स्वतंत्रता के लक्षण निम्नलिखित हैं–

(i) स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है।

(ii) करने योग्य कार्य को करने की शक्ति ही स्वतंत्रता है।

(iii) स्वतंत्रता नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती बल्कि व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करती है।

(iv) स्वतंत्रता समाज में मिल सकती है, समाज के बाहर नहीं।

(v) स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

4. सिद्धान्त यह है कि किसी के कार्य करने की स्वंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देष्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अतः हानि पहुँचाने वाले कार्यो पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे ही हानि का सिद्धान्त कहते हैं।

5.1 (A) प्रतिबन्धों का होना

5.2 (D) प्रतिबन्धों का अभाव

5.3 (A) हाँ

5.4 (C) समाज में

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छे 19 द्वारा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध हैं। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परन्तु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता या किसी को अपशब्द नहीं कह सकता। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक कार्य तो कर सकता है परन्तु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। परन्तु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देष की अखण्डता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है।''

   राज्य यह भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार लोगों का स्वंतत्रता की रक्षक हैं।

2. विद्यार्थी स्वयं अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय 10

समानता

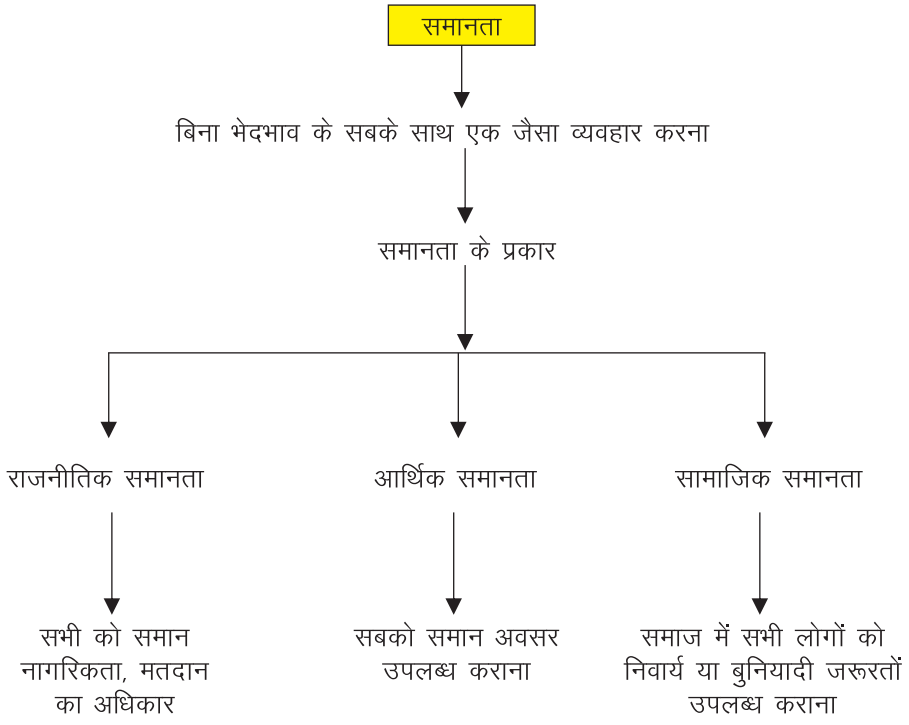
समानता
बिना भेदभाव के सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना
समानता के प्रकार
राजनीतिक समानता
आर्थिक समानता
सामाजिक समानता
सभी को समान नागरिकता, मतदान का अधिकार
सबको समान अवसर उपलब्ध कराना
समाज में सभी लोगों को निवार्य या बुनियादी जरूरतों उपलब्ध कराना

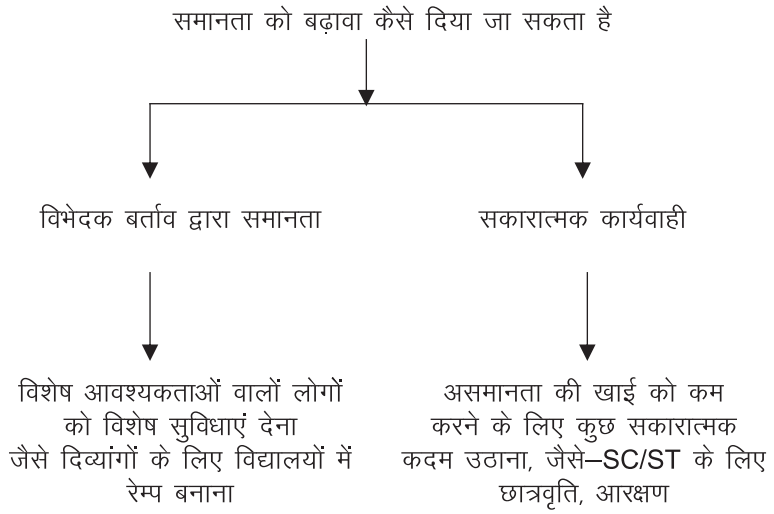
समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है
विभेदक बर्ताव द्वारा समानता
सकारात्मक कार्यवाही
विशेष आवश्यकताओं वालों लोगों को विशेष सुविधाएं देना जैसे दिव्यांगों के लिए विद्यालयों में रेम्प बनाना
असमानता की खाई को कम करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाना, जैसे–SC/ST के लिए छात्रवृति, आरक्षण

मुख्य बिन्दुः

– समानता का महत्व।

– समानता क्या है?

– समानता के विभिन्न आयाम।

– हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?

समानता का महत्व (महत्वपूर्ण क्यों?)

समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी है। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक भी है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए भी समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समानता क्या है?

सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेद–भाव के।

सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है।

- अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, सम्पदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती हैं
- समानता के अनुसार, व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार, जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए।
- प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है।

समानता के तीन आयामः–

- **राजनीतिक समानता**– सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है।

- **आर्थिक समानता**– आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने की मौका देती हैं।

- **समाजिक समानता**– राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवनयापन के लिये अनिवार्य–चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारण्टी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी।

- असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है।

- विभेदक बर्ताव अर्थात् लोगों के बीच अंतर को ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव (आरक्षण) की नीति बनाई गई है जिससे समाज के सभी वर्गों की अवसरों तक समान पहुंच हो सके। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया है।

- समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रूत्बे या विशेषाधिकार जैसी असमानाताओं को बढ़ावा देती है इसीलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है।

- उदारवादी, समाज में, संसाधनों के वितरण के मामले में, प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते है और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते है।

- स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिये अत्यंत आवश्यक हैं

- विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक व समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है।

समानता के प्रमुख प्रकारः

– प्राकृतिक समानता

– नागरिक समानता

– सामाजिक समानता कानूनी समानता

– राजनीतिक समानता

– आर्थिक समानता

– शिक्षा की समानता

– अवसर की समानता

– सांस्कृतिक समानता आदि।

हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं?

– औपचारिक समानता की स्थापना करके।

– सरकार और 'कानून' और 'समानता' की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करके।

– विशेष अधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा।

– दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता स्थापित करने वाली कानूनी व्यवस्था और रीति–रिवाजों को समाप्त करना होगा।

– महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे कर।

विभेदक बर्ताव द्वारा समानता।

समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं कभी–कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकें उनसे अलग–अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यागों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ बर्ताव बनाया जाता है।

सकारात्मक कार्यवाही

जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप में लागू करना।

असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

दलित, वंचित समुदायों, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा होस्टल जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों के विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य अर्थात सरकार को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. कथनः कानून के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है।

   कारणः भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

   A—कथन और कारण दोनों सही है, कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   B—कथन सही, कारण गलत है।

   C—कथन और कारण दोनेां सही हैं, कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।

   D—दोनों गलत हैं।

2. समानता के तीन प्रमुख आयाम हैं?

   A. राजनीतिक समानता

   B. आर्थिक समानता

   C. सामाजिक समानता

   D. उपरोक्त सभी

3. '''पुरुष', 'स्त्री' से शक्तिशाली है''। यह किसका उदाहरण है?

   A. सामाजिक असमानता का

   B. अवसर की समानता का

   C. शैक्षिक असमानता का

   D. आर्थिक असमानता का

4. धर्म, जन्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना कहलाता है?

A. नैतिक समानता

B. राजनीतिक समानता

C. सामाजिक समानता

D. इनमें से कोई नहीं

5. न्यूनतम आवश्यकतआं की पूर्ति से अभिप्राय है किः

A. सामाजिक समानता

B. आर्थिक समानता

C. प्राकृतिक समानता

D. सांस्कृतिक समानता

6. सभी व्यवस्कों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार किस समानता में आता है?

A. राजनीतिक समानता

B. धार्मिक समानता

C. शैक्षिक समानता

D. अवसर की समानता

7. समानता का महत्व लिखिए।

8. क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना है?

9. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था?

10. क्या समाज मे समानता के साथ–साथ असमानता अधिक नजर आती है?

11. भारतीय समाज में व्याप्त एक साधारण असमानता का उल्लेख कीजिए?

12. नारीवाद से आप क्या समझते है?

13. वंचित समूहों से क्या अभिप्राय है?

14. समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है?

(क) 19 से 22 (ख) 14 से 18

(ग) 10 से 12 (घ) इनमें से कोई नहीं

15. भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष में पास किया?

(क) 1975 (ख) 1875

(ग) 1895 (घ) 1995

16. कथन को सही करके लिखें:

समानता के तीन आयाम, सांस्कृतिक समानता, आर्थिक समानता व नैतिक समानता है।

17. सही वह गलत का निशान लगाए:

1. सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार की समानता है। ( )

2. सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना समानता है। ( )

3. विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है। ( )

4. जैसा जो चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र होना ही समानता है। ( )

18. मनुष्य के ..... विकास के लिए भी समानता अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

19. समानता को बढ़ावा देने वाले कोई दो कारक लिखिए।

20. किसी एक असमानता को लिखिए जो आपने स्वयं अनुभव की हो।

21. क्या आर्थिक असमानता समाप्त करना संभव है? यदि हां तो किस प्रकार से?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते है?

2. आर्थिक समानता का अर्थ लिखिये।

3. समानता के आदर्श से क्या तात्पर्य है?

4. कुछ विभिन्नताएं जन्मजात न होकर भी जन्मजात बना दी गई है? इस संबंध में अपने विचार लिखिये।

5. प्राकृतिक व समाज—जनित असमानताओं से आप क्या समझते है?

6. क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का उदाहरण हो सकता हैं?

7. क्या आपके अनुसार सामाजिक समानता भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है? क्यों?

8. मॉर्क्सवाद से आप क्या समझते है?

9. समाजवाद की अवधारणा समझते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम बताइये।

10. ''विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है'' कैसे?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. ''क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती है? इस सम्बन्ध में अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिये।

2. मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारण को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट कीजिए।

3. हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते है?

4. ''राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है''। प्रयुक्त वाक्य को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट कीजिये।

5. संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये? क्या यह कारगर सबित हुए।

6. ''एक अध्यापक और एक फैक्ट्री मजदूर के वेतन के अंतर को आप असमानता मानते है''। यदि नही तो क्यों?

6. गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिये–

समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलनों द्वारा उठाए गए। उन्नीसवीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकरों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज–यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरूषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बरताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यवसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा

सकेंगी दूसरे शब्दों में पुरूषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बरताव की जरूरत होती थी।

1. नारीवाद से क्या तात्पर्य है?

   (A) महिला अधिकारों पर बल देना (B) महिला–पुरुष समानता स्थापित करना

   (C) महिला सशक्तिकरण (D) उपरोक्त सभी

2. पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं को विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

   (A) महिलाओं की वंचित स्थिति के कारण

   (B) राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में न्यून महिला भागीदारी के कारण

   (C) (A) तथा (B) दोनों

   (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. क्या यह विशेषाधिकार समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है या नहीं? समझाइये।

4. उपरोक्त गद्यांश किस विषय की सार्थकता को प्रदर्शित कर रहा है।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1.

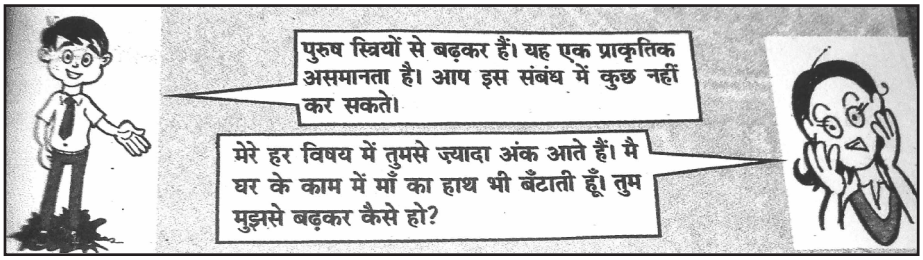

प्रस्तुत कार्टून के संदर्भ में स्त्री पुरूष समान हैं या असमान। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

छः अंकों वालों प्रश्नः

1. ''मानव जीवन के सम्मानपूर्वक संचालन के लिये समानता आवश्यक व अनिवार्य है''। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समानता के तीनों आयामों पर प्रकाश डालिये।

2. क्या विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता की विरोधी अवधारणा है? आपके अनुसार इस सम्बंध में क्या सुझाव या सुधार होने चाहिये।

उत्तरमाला

1. A—कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. D—उपरोक्त सभी
3. A—सामाजिक असमानता का
4. C—सामाजिक समानता
5. B—आर्थिक समानता
6. A—राजनैतिक समानता

एक अंकीय उत्तरः—

7. समानता के कारण सभी व्यक्ति महत्व व सम्मान के अधिकारी है। इसी धारणा ने सर्वभौमिक मानावधिकार जैसी धारणा का जन्म दिया।
8. नहीं वरन व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमताओं को ध्यान में रखकर अवसर की समानता मुहैया कराना है।
9. स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा।
10. हाँ। आलीशान कॉलोनियों के साथ झुग्गियां भोजन की बर्बादी के साथ भुखमरी समाज में आसानी से देखी जा सकती है।
11. स्त्री पुरूष असमानता जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है।
12. नारीवाद स्त्री पुरूष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है।
13. लम्बे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिनपर जन्म व जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होते रहे है।
14. अनुच्छेद (14—18)
15. वर्ष 1995
16. समानता के तीन आयाम राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता व सामाजिक समानता है।

17. 1. (√) सही

2. (√) सही

3. (√) सही

4. (×) गलत

18. सर्वांगीण

19. 1. औपचारिक समानता की स्थापना करके

2. महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे करके।

20. विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर उत्तर लिखें।

21. अवसर की समानता द्वारा।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. व्यक्ति के काम के महत्व के आधाार पर असमानता न्यायपूर्ण कहीं का सकती है जैसे देश के प्रधानमंत्री व सेना के जनरल को विशेष दर्जा या सम्मान जबकि व्यक्ति के जन्म व जाति पर आधारित असमानता अन्यायपूर्ण होगी जैसे मंदिर व सार्वजनिक स्थल में प्रवेश पर रोक।

2. अमीर व गरीब के बीच व्याप्त खाई को कम करना तथा अवसरों से समानता की उपलब्धि

3. व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या समाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने चाहिए।

4. जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लम्बे समय तक विद्यमान रहती है तो वह प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित लगने लगती है जैसे प्राचीन समय से ही महिलाओं को अबला व पुरूषों के मुकाबले में डरपोक मानकर उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना, न्यायसंगत मान लिया गया था।

5. प्राकृतिक असमानताएं व्यक्तियों की क्षमता व प्रतिभा से जुड़ी होती है जबकि समाजजनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से जुड़ी होती है।

6. यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता वर्णित है किंतु फिर भी समाज में अमीर गरीब, स्त्री पुरूष व जातिगत असमानताओं के उदाहरण प्रतिदिन देखने को मिलते है।

7. हां क्योंकि भारतीय समाज जातिगत विभिन्नताओं में बंटा है। जन्म के आधार पर फैली असमानता को समाप्त करने के लिय डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने आरक्षण सम्बधी प्रावधानों का जिक्र किया था।

8. सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधानों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए।

9. समाजवाद का अर्थ असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया।

10. हाँ, क्योंकि समानता व विकास की दौड़ में पीछे रह गई नीतियों को विशेषाधिकारों की आवश्यकता है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. नहीं! यह परिवर्तनीय हो सकती है चिकित्सा तकनीक व कम्प्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिन्स का चलने व न बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है।

2. मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने के प्रयास में विश्वास रखते है जबकि उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गो से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं।

3. विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति तथा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लाने का प्रयास।

4. न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ सकता जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

5. 1964 में Civil Right Act सरकार द्वारा पास किया गया जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमा मय पद पर दो बार आसीन हो चुके हैं। जो रंगभेद की नीति के नकारे जाने का उदाहरण है किंतु फिर भी समाज में समय –समय पर अश्वेतों के विरूद्व हिंसा की गूंज सुनाई पड़ जाती है।

6. समानता के अनुसार समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए था कार्य बौद्विक व शारीरिक अलग अलग है।

अध्याय 11
न्याय

''न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।—डॉ. बी आर अंबेडकर	सामाजिक न्यायः व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियम और तरीके, सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा।	''न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है।'' —जे.एस.मिल

न्याय के सिद्धांत

- 1. समान लोगों के प्रति समान बर्ताव
- 2. समानुपातिक न्याय
- 3. विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल

न्यायपूर्ण बंटवाराः नियम कानूनों को निष्पक्षता से लागू करवाना तथा वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित बंटावारा।

जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांतः तर्क–1: निष्पक्ष और न्याय संगत नियम यह है कि यदि हम खुद को ऐसी स्थिति में होने की कल्पना करते हैं जिसमें हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए अर्थात ''अज्ञानता के आवरण में सोचना।''

तर्क–2: नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है।

सामाजिक न्याय का अनुसरणः समाज में व्याप्त अमीर और गरीब के बीच स्थाई विभाजन को समाप्त करना।

मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेपः 1. समर्थकों का मानना है कि यदि बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त छोड़ दिया जाए तो बाजार के लेनदेन का योग समाज में लाभो और कर्तव्यों के समग्र वितरण को सुनिश्चित करेगा। हालांकि कुछ समर्थक राज्य के हस्तक्षेप को स्वीार करते हैं ताकि समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा हो सके।

2. निजी एजेंसियों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें।

मुख्य बिन्दुः

1. न्याय का अर्थ
2. न्याय के विभिन्न आयाम
3. सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांत
4. न्यायपूर्ण बंटवारा
5. रॉल्स का न्याय सिद्धांत
6. सामाजिक न्याय का अनुसरण
7. मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप
8. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाये गए कदम।

– न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्त्तव्यों का बंटवारा किया जाता है।

– प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुडा था जिसकी स्थापना राजा का परम कर्त्तव्य था।

– चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशस के अनुसार गलत करने वालों को दण्डित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिये।

– प्लेटों ने अपनी पुस्तक 'द रिपब्लिक' में न्याय की चर्चा की है।

– सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जायेगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

– साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है।

– जर्मनी दार्शनिक इमैनुएल के अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिये अवसरों की प्राप्ति है।

न्याय के विभिन्न आयाम

न्याय का अर्थ—न्याय को अंग्रेजी भाषा में ''जस्टिस'' (JUSTICE) कहा जाता है। ''जस्टिस'' (Justice) लेटिन भाषा के शब्द "jus" सेबना है, जिसका अर्थ है—''बंधन'' या ''बांधना'' (Bouind or Tie) इसका अर्थ है कि ''न्याय'' उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा होता है। अतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसका ''उचित'' हक देने से संबंध रखता है।

प्लेटो के अनुसार–''न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।''

न्याय के विभिन्न आयाम

1. **विधिक न्याय** : यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहां, न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है।

2. **राजनीतिक न्यायः** किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

3. **सामाजिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

4. **आर्थिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है, जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैस भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है।

   जहां राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से संबंद्ध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय ''समानता'' तथा सामाजिक

न्याय ''भ्रातृत्व'' के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

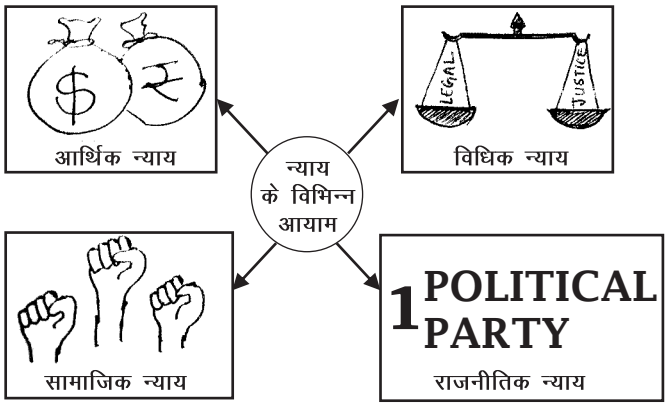

सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांतः–

- **समान लोगों के प्रति समान बर्तावः** सभी के लिये समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग जाति नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिये अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम कर रहें हो तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
- **समानुपातिक न्यायः** कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां समान बर्ताव अन्याय होगा जैसा परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिये जायें। यह न्याय नहीं हो सकता अतः मेहनत कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग–अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा।
- **विशेष जरूरतों का विशेष ख्यालः** जब कर्त्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाये तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए।

न्यायपूर्ण बंटवाराः–

- सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सकें, जैसा भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये भूमि सुधार जैसे कदम है।

रॉल्स का न्याय सिद्धांतः–

– ''अज्ञानता के आवरण'' द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो, कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी? और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाये तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनायेगा, जिसमें 'समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी।

सामाजिक न्याय का अनुसरणः–

– सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरम्यान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिये जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां–आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम–मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है।

मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेपः–

– मुक्त बाजार, खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना, राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये? क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये उठाये गये कदमः–

– निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।
– पंचवर्षीय योजनाएं।
– अन्तयोदय योजनाएं।
– वंचित वर्गो को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा।
– मौलिक अधिकारों में प्रावधान।
– राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास।
– प्रधानमंत्री उज्जवला योजना।
– किसान फसल बीमा योजना।
– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एक अंकीय प्रश्न)

1. समस्य समाज को बराबर की अहमियत मिले और प्रतिभा के विकास के लिए समान अवसर मिलने की स्थिति को क्या कहते हैं?

   (a) समानता (b) स्वतंत्रता

   (c) धर्म (d) न्याय

2. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ किसको जोड़कर देखा जाता था?

   (a) शिक्षा (b) धर्म

   (c) संस्कृति (d) समुदाय

3. प्राचीन भारतीय समाज में न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना किसका प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था।

   (a) न्यायालय (b) राजा

   (c) मंत्री (d) सेना

4. गलत करने वालों को दंडित और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। यह कथन किसका है?

   (a) प्लेटो (b) कन्फ्यूशियस

   (c) सुकरात (d) अरस्तु

5. ''द रिपब्लिक'' पुस्तक के लेखक थे?

   (a) अरस्तु (b) सुकरात

   (c) प्लेटो (d) लॉक

6. निम्न में से कौन सुकरात का शिष्य था?

   (a) अरस्तु (b) लास्की

   (c) रूसो (d) ग्लाउकॉन

7. प्लेटो का संबंध ..... से था।

   (a) ईरान (b) इराक

   (c) यूनान (d) लेबनान

8. यदि एक स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज्यादा वेतन मिलता है, तो यह किस सिद्धांत के विरूद्ध है?

(a) स्वतंत्रता के विरूद्ध

(b) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के विरूद्ध

(c) समकक्षों के साथ समान बर्ताव सिद्धांत के विरूद्ध

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. किसी काम कें लिए वांछित मेहनत, कौशल और संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग काम के लिए अलग–अलग पारिश्रमिक का निर्धारण कहलायेगा?

(a) अन्याय संगत

(b) न्याय संगत

(c) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के विरूद्ध

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

10. जिन लोगों में शारीरिक विकलांगता हो, या जिन तक अभी अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची, उनको न्याय किस माध्यम से दिया जा सकता है?

(a) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव द्वारा

(b) समानता के अधिकार द्वारा

(c) विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल द्वारा

(d) उपरोक्त सभी

11. भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासः

(a) छुआछुत की प्रथा का उन्मूलन

(b) भूमि सुधार कानून लागू करना

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

12. भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में या सरकारी नौकरी में सीट आरक्षण का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था?

(a) सरकारिया आयोग (b) मंडल आयोग

(c) शाह आयोग (d) जैन आयोग

13. सुकरात कौन था?

(a) राजनीतिज्ञ (b) राजा

(c) दार्शनिक (d) अर्थशास्त्री

14. न्याय के सिद्धांत हैं–

(a) समानुपातिक न्याय

(b) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. ''न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।'' उपरोक्त कथन किसका है?

(a) महात्मा ज्योति राव फूले (b) महात्मा गांधी

(c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (d) डॉ. बी आर अंबेडकर

16. जॉन रॉल्स ने ..... का सिद्धांत दिया।

(a) समानता का (b) न्याय का

(c) संपत्ति का (d) स्वतंत्रता का

17. जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उपरोक्त विचार है.....

(a) मुक्त बाजार के समर्थकों का (b) समाजवादियों का

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

18. समाज में बेहिसाब धन दौलत रखने वालों एवं वंचितों के बीच गहरी खाई किस बात का प्रतीक है?

(a) अवसर का अभाव (b) सामाजिक न्याय का अभाव

(c) समानता का अभाव (d) उपरोक्त कोई नहीं

19. अभिकथनः भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

कारणः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के साथ–साथ जनसामान्य की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

(a) अभिकरण और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

20. अभिकथनः न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है।

कारणः निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय देने के लिए न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

21. न्याय (JUSTICE) शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई?

(a) यूनानी भाषा (b) जापानी भाषा

(c) लेटिन भाषा (d) अरबी भाषा

22. ''न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।'' न्याय की यह परिभाषा किसने दी है?

(a) लास्की (b) प्लेटो

(c) अरस्तु (d) रूसो

23. ''न्याय पूर्ण कानून का निर्माण'' किस न्याय का पहलू है?

(a) राजनीतिक न्याय (b) सामाजिक न्याय

(c) आर्थिक न्याय (d) कानूनी न्याय

24. जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है?

(a) द थ्योरी ऑफ जस्टिस (b) द रिपब्लिक

(c) द डेमोक्रेसी (d) द पॉलिटिक्स

25. भारत में पिछड़ों / दलितों के शोषण का उदाहरण किस प्रकार के अन्याय का है?

(a) आर्थिक अन्याय (b) सामाजिक अन्याय

(c) सामाजिक अन्याय (d) धार्मिक अन्याय

26. सुकरात ने कहा है कि न्याय ने तमाम लोगों की ..... निहित रहती है।

27. सत्य और स्वतंत्रता न्याय के आधारभूत ..... में शामिल हैं।

28. वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन ..... ने किया।

29. भारत के संविधान का अनुच्छेद ..... कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।

30. ''न्याय पूर्ण समाज वह है, जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। इस कथन के लेखक कौन है?

31. ''न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है, जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है।'' इस कथन के लेखक का नाम लिखिए।

32. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें–

मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो, व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरें के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जा, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा।

बहु विकल्पीय प्रश्नः–

32.1 ''मुक्त बाजार'' से क्या आशय है?

(A) उद्यमों को प्रोत्साहित करना

(B) उद्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना

(C) उद्यमों को सरकारी नियंत्रण में रखना

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32.2 बाजारों में अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता हैं?

(A) जब बाजारों पर नीजी क्षेत्र के लिए प्रतिबंध हो

(B) जब बाजारों पर राज्य/सरकार का प्रतिबंध हो

(C) जब बाजारों पर राज्य/सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32.3 मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है?

(A) बाजारों को लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु

(B) बाजारों को लाभ की न्यूनतम मात्रा हासिल करने हेतु

(C) बाजारों में काम करने वाले मजदूरों को अधिकतम लाभ हो

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32.4 बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देने से क्या लाभ होगा?

(A) बाजारों में दुकानदारों को अधिक नुकसान होगा

(B) बाजारों में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी।

(C) समाज में लाभ और कर्त्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण होगा

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

33.1 ''मुक्त बाजार'' से क्या आशय है?

33.2 बाजारों में अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता हैं?

33.3 मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है?

33.4 बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देने से क्या लाभ होगा?

34. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

प्राचीन भारतीय समाज में न्याय अधर्म के साथ जुड़ा था।

35. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिए–

(i) तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है।

(ii) प्लेटों ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है।

(iii) न्याय के लिए जरूरी है कि तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें।

(iv) संसद में एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि संसद की कुल सीटों में से दो तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए।

(v) राल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया है।

35. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधी अवधारणा क्या थी?

36. साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ समझाइए।

37. न्याय को बढ़ावा देने का तरीका क्या हो सकता है?

38. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से क्या अभिप्राय है?

39. न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी?

40. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में जो आंदोलन चला उसका क्या नाम था?

41. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है?

42. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है?

43. व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं कौन–कौन सी होती हैं?

44. भारत में बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच न होने के कारण, कौन से समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. सामाजिक न्याय ..... व ..... का सामंजस्य है।

2. रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य समझाइये।

3. समानता व सामाजिक न्याय के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिये।

4. न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है?

5. न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा से क्या अपेक्षा की जाती है?

6. संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाईयों ने न्यूनतम आवश्यकताओं में किन सुविधाओं की गणना की है?

7. मुक्त बाजार से क्या अभिप्राय है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. न्याय में देरी होना अंधेर होना है। उक्त वाक्य का अर्थ समझाइये।

2. न्याय अपने आप में सम्पूर्ण प्रक्रिया है फिर भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया गया है?

3. मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिये।

4. हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है?

5. न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमनुएल कांट के विचार लिखिये।

पांच अंकीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नः—

1. प्रस्तुत कॉर्टून पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

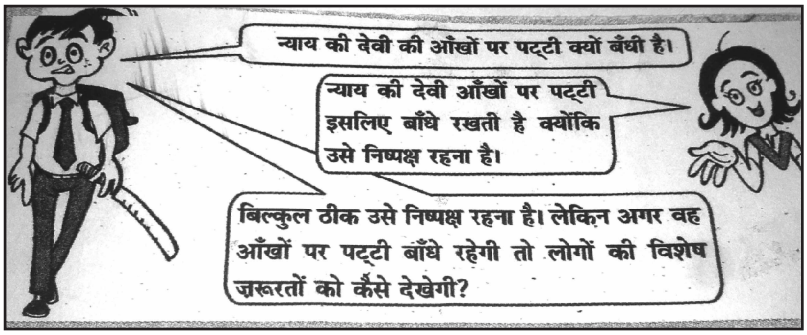

1.1 न्याय से क्या तात्पर्य है?

(A) हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना

(B) हर व्यक्ति को उपहार देना

(C) हर व्यक्ति को निःशुल्क आवास देना

(D) हर व्यक्ति को निःशुल्क पानी, बिजली देना

1.2 विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है?

(A) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान है। उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए।

(B) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है। उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए।

(C) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में महत्वपूर्ण हो उन्हें सम्मान दिया जाएग।

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

1.3. क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत न्याय के मार्ग में अवरोध पैदा करता है?

(A) हाँ (B) नहीं

(C) (A) और (B) (D) उपरोक्तस में से कोई नहीं

छः अंकीय प्रश्नः—

1. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले तीन सिद्धांत पर प्रकाश डालिये।
2. राल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिये।
3. मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है। विस्तार से समझाइये।
4. न्याय के विभिन्न आयामों का सविस्तार वर्णन कीजिए।

उत्तरमाला

वस्तुनिष्ठ/एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः

1. (d) न्याय
2. (b) धर्म
3. (b) राजा
4. (b) कन्फ्यूशियस
5. (c) प्लेटो
6. (d) ग्लाउकॉन
7. (c) यूनान
8. (c) समकक्षों के साथ समान बर्ताव सिद्धांत के विरूद्ध
9. (b) न्याय संगत
10. (c) विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल द्वारा
11. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
12. (b) मंडल आयोग
13. (c) दार्शनिक
14. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
15. (d) डॉ. बी आर अम्बेडकर
16. (b) न्याय का
17. (a) मुक्त बाजार के समर्थकों का
18. (b) सामाजिक न्याय का अभाव
19. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।
20. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

21. (c) लेटिन भाषा
22. (b) प्लेटो

23. (d) कानूनी न्याय।

24. (c) प्लेटो

25. (a) द थ्यारी ऑफ जस्टिस

26. (b) सामाजिक अन्याय

27. भलाई

28. तत्वों

29. जॉन रॉल्स

30. तत्वों

31. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

32. जे.एस. मिल

32.1 (B) उद्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखाना।

32.2 (C) जब बाजारों पर राज्य / सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा।

32.3 (A) बाजारों को लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु।

32.4 (C) समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण होगा।

33. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था।

34. (i) सही (ii) गलत (iii) सही (iv) गलत (v) सही

35. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का कर्तव्य था।

36. साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक / हिस्सा दिया जाए।

37. पारिश्रमिक और कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल सिद्धांत न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है।

38. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से अभिप्राय है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव में किया जाए।

भिन्न–भिन्न वर्गों के दो व्यक्ति यदि एक ही काम करते हैं तो उन्हें समान परिश्रमिक मिलना चाहिए।

39. न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–1979) में लाई गई थी।

40. मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन–1990।

41. डॉ. बी आर अंबेडकर।

42. न्याय पूर्ण बंटवारे से अभिप्राय है कि लोगों में वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण हो।

43. व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं–भोजन, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम आवश्यक संसाधन जरूरी है।

44. भारत में बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच न होने के कारण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. व्यक्तिगत अधिकारों, सामाजिक अधिकारों

2. हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाये और साथ ही हमें यह भी पता न हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी तब हम ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिये हितकर होगा।

3. दोनों में घनिष्ठ संबंध है सामाजिक न्याय द्वारा समानता तथा समानता द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना होती है।

4. सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बंटवारे से है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के बीच होता है जिससे उन्हें जीने के लिये समान धरातल मिल सके।

5. न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिये न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ जरूर मुहैया करानी चाहिये ताकि स्वस्थ व सुरक्षित जीवन के साथ समान अवसर के जरिये अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।

6. भोजन, शुद्ध पानी, आवास, आय व शिक्षा।

7. मुक्त बाजार के समर्थक खुली प्रतिद्वंदिता के पक्षधर है। व्यक्ति को संम्पति अर्जित करने हेतु, मूल्य व मजदूरी के मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हामी है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. न्याय मे ंदेरी वास्तव में अंधेर ही है क्योंकि यदि पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिये लम्बे समय तक दर दर भटकता रहे तो उसका न्याय से विश्वास उठने

लगता है कभी कभी तो पीड़ित इंसाफ की उम्मीद लिये दुनिया से ही चला जाता हे।

2. लम्बे समय से चली आ रही जातिगत विभिन्नताओं के कारण न्याय की प्रक्रिया कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। इसीलिये सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर ही न्याय किया जाना चाहिए।

3. पक्षः बाजार व्यक्ति की जाति धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है।

   विपक्षः मुक्त बाजार ताकतवर धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत होता है जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिये अवसरों से वंचित होना हो सकता है।

4. बदलते समय व परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की आावश्यकताओं में भी बदलाव आया है। भूमण्डलीकरण व तकनीक के विस्तार ने व्यक्ति के जीवन में महान परिवर्तन ला दिये हैं इसी के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं भी बढ़ या बदल गई है।

5. इमैनुएल कांट के अनुसर हर व्यक्ति की गरिमा होती है इसलिये हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिये समान अवसर प्राप्त हो।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (A) हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना।

2. (B) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाये।

.3. (B) नहीं।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. 1) समान लोगों के बीच समान बर्ताव
   जरूरतमंदों के लिये जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों का प्रावधान।

   2) लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयास व कौशलों को मान्यता देना (समानुपातिक न्याय)

   3) विशेष जरूरतों का विशेष ख्यालः जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिये।

2. रॉल्स ने न्याय प्राप्ति के लिये 'अज्ञानता के आवरण' का सिद्धान्त दिया है यदि अज्ञानता में रहकर यह निर्णय लिया जाये कि समाज में न्याय कैसा होना चाहिये किस वर्ग के लिये क्या सुविधाएं होनी चाहिए तो व्यक्ति सबसे कमजोर या निचले वर्ग के लिये भी सर्वश्रेष्ठ नीति का चयन करेगा क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि इस समाज में उसका स्थान कहां होगा।

3. मुक्त बाजार के समर्थक राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी और खुली प्रतिस्पर्धा के पक्षधर है। उनके अनुसार इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अच्छा फल मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा।

4. **न्याय के विभिन्न आयामः**

(1) **विधिक न्यायः** यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहां, न्याय, विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है।

(2) **राजनीतिक न्यायः** किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

(3) **सामाजिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(4) **आर्थिक न्याय:** इसका अर्थ है सभी को उनके जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है, जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में समक्ष नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है।

जहां राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से संबंद्ध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय ''समानता'' तथा सामाजिक न्याय ''भ्रातृत्व'' के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करके में सहायक होगा।

अध्याय 12
अधिकार

अधिकारः किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है।

अधिकारों की उत्पत्ति

1. प्राचीन युग में: प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांतः (प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त/जन्म से प्राप्त अधिकार) जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।

2. आधुनिक युग में: प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य। मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण।

अधिकारों के प्रकार

- प्राकृतिक अधिकार
- नैतिक अधिकार
- कानूनी अधिकार

कानूनी अधिकार

- 1. मौलिक अधिकार
- नैतिक अधिकार
- नैतिक अधिकार
- कानूनी अधिकार

अधिकार और राज्य

- 1. अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि
- 2. अधिकारों की रक्षा राज्यों का दायित्व
- 3. किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं जब तक उसे राज्य मान्यता न दे।
- 4. राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और दुरूपयोग होने से भी रोकता है।

विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने मानव–अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया।

मुख्य बिन्दुः

1. अधिकार का अर्थ
2. मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा
3. अधिकारों क्यों आवश्यक है?
4. अधिकारों की उत्पत्ति
5. अधिकारों के प्रकार
6. अधिकारों की दावेदारी
7. कर्त्तव्य, कर्त्तव्यों के प्रकार
8. मानवाधिकार

अधिकार का अर्थः–

– अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई 'मांग' है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग अधिकार बन जाती है।

समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे, अधिकार का रूप नहीं ले सकतीं।

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणाः–

– विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 'सामान्य सभा' ने मानावाधिकरों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया गया है।

मानव अधिकार दिवस – 10 दिसम्बर

अधिकार क्यों आवश्यक है?

– व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए।

– लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए।

– व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए।

– व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए।

– अधिकार रहित व्यक्ति, बंद पिंजड़े में पक्षी के समान है।

अधिकारों की उत्पत्तिः–

1. प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत– जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति–प्राकृतिक अधिकार (17वीं और 18वीं शताब्दी)
2. आधुनिक युग में– प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य

   मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण

अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार | नैतिक अधिकार | कानूनी अधिकार

1. प्राकृतिक अधिकार : जन्म के समय मिला अधिकार
   जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति
2. नैतिक अधिकार : व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार माता–पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव
3. कानूनी अधिकार : जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है।

3.1 मौलिक अधिकारः

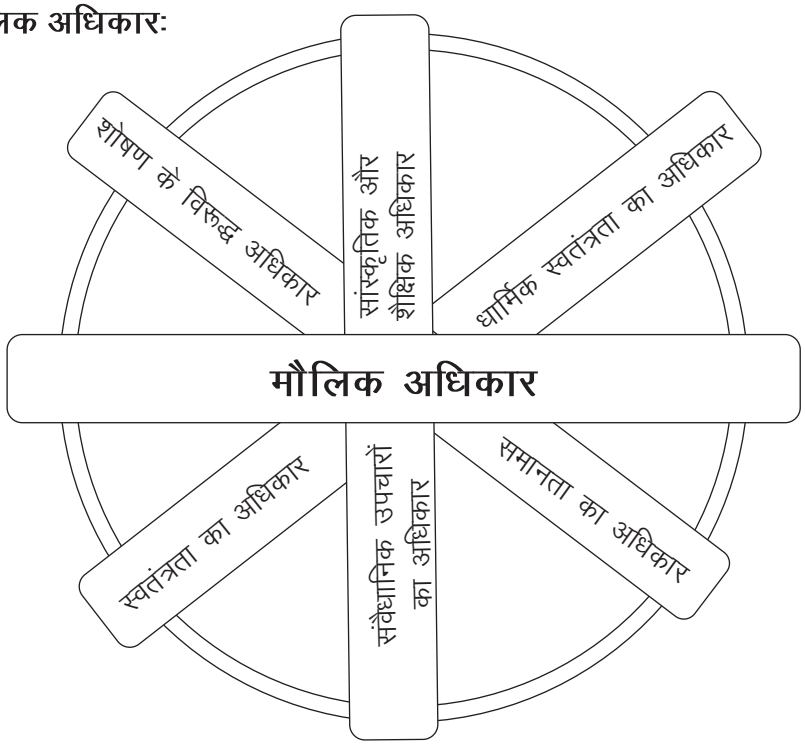

3.2 राजनैतिक अधिकार : (i) मत देने का अधिकार
(ii) निर्वाचित होने का अधिकार
(iii) सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार

3.3 नागरिक अधिकार : (i) देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता
(ii) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

3.4 आर्थिक अधिकार : (i) काम करने का अधिकार
(ii) संपत्ति खरीदने का अधिकार

अधिकारों की दावेदारी

– सार्वभौम अधिकार – शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

कुछ कार्यकलाप, जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकताः

– वे कार्यकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह हैं।

धूम्रपान

नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन

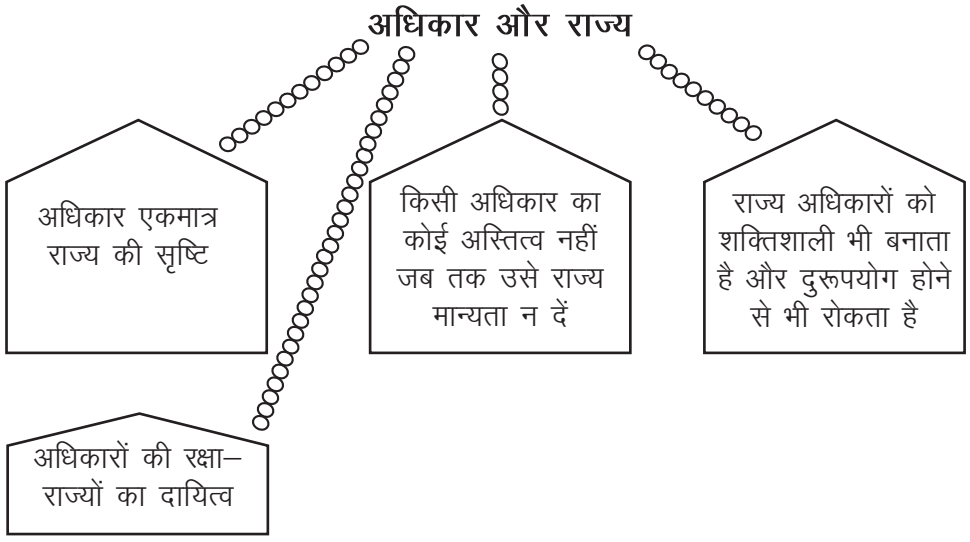

अधिकार और शक्तिशाली कैसे हों?

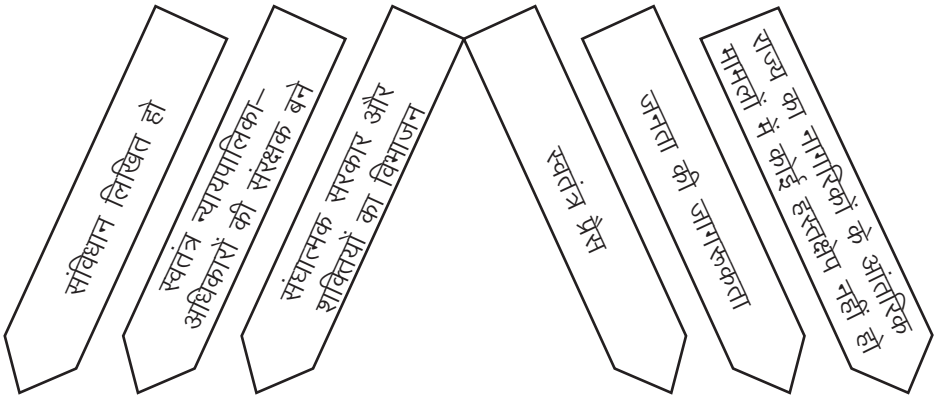

यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता हे तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अधिकारों के दुरूपयोग को रोके इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) में मौलिक कर्त्तव्यों का भी वर्णन किया गया है।

अधिकार और कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्त्तव्य। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते है। ये ऋण ही हमारे कर्त्तव्य हैं।

कर्त्तव्य के प्रकार

नैतिक कर्त्तव्य	कानूनी कर्त्तव्य
• अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्त्तव्य।	• संविधान का सम्मान करना।
	• राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
• बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना।	• कानून व व्यवस्था बनाए रखना
• माता–पिता व बुजुर्गों की सेवा करना	• नियमित रूप से 'कर' देना
• सामाजिक नियमों का पालन करना	• राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा
• परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना	• देश की एकता तथा अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना।
	• देश की रक्षा करना।
	• प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी पूर्ण उपयोग।
	• ओजोन परत की हिफाजत करना।

– **कुछ नए मानवाधिकारः–**

देश में नए खतरों और चुनौतियां से उभरने के लिए नए मानवाधिकारों की सूचीः

1) स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार
2) सूचना के अधिकार का दावा
3) महिला सुरक्षा का अधिकार
4) समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था
5) बच्चों को खाद्य, संरक्षण शिक्षा का अधिकार
6) सादा–जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियाँ

मानवाधिकारों की कीमतः–

– मनुष्य की सतत् जागरूकता।
– किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी है।
– अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं।
– नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहें, अपनी आँखे खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. अधिकार मूल रूप से एक ऐसा..... है जिसका औचित्य सिद्ध हो।

   (a) दावा (b) मांग

   (c) कर्तव्य (d) अधिकार

2. 17वीं–18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों का तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार ..... प्रदत्त हैं।

   (a) प्रकृति द्वारा (b) ईश्वर द्वारा

   (c) प्रकृति या ईश्वर द्वारा (d) उपरोक्त में से कोई भी

3. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा ..... अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है।

   (a) राजनीतिक (b) राजनीतिक

   (c) आर्थिक (d) सांस्कृतिक

4. अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं..... अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरूआत करती हैं।

(a) सामाजिक (b) राजनीतिक

(c) आर्थिक (d) सांस्कृतिक

5. 10 दिसंबर ..... को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया।

(a) 1945 (b) 1947

(c) 1948 (d) 1960

6. आधुनिक काल में प्राकृतिक अधिकार हैं:

(a) स्वीकार्य (b) अस्वीकार्य

(c) कानूनी (d) उपरोक्त में कोई नहीं

7. मानव अधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हैं.....

(a) महत्वपूर्ण (b) महत्वहीन

(c) सामान्य (d) विशिष्ट

8. निर्वाचित होने का अधिकार, किस श्रेणी में आता है?

(a) प्राकृतिक अधिकार (b) सामाजिक अधिकार

(c) राजनीतिक अधिकार (d) सांस्कृतिक अधिकार

9. ''काम'' का अधिकार है:

(a) सामाजिक (b) आर्थिक

(c) राजनीतिक (d) नैतिक

10. हमें सृजनात्मकता और मौलिक होने का अधिकार कौन देता है?

(a) समानता का अधिकार (b) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(c) अभिव्यक्ति का अधिकार (d) शोषण के विरूद्ध अधिकार

12. हमारी तर्कशक्ति विकसित करने में सहयोग करने वाला अधिकार है–

(a) समानता का अधिकार (b) शिक्षा का अधिकार

(c) अभिव्यक्ति का अधिकार (d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

13. 17वीं, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने मनुष्य के कौन–से अधिकारों को चिह्नित किया था–

(a) जीवन का अधिकार (b) स्वतंत्रता का अधिकार

(c) संपत्ति का अधिकार (d) उपरोक्त सभी

14. ''सभी लोग, मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के लिए अधिकारी हैं।'' यह मूल मान्यता है–

(a) मानवाधिकारों की (b) नैतिक अधिकारों की

(c) सामाजिक अधिकारों की (d) राजनीतिक अधिकारों की

15. दास प्रथा के उन्मूलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है?

(a) प्राकृतिक अधिकारों की (b) सामाजिक अधिकारों की

(c) मानवाधिकारों की (d) राजनीतिक अधिकारों की

16. शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार, अधिकारों की किस श्रेणी में आता है?

(a) सामाजिक अधिकार (b) आर्थिक अधिकार

(c) सांस्कृतिक अधिकार (d) मानवाधिकारों की

17. किस सकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी का निर्माण होता है.....

(a) नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार द्वारा

(b) नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार द्वारा

(c) नागरिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार द्वारा

(d) नागरिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार द्वारा

18. अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अधिकारों की किस श्रेणी में आता है–

(a) स्वतंत्रता का अधिकार (b) समानता का अधिकार

(c) शोषण के विरूद्ध (d) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार

19. लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण कौन करता है?

(a) कर्तव्य (b) अधिकार

(c) दावे (d) उपरोक्त में कोई नहीं

20. प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर आधारित स्टिंग ऑपरेशन को टेलीविजन पर दिखाना किस अधिकार का अतिक्रमण है?

(a) निजता के अधिकार का (b) स्वतंत्रता के अधिकार का

(c) समानता के अधिकार का (d) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार

21. अभिकथनः 18वीं सदी में जर्मनी में महान दार्शनिक ''इमैन्युएल कांट'' थे।

कारणः महान दार्शनिक ''इमैन्युएल कांट'' के अनुसार–'हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं।''

(a) अभिकरण और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

22. अभिकथनः पूरी दुनिया के उत्पीड़िन जन सार्वभौम मानवाधिकारों की अवधारणा का लाभ उठा रहे हैं।

कारणः विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

23. अभिकथनः 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव–अधिकारों की सार्वभौमिक घोषण को स्वीकर करते हुए विश्व से इनपर अमल करने की अपील की।

मानवः मानवाधिकारों के दावों की नैतिक अपील की सफलता विश्व के देशों की सरकारों एवं कानूनों पर निर्भर करती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

24. अभिकथनः अधिकार सिर्फ यह ही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है।

कारणः राज्य किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे न्यायालय के समक्ष उसके कारण बताने पड़ेंगे।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

25. अभिकथनः अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है।

कारणः लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

26. अधिकार किसे कहते हैं?

27. अधिकार किन बातों का द्योतक है?

28. 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अधिकारों की उत्पत्ति कहां से बताई थी?

29. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा किस ''अधिकार–शब्द'' का प्रयोग हो रहा है?

30. मानव अधिकारों के पीछे ''मूल–मान्यता'' क्या है?

31. मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र किसने बनाया है?

32. विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?

33. मानव के जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है?

34. भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों का क्या महत्व है?

35. शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों कहा जाता है?

36. कर्तव्य से आप क्या समझते हैं?

37. मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों में कोई एक अंतर लिखिए।

38. कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए।

39. किन्हीं दो नैतिक कर्तव्यों का नाम लिखिए।

40. ''हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं।'' अधिकार की यह नैतिक अवधारण किस दार्शनिक की है?

(a) लास्की (b) अरस्तु

(c) कांट (d) लॉक

41. प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है?

(a) वे अधिकार जो प्राचीनकाल में राजा के द्वारा दिए जाते थे।

(b) वे अधिकार जो राज्य की ओर से नागरिकों को दिए जाते हैं।

(c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

(d) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

42. प्राकृतिक अधिकार का समर्थन क्या है:

(a) कार्ल मार्क्स ने (b) लॉक ने

(c) अरस्तु ने (d) मैक्यावली ने

43. जीवन का अधिकारः

(a) सामाजिक अधिकार (b) आर्थिक अधिकार

(c) राजनीतिक अधिकार (d) सांस्कृतिक अधिकार

44. ''अधिकार उन समाजिक व्यवस्थाओं का नमा है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में विकास नहीं कर सकता''। यह कथन किसका है

(a) मैक्यावली (b) अरस्तु

(c) आइंस्टीन (d) लास्की

45. मतदान करने का अधिकार है:

(a) सामाजिक अधिकार (b) राजनीतिक अधिकार

(c) आर्थिक अधिकार (d) नैतिक अधिकार

खाली स्थान भरो:

46. ..... सामाजिक जीवन की भी अनिवार्य परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

47. काम का अधिकार ..... अधिकार है।

48. भारत में राजनीतिक अधिकार ..... वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु के नागरिकों को प्राप्त होता है।

49. किसान कृषि कानूनो के खिलाफ सरकार की आलोचना ..... अधिकार के तहत कर रहे हैं।

50. ..... दिसंबर ..... को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया।

51. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

''आज संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकारों की विश्व–जननीय घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एतदर्थ घोषित करती है कि–प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा–पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता, स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकास की ओर उन्मुख राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्व–देशिक तथा सशक्त स्वीकृति आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा।''

51.1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी?

(a) 1940 (b) 1945 (c) 1950 (d) 1955

51.2 ''मानवाधिकारों के विश्व–जननीय घोषणा पत्र को'' संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने घोषित किया.....

(a) यूनिसेफ (b) सुरक्षा परिषद ने

(c) यूनेस्को ने (d) महासभा ने

51.3 संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किस माध्यम को उचित समझा.....

(a) मीडिया द्वारा (b) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा

(c) शिक्षा द्वारा (d) पत्राचार द्वारा

51.4 संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को किसके बीच स्थापित करने का आह्वान किया.....

(a) सदस्य देशों के बीच (b) गैर सदस्य देशों के बीच

(c) शिक्षा द्वारा (d) उपरोक्त में कोई नहीं

52. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

(a) शिक्षा प्राप्ति का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है।

(b) काम प्राप्ति का अधिकार एक सांस्कृतिक अधिकार है।

(c) भाषण का अधिकार एक आर्थिक अधिकार है।

(d) चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है।

(e) सम्मान के साथ रहने के लिए व्यक्ति को काम का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है

दो अंकीय प्रश्नः–

1. राजनीतिक अधिकारों में कौन–कौन से अधिकार शामिल है?
2. अधिकारों की सुरक्षा के कोई दो उपाय सुझाइए।
3. नागरिक के राज्य के प्रति किन्हीं दो कर्त्तव्यों को लिखिए।
4. एक नागरिक को कौन–कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त है?

5. निम्नलिखित का मिलान कीजिए–

a)	आर्थिक अधिकार	मत देने का अधिकार
b)	नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार	स्वतंत्रता का अधिकार
c)	राजनीतिक अधिकार	न्यूनतम भत्ता
d)	सांस्कृतिक अधिकार	मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

चार अंकीय प्रश्नः–

1. कर्त्तव्यों व अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? समझाइए।
2. नागरिक के किन्हीं चार राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करो।
3. अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगातें है? उदाहरण देकर समझाइए।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. निम्नलिखित चित्र और वार्तालाप को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो– [1+2+2=5]

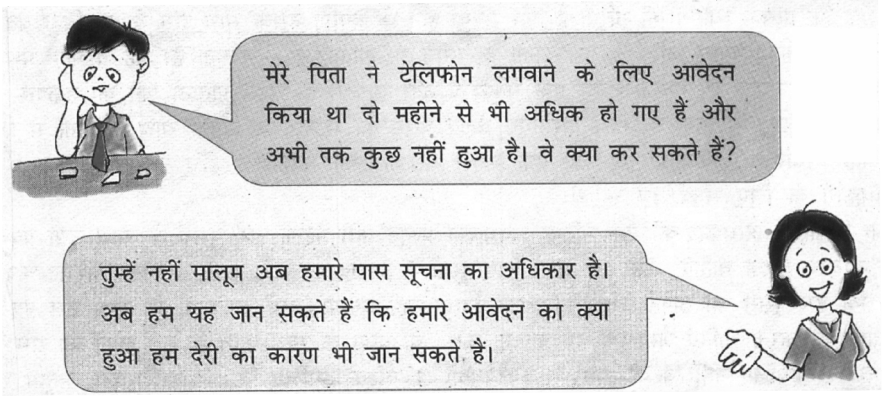

1.1 उपरोक्त चित्र किस अधिकार का दावा कर रहा है?

(A) काम का अधिकार (B) सूचना का अधिकार

(C) सम्पत्ति का अधिकार (D) मानव अधिकार

1.2 समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति को राहत कौन देता है?

(A) कार्यपालिका (B) व्यवस्थापिका

(C) न्यायपालिक (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

1.3 सूचना का अधिकार है–

(A) किसी भी विषय पर जानकारी इकट्ठा करना

(B) किसी भी विषय पर आँकड़े मिलान

(C) किसी भी विषय पर, संशय की परिस्थिति में जानकारी व आँकड़े प्राप्त करना

(D) इनमें से कोई नहीं

छः अंकीय प्रश्नः–

1. कर्त्तव्य किसे कहते हैं? एक अच्छे नागरिक के कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
2. अधिकार कितने प्रकार के हेाते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
3. अधिकार तथा कर्त्तव्यों में क्या संबंध है?
4. अधिकार व दावे में अंतर लिखो?

उत्तरमाला

वस्तुनिष्ठ (एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर)

1. (a) दावा
2. (c) प्रकृति या ईश्वर द्वारा
3. (d) मानव
4. (b) राजनीतिक
5. (c) 1948
6. (b) अस्वीकार्य
7. (a) महत्वपूर्ण
8. (d) प्राकृतिक
9. (c) राजनीतिक अधिकार
10. (b) आर्थिक
11. (c) अभिव्यक्ति का अधिकार

12. (b) शिक्षा का अधिकार

13. (d) उपरोक्त सभी

14. (a) मानवाधिकारों की

15. (c) मानवाधिकारों की

16. (d) मानवाधिकारों की

17. (a) नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार द्वारा

18. (d) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार

19. (b) अधिकार

20. (a) निजता के अधिकार का

21. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

22. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

23. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

24. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

25. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

26. अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग या दावा है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग ''अधिकार'' बन जाती है।

27. अधिकार उन बातों का द्योतक है जीने में और अन्य लोग सम्मान ओर गरीमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं।

28. 17 मई और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत कार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं।

29. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा ''मानवाधिकार–शब्द'' का प्रयोग हो रहा है।

30. मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग, मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पानी के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है।

31. मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया है।

32. प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को।

33. मानव के सर्वागीण विकास हेतु अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है।

34. भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों को ''मौलिक–अधिकार'' कहा जाता है।

35. क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सभी क्षेत्रों के विकास में सहयोगी होती है, इसलिए इस अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है।

36. अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई जाने वाली जिम्मेदारीयों को कर्तव्य कहते हैं।

37. मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं जबकि प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं।

38. कर्तव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैंः
(i) नैतिक कर्तव्य और (ii) कानूनी कर्तव्य

39. नैतिक कर्तव्य हैंः (i) सामाजिक नियमों का पालन करना (ii) बुजुर्गों की देखभाल करना।

40. (c) कांट

41. (c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

42. (b) लॉक ने

43. (a) सामाजिक अधिकार

44. (d) लास्की

45. (b) राजनीतक अधिकार

खाली स्थान भरो के उत्तर–

46. अधिकार

47. आर्थिक अधिकार

48. 18 वर्ष की आयु

49. राजनीतिक अधिकार

50. 10 दिसम्बर 1948

51. (i) (b) 1945

(ii) (d) महासभा ने।

(iii) (c) शिक्षा द्वारा

(iv) (c) सदस्य देशों की जनता के बीच

52. ''आजकल प्राकृतिक अधिकार से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है।

53. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः–

(a) सही (b) गलत (c) गलत (d) सही (e) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) मत देने का
   (ii) निर्वाचित होने का

2. (i) राज्य द्वारा
   (ii) स्वतंत्रत न्यायपालिका द्वारा

3. (i) संविधान का सम्मान
   (ii) कानून व व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग

4. (I) व्यवसाय चुनने, काम करने का अधिकार।
   (ii) सम्पत्ति खरीदने का अधिकार।

5. (i) आर्थिक अधिकार – न्यूनतम भत्ता
   (ii) सामाजिक अधिकार – स्वतंत्रता का अधिकार

(iii) राजनीतिक अधिकार – मत देने का अधिकार

(iv) सांस्कृतिक अधिकार – मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. अधिकार व कर्त्तव्य का नजदीकी संबंध अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य नहीं निभाता। कर्त्तव्य एक दायित्व है जो दूसरों को अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देता है।
2. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार।
3. राज्य अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

   जनता के हितों का ध्यान राज्य द्वारा क्योंकि जनता ही लोकतांत्रिक देशों में सरकार चुनती है

   अधिकार ही राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने का दायित्व देते हैं। अधिकार यह निश्चित करते है कि राज्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करें।

पाँच अंकीय प्रश्नों के उत्तर –

1 (B) सूचना के अधिकार का

(C) न्यायपालिका

(Ci) किसी भी विषय पर, संषय की परिस्थिति में जानकारी तथा आंकड़े प्राप्त करना।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

(सिर्फ Hint के लिए explanation विद्यार्थी स्वंय करें)

1. कर्त्तव्य एक दायित्व है। कर्त्तव्य हम दूसरों के प्रति निभाते हैं जिससे समाज का विकास होता है।

   कर्त्तव्यः– (i) शरीर मन स्वस्थ रखना

   (ii) शिक्षा

   (iii) माता पिता की सेवा

   (iv) राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना

(v) देश की सुरक्षा

(vi) राष्ट्र ध्वज तथा गान की गरिमा

2. (I) प्राकृतिक – जीवन, स्वतंत्रता

(ii) नैतिक – माता पिता की सेवा, बच्चों की शिक्षा

(iii) कानूनी– मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक

3. गहरे रूप से जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू कर्त्तव्य के बिना अधिकार लागू नहीं हो सकते। अपना अधिकार ही पहला कर्त्तव्य है।

4. (i) सभी दावे अधिकार नहीं होते परंतु सभी अधिकार दावे होते हैं।

(ii) अधिकार दावें है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सभी दावों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते है।

(iii) दावे–राज्य के संविधान द्वारा गारंटी नहीं।
मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान द्वारा।

अध्याय 13

नागरिकता

नागरिकताः नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता।

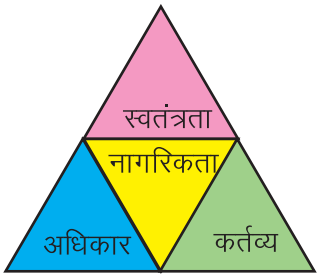

संपूर्ण और समान सदस्या

राजकृत नागरिकता के तरीकेः

1. पंजीकरण, 2. देसी कारण, 3. वंश परंपरा, 4. किसी भू क्षेत्र का राज्य क्षेत्र में मिलना

सार्वभौमिक नागरिकता/विश्व नागरिकता

मुख्य बिन्दुः

1. नागरिकता
2. सम्पूर्ण और समान सदस्यता
3. प्रवासी
4. प्रतिवाद के तरीके
5. नागरिक और राष्ट्र
6. राज्यकृत नागरिकता के तरीके
7. सार्वभौमिक नागरिकता
8. विस्थापन के कारण
9. शरणार्थी का अर्थ
10. विश्व नागरिकता
11. विश्व नागरिकता के लाभ

– भारतीय संविधान के भाग दो (अनुच्छेद 5–11) में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

– नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए है। इसलिए हम सबंद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वंय को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं।

– अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं।

– नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते है उन्हें उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि।

– नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित होते हैं।

– नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है।

संपूर्ण और समान सदस्यताः–

– इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहां चाहें रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर–गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना है।

प्रवासीः–

– काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा देश से दूसरे देश की ओर की जाते है, तब वे प्रवासी कहलाते है।

– निर्धन प्रवासियों का अपने–अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है।

– प्रतिवाद (विरोध) का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है बशर्ते इससे दूसरें लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।

प्रतिवाद के तरीकेः–

– नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर के, मीडिया का इस्तेमाल करके, राजनीतिक दलों से अपील करके या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है।

– समान अधिकारः शहरों में अधिक संख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जें की भूमि पर बसे लोगों की हैं। ये लोग हमारे बहुत काम के है । इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता, जैसे–सफाईकर्मी, फेरीवाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि।

– सरकार, स्वंय सेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे है। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ।

– इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह है आदिवासी और वनवासी समूह। ये लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं

– नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है–नीतियाँ बनाते समय भिन्न–भिन्न लोगों की भिन्न–भिन्न जरूरतों का तथा दावों का ध्यान रखना।

नगारिक और राष्ट्रः–

– कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देता है। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं।

– राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्ते प्रत्येक देश में पृथक होती है। जैसे–इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है।

– भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग–अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है।

– नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के तीसरे खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ हैं।

राज्यकृत नागरिकता के तरीके

1) पंजीकरण
2) देशीकरण
3) वंश परंपरा
4) किसी भू क्षेत्र का राजक्षेत्र में मिलना

सार्वभौमिक नगारिकताः–

– हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी है, वहां काम करते या जो नागरिकता के लिए आवदेन करते हैं किंतु नागरिकता देने की शर्ते सभी तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है।

विस्थापन के कारणः–

– युद्ध, अकाल, उत्पीड़न एवं महामारियों आपदाएँ।

शरणार्थी का अर्थः–

– विस्थापन के कारण जो लोग न तो घर लौट सकते है और न ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी कहलाते हैं।

विश्व नागरिकताः–

– आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। संचार के साधन, टेलिविजन या इंटरनेट ने हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया की सूनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावोद्‌गार विश्व समाज की उभार कि ओर इशारा करता है। इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है। यही 'विश्व ग्राम' व्यवस्था का आधार भी है।

विश्व नागरिकता से लाभः–

– इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा, जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। इससे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निबटान करना आसान हो सकता है।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एक अंकीय प्रश्न)

1. एक राजनीतिक समुदाय की ओर समान सदस्यता क्या कहलाती है?
   (a) राजनीतिक सदस्या (b) नागरिकता
   (c) नागरिकत अधिकार (d) सामाजिक सदस्यता
2. नागरिकता के माध्यमिक चुनौतियां हैं–
   (a) गरीबी (b) अशिक्षा
   (c) क्षेत्रवाद (d) उपरोक्त सभी
3. नागरिकता का गुण नहीं है–
   (a) आत्म संयम (b) सचरित्रता
   (c) कर्तव्य परायणता (d) अलगाववादी

4. यूरोप में समान नागरिकता पाने के लिए पहली क्रांति कब हुई?

(a) 1785 (b) 1789

(c) 1885 (d) 1889

5. दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की जनता को जिसके खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा।

(a) अफ्रीकी सेना के खिलाफ

(b) अफ्रीकी राजा के खिलाफ

(c) अफ्रीका में सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ

(d) उपरोक्त सभी

6. 17वीं शताब्दी से ..... शताब्दी के बीच यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा।

(a) 19वीं शताब्दी (b) 20वीं शताब्दी

(c) 21वीं शताब्दी (d) उपरोक्त में कोई नहीं

7. मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संबंध ..... देश से था?

8. 1950 का दशक अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में ..... और ..... आबादी के बीच नागरिक अधिकार आंदोलन का साक्षी है।

(a) उत्तरी..... दक्षिणी (b) पूर्वी..... पश्चिमी

(c) गोरी ..... काली (d) मैदानी ..... पहाड़ी

9. वर्ष ..... में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है।

(a) 2004 (b) 2006

(c) 2001 (d) 2008

10. अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल न ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' पुस्तक वर्ष ..... में लिखी।

(a) 1960 (b) 1918

(c) 1950 (d) 1980

11. राष्ट्रीय पहचान को व्यक्त किया जा सकता है.....

(a) राष्ट्रीय गान (b) झंडा

(c) राष्ट्रभाषा (d) उपरोक्त सभी

12. समाजशास्त्री टी एच मार्शल ने नागरिकता में कौन से तीन प्रकार के अधिकारों को जरूरी मानते हैं?

(a) नागरिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार

(b) सामाजिक, शैक्षिक और नागरिक अधिकार

(c) नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार

(d) नागरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार

13. फ्रांस देश है.....

(a) धर्मनिरपेक्ष

(b) समावेशी

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

14. ''नागरिकता'' से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है–

(a) भाग 1 (b) भाग 2

(c) भाग 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. ''नागरिकता'' प्रदान के में इजरायल देश में वरीयता दी जाती है.....

(a) धर्म को

(b) जाति को

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

16. भारत में नागरिकता प्राप्त होती है.....

(a) जन्म से (b) वंश–परंपरा से

(c) पंजीकरण से (d) उपरोक्त सभी

17. नागरिकता देने की शर्तें अक्सर देशों के संविधान और ..... में लिखी होती हैं।

(a) कानूनों (b) शर्तों

(c) ग्रंथों (d) उपरोक्त में कोई नहीं

18. किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए रहते हैं। उन्हें कहते हैं....

(a) कामगार (b) शरणार्थी

(c) गुलाम (d) उपरोक्त में कोई नहीं

19. एक देश के नागरिक काम की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं, उन्हें कहते हैं...

(a) शरणार्थी (b) प्रवासी

(c) नागरिक (d) उपरोक्त में कोई नहीं

20. प्रवासियों एवं राज्य–विहीन लोगों की समस्याओं का निपटारा आसान हो सकता है....

(a) विश्व नागरिकता देकर

(b) आर्थिक सहायता देकर

(c) रोजगार देकर

(d) सामाजिक सुरक्षा देकर

21. अभिकथनः नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न–भिन्न हो सकती है।

कारणः नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया गया है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

22. अभिकथन–यूरोप में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई।

कारणः फ्रांसीसी क्रांति की तर्ज पर एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशो में समान नागरिकता की मांग के लिए संघर्ष हुआ।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

23. अभिकथन–हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं।

कारण–सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में बेंगलुरू शहर की ओर कुशल कामगार जा रहे हैं।

(a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

24. अभिकथनः मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के अग्रणी काले नेता थौ

कारणः मार्टिन लूथर किंग ने दलील दी है कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

25. अभिकथन–भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टीयों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है।

कारण–शहर की अधिकांश आबादी झोपड़पट्टी वालों को अवांछनीय मेहमान की तरह दिखती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

26. नागरिकता की परिभाषा दीजिए।

27. ''नागरिक वह व्यक्ति है जिसको राज्य के कानून संबंधी विचार–विमर्श और न्याय प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है।'' यह परिभाषा किस विद्वान की है?

28. दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को किसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ा?

29. नागरिक की कोई एक विशेषता लिखिए।

30. भारतीय संविधान के किस ''भाग'' में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है?

31. शरणार्थी किसे कहा जाता है?

32. ''मुंबई–मुंबईकर के लिए'' नारे का क्या अर्थ है?''

33. बाहरी लोगों से क्या अभिप्राय है?

34. शहरी निर्धनों से क्या अभिप्राय है?

35. ''विश्व–नागरिकता'' की धारणा का आकर्षण बिंदु क्या है?

36. नागरिक अधिकारों के लिए विश्व की पहली क्रांति थी–

(a) रूसी क्रांति (b) फ्रांसीसी क्रांति (c) अमेरिकी क्रांति (d) जर्मन क्रांति

37. यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों पर अपना शासन कायम रखाः

(a) 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी (b) 16वीं सदी शताब्दी से 20 शताब्दी

(c) 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी (d) 18वीं शताब्दी से 20 शताब्दी

38. संयुक्त राज्य अमेरिका में काली और गोरी आबादी के बीच विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन किस दशक में चला?

(a) 1850 दशक (b) 1960 दशक

(c) 1860 दशक (d) 1950 दशक

39. निम्नलिखित में से कौन–सा राज्य की नागरिकता प्राप्त करने का साधन है?

(a) दीर्घकालीन आवास (b) सरकारी नौकरी

(c) विवाह (d) उपर्युक्त सभी

40. निम्नलिखित में से कौन–सा नागरिकता खोने का साधन है?

(a) दीर्घकालीन आवास (b) लंबी अनुपस्थिति

(c) विवाह (d) सरकारी नौकरी

41. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

''पृथक्करण कानूनों'' के खिलाफ हुए आंदोलन में अमेरिका के अब्राहम लिंकन जूनियर अग्रणी काले नेता थे।

42. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है। इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध का सर्व सम्मत सूत्री–करण अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने किया है। अपनी पुस्तक ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' में मार्शल ने नागरिकता को ''किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत प्रतिष्ठा'' के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। नागरिकता की मार्शल प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना ''समानता'' की है। मार्शल नागरिकता

में तीन प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं—नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को ''असमानता की व्यवस्था'' के रूप में चिह्नित किया है।

42.1 टी.एच. मार्शल है—

(a) अर्थशास्त्री (b) समाजशास्त्री (c) राजनीतिज्ञ (d) इतिहासकार

42.2 ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' पुस्तक के लेखक हैं—

(a) टी एच ग्रीन (b) टी एच साल्वे (c) समानता (d) टी एच मार्शल

42.3 नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना हैं:

(a) नागरिक (b) सरकार (c) समानता (d) स्वतंत्रता

42.4 मार्शल नागरिकता में कितने प्रकारों के अधिकारों को शामिल करते हैं?

(a) दो प्रकार के अधिकार (b) तीन प्रकार के अधिकार

(c) चार प्रकार के अधिकार (d) छः प्रकार के अधिकार

खाली स्थान भरो:—

43. भारतीय संविधान के अनुच्छेद .....से ..... में नागरिकता सं संबंधित प्रावधानपों का वर्णन किया गया है।

44. अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को ..... अधिकार दिए जाते हैं।

45. काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तब वे ..... कहलाते हैं।

46. राज्य नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में .. होती हैं।

47. भारतीय संविधान में बहुत ही ..... समाजको समायोजित करने की कोशिश की है।

48. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिए:—

(a) नागरिक शब्द अंग्रेजी के सिटीजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है।

(b) स्थानीय लोग ''बाहरी लोगों'' की प्रतिद्वन्दिता से नाराज होते हैं।

(c) 1960 का दशक अमेरिका में विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन का साक्षी था

(d) मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी गोरे नेता थे।

(e) विश्व नागरिकता की धारणा ''वसुदेव—कुटुंबकम'' पर आधारित है।

दो अंकीय प्रश्नः–

1. एक नागरिक का दूसरे नागरिकों के प्रति क्या कर्त्तव्य है?
2. रंगभेद की नीति से क्या अभिप्राय है?
3. समान सदस्यता से क्या अभिप्राय है?
4. नागरिक किस प्रकार प्रतिवाद या विरोध कर सकते हैं?
5. आदिवासी तथा वनवासियों के क्या अधिकार हैं?
6. ''कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते है'' इस कथन का आशय स्पष्ट करें।
7. नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके बताइए।
8. नागरिकता खो जाने के दो कारण बताइए।
9. लोग विस्थापित क्यों होते है दो कारण बताइए।
10. भारत में विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करों।

चार अंकीय प्रश्नः–

1. एक नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर है?
2. एक अच्छे नागरिक में क्या–क्या गुण होने चाहिए। अपने विचार दें।
3. सार्वभौमिक नागरिकता से क्या अभिप्राय है? कुछ शरणार्थी लोगों के उदाहरण दीजिए।
4. विश्व नागरिकता आज एक आकर्षण बनी है। कैसे?
5. भारत में एक जातिगत तथा एक पर्यावरणीय आंदोलन का वर्णन करो।
6. शरणार्थियों को किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
7. 'बाहरी तथा भीतरी' की समस्या का वर्णन करो।
8. आज विश्व एक विश्व ग्राम की भांति बदल रहा है? कैसे?
9. नागरिक और सामाजिक अधिकार क्या है?
10. शहरी गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. दिए गए चित्र/कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन किजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मधयवर्ग के जीवन का एक दिन

(a) प्रवासी किसे कहते हैं? (1)

(b) प्रवासी लोग शहरों में कौन–कौन से काम करते हैं? (2)

(c) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। (2)

छः अंक वाले प्रश्नः–

1. ''आज नागरिक को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है''। सिद्ध करो।
2. ''समान सदस्यता मिलने का अर्थ यह नहीं कि सभी उसका समान प्रयोग कर सकें'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित दीजिए।
3. ''लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कि विवादों का निदान बल प्रयोग की अपेक्षा संधि–वार्ता तथा विचार विमर्श से हो'' आपके अनुसार क्या यह तरीका विश्व नागरिकता को बढ़ावा देगा।
4. ''भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है'' कैसे।

उत्तरमाला

वस्तुनिष्ठ (एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर)

1. (b) नागरिकता
2. (d) उपरोक्त सभी
3. (d) अलगाववादी
4. (b) 1789
5. (c) अफ्रीका में सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ
6. (b) 20वीं शताब्दी
7. (d) अमेरिका
8. (c) गोरी..... काली
9. (a) 2004
10. (c) 1950
11. (d) उपरोक्त सभी
12. (c) नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार
13. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
14. (b) भाग–2
15. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
16. (d) उपरोक्त सभी
17. (a) कानूनों

18. (b) शरणार्थी

19. (b) प्रवासी

20. (a) विश्व नागरिकता देकर

21. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

22. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

23. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और अभिकथन की सही व्याख्या है।

24. (d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

25. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

26. नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है।

27. अरस्तु

28. दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीाक की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा।

29. नागरिक को राज्य की ओर से अधिकार मिले होते हैं, जिनका वह अपने और समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करता है।

30. भारतीय संविधान के ''भाग दो'' (अनुच्छेद 5–11) में नागरिकता से संबंधित है प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

31. अकाल, प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण हुए विस्थापित लोगों को ''शरणार्थी'' कहा जाता है।

32. ''मुंबई–मुंबईकर के लिए'' नारे का अर्थ है कि मुंबई में केवल मुंबई के ही लोग रहेंगे बाहर के लोग नहीं।

33. जो लोग समाज और सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें बाहरी लोग कहा जाता है।

34. शहरी क्षेत्रों में अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोग या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, जो अक्सर कम मजदूरी पर काम करते हैं, उन्हें शहरी निर्धन कहते हैं।

35. विश्व नागरिकता की धारणा का आकर्षण बिन्दु यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है।

36. (b) फ्रांसीसी क्रांति

37. (c) 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी

38. (d) 1950 दशक

39. (d) उपर्युक्त सभी

40. (b) लंबी अनुपस्थिति

41. ''पृथक्करण कानूनों'' के खिलाफ हुए आंदोलन में अमेरिका के ''मार्टिन लूथर किंग जूनियर'' अग्रणी काले नेता थे।

42.1 (b) समाजशास्त्री

42.2 (d) टी एच मार्शल

42.3 (c) समानता

42.4 (b) तीन प्रकार के अधिकार

43. अनुच्छेद 5 से 11

44. अभिव्यक्ति का अधिकार / मतदान का अधिकार / आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार / शिक्षा का अधिकार / न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार।

45. प्रवासी

46. भिन्न–भिन्न / प्रथक–प्रथक।

47. विविधतापूर्ण (समाज)

48. (a) सही (b) सही (c) गलत (d) गलत (e) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे दूसरें नागरिकों के अधिकारें का सम्मान करें। रोजमर्रा के जीवन में उन्हें सम्मिलित होने और योगदान करने का दायित्व शामिल हैं

2. गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव दक्षिण अफ्रिका का उदाहरण।

3. राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को चाहें वे धनी हो या निर्धन कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देना।

4. समूह बनाकर, प्रदर्शन, धरना, मीडिया का प्रयोग, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखना और प्रभावित करना।

5. उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के साथ रहने का अधिकार, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का

अधिकार।

6. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

7. राज्यकृत नागरिकता।

   (i) विवाह द्वारा

   (ii) नौकरी द्वारा

   (iii) आवेदन द्वारा

8. (i) देशद्रोही क्रियाकलाप द्वारा

   (ii) विवाह द्वारा

9. अकाल, बाढ़, युद्ध, सुनामी, महामारी जैसी समस्याओं से।

10. सरदार सरोवर बांध का वर्णन।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. नागरिक – देश के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है वह मतदान, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

   विदेशी– विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं।

2. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

3. किसी देश की पूर्ण सदस्यता, सभी को उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते है और काम करते हैं तथा जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। बांग्लादेशी आदि....।

4. क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन दिक्कतों का सामना करना, सरल हो सकता है जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। विजय माल्या का उदहारण।

5. जातिगत आंदोलन – दलित पैथर्स

   पर्यावरणीय आंदोलन – चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओं आंदोलन

6. (i) कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता।

   (ii) वे शिवरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश किए जाते है।

(iii) वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या

(iv) संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।

7. भीतरी– जो समाज से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और सरकार से नागरिकता के अधिकार।

बाहरी– जो समाज व राज्य से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते।

8. विश्व ग्राम– हम सब संचार के नए माध्यमों द्वारा जैसे टेलिविजन, इंटरनेट आदि से एक दूसरे से जुडाव अनुभव करते हैं आज विश्व के तमाम राष्ट्रों के लोगों में साझे सरोकर एवं भाईचारे की भावना का विकास हो रहा है।

9. नागरिक अधिकार– आस्था और स्वतंत्रता के अधिकार

सामाजिक अधिकार– न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा प्राप्त करने, किसी भी जगह घूमने फिरने की आजादी।

10. (i) 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई ताकि फुटपाथी दुकानदारों को पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न न झेलना पड़ा।

(ii) संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गांरटी दी गई है जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (क) काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर अथवा एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है।

(ख) प्रवासी लोग शहरी में घरेलू नौकर, सफाई, कर्मचारी, समाचार पत्र वितरक, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचना, फेरी लगाकर सामान भेजना, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली छोटी–छोटी वस्तुओं को साप्ताहिक बाजारों में बेचना आदि काम करते हैं।

(ख) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो सकता है, शहरी लोगों के रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी कोरोनावायरस के काल में जब घरेलू नौकर/ नौकरानीया छूट्टी पर चली गई तथा लॉक डाउन लग गया तो शहरी लोगों का जीवन बदहाल हो गया था। शहरी लोगों के जीवन में प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, छोटे–छोटे कामों के लिए शहरी लोग प्रवासियों पर ही आश्रित होते हैं।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति।

   (ii) एशिया अफ्रीका में भी समान नागरिकता की मांग, संघर्ष से ही प्राप्त की।

   (iii) दक्षिण अफ्रीका मे भी अश्वेत जनसंख्या को सत्तारूढ़ श्वेत अल्पसंख्यकों के विरूद्ध लम्बा संघर्ष किया।

2. अधिकांश समाजों में लोगों की योग्यताओं और सामर्थ्य के आधार पर संगठन पाया जाता है लोगों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण तथा मौलिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की दृष्टि से अलग हो सकते है। यदि लोगों को समानता पर लाना है तो नीतियों का निर्धारण करते वक्त लोगों की भिन्न–भिन्न जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।

3. हाँ, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है इसके लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है अगला चरण सरकार का प्रतिवाद हो सकता है परन्तु शर्त है कि अन्य नागरिकों व सरकार के जीवन व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध की प्रक्रिया धीमी हो सकती हे पर वार्ता द्वारा या संधि द्वारा समस्याओं के समाधान किए जा सकते है।

4. स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में संबंद्ध होकर प्रयत्न करने पड़ें। भारत में विभाजन को रोका तो नहीं जा सका परंतु स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कामय रखा गया। यह निश्चय संविधान में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है।

अध्याय 14

राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद का अर्थ हैं एक भोगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों में अपनापन कि भावना होना

राष्ट्रवाद क्या हैं?

– एक राजनीतिक सिद्धांत जिसका अर्थ हैं एक देश जो किसी के अधीन नहीं हैं बल्कि स्वशासित हैं

– राष्ट्रवाद स्वयं का एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने कि बात करता हैं

– राष्ट्र का आत्मनिर्णय का एक अधिकार (केंद्रीय सिद्धांत)

– देश का स्वयं निर्माण का अधिकार (लक्ष्य)

मुख्य बिन्दुः

राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद, राष्ट्र के बारे में मान्यताएं, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्र और बहुलवाद

राष्ट्रवाद क्या हैं? → सामान्यतः यदि जनता की राय ली जाये तो राष्ट्रवाद से आशय राष्ट्रीय ध्वज, देश भक्ति वे देश के लिए बलिदान जैसे बातें ही सुनने को मिलेंगी दिल्ली में राजपथ पर देखें जाने वाली गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक हैं।

पिछली दो शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर सामने आया हैं जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं इसने गुलामी की दासता से मुक्ति दिलाने में सहायता की हैं तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा हैं राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के निर्धारण–पुनर्निर्धारण में योगदान किया हैं।

राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप की कई छोटी–छोटी रियासतों का एकीकरण किया हैं जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हो पाया था राष्ट्रवाद बड़े–बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा हैं बीसवीं शताब्दीं के शुरूआत में यूरोप में आस्ट्रियाई–हंगरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाल साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवाद ही थाः

राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद → राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, उम्मीदों और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता हैं यह कुछ मान्यताओं पर आधारित होता हैं जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं ऐसा माना जाता हैं कि रास्त्रों का निर्माण ऐसे समूहों द्वारा किया जाता हैं कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसी कुछ पहचान का सहभागी होता हैं।

राष्ट्र के बारे में मान्यताएंः

1. **साझे विश्वासः** एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक ही बना रह सकता हैं जब तक उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दुसरे के साथ हैं।

2. **इतिहासः** व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं उनके अन्दर स्थायी पहचान की भावना होती हैं देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किवंदतियों, स्मृतियों तथा इतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं।

3. **भू–क्षेत्रः** किसी भू क्षेत्र पर हाफी हद तक साथ–साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जन साधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती हैं जैसे कोई भू क्षेत्र को मातृभूमि या पितृभूमि कहता हैं।

4. **साझे राजनीतिक आदर्शः** राष्ट्र के सदस्यों की एक साझा दृष्टि होती हैं कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं इन शर्तों के साथ–साथ आना और रहना चाहते हैं।

5. **साझी राजनीतिक पहचानः** लोगों का मानना हैं कि राज्य के बारें में साझी राजनीतिक द्रष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती बल्कि एक समान भाषा या जातीय वंश परम्परा जैसी राजनीतिक पहचान चाहते हैं।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णयः

बाकि सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं दूसरें शब्दों में कहे तो वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता हैं कि उसके प्रथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकार्यता दी जाए।

उन्नीसवीं सदीं में यूरोप में एक संस्कृतिः एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्रत राज्यों का गठन हुआ इस कारण राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए।

अलग–अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग–अलग राष्ट्र राज्य मिले यह ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया पर ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाया

क्योंकि एक राष्ट्र राज्य में एक से ज्यादा नस्ल व संस्कृति के लोग रहते थे।

आश्चर्य की बात हैं जिन राष्ट्र राज्यों ने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की किन्तु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं।

आत्मनिर्णय के आन्दोलनों से कैसे निपटें:

नए राज्यों का गठन करने में समाधान नहीं हैं बल्कि राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में हैं आत्मनिर्णय के आन्दोलन का समाधान यह हैं कि भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिकों तथा मित्रों की तरह सहअस्तित्व पूर्वक रह सकें।

राष्ट्रवाद और बहुलवाद

एक संस्कृति–एक राज्य के विचार को छोड़ने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा करने के तरीकों की शुरूआत की हैं भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं।

हालांकि ऐसा हो सकता हैं कि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं सरंक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह प्रथम राज्य की मांग पर अड़े रहे यह विरोधाभाषी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाए विभिन्न वर्गों और समुदायों को उव्देलित कर रही हैं इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा साथ ही असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्न–

1. कौन–सा राष्ट्रवाद में शामिल नहीं है?
   (i) सामान्य इतिहास
   (ii) सामान्य भूमि क्षेत्र
   (iii) आम धारणा
   (iv) सामान्य धर्म

2. निम्नलिखित में से किस संधि ने नए राज्यों का गठन किया?
   (i) वर्साय की संधि
   (ii) लंदन की संधि
   (iii) पेरसि की संधि
   (iv) न्यूयॉर्क की संधि
3. किसने कहा कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है?
   (i) पंडित नेहरू
   (ii) महात्मा गांधी
   (iii) रविंदर नाथ ठाकुर
   (iv) अरविंद घोष
4. 'राष्ट्र' शब्द किस भाषा से लिया गया है?
   (i) ग्रीक
   (ii) फ्रेंच
   (iii) लैटिन
   (iv) रूसी
5. राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है
   (i) मजबूत ऐतिहासिक विरासत
   (ii) सांप्रदायिकता
   (iii) भावनात्मक एकीकरण
   (iv) सामान्य सभ्यता

अभिकथन और कारण प्रश्न

1. दावा (a) : इटली और जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रवाद मुख्य कारक था
   कारण (R): इटली और जर्मनी के एकीकरण के दौरान बडी हिंसा देखी गई
   (a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
   (b) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
   (c) A सच है, लेकिन R गलत है
   (d) A झूठा है, लेकिन R सच है।

2. दावा (a) : वर्तमान में समय में राष्ट्रवाद की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
कारण (R): पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव की ओर बढ़ रही है

(a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है

(b) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A सच है, लेकिन R गलत है

(d) A झूठा है, लेकिन R सच है।

एक अंकीय प्रश्नों:

1. राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है?
2. 'राष्ट्र' शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहता है?
4. भूक्षेत्र को लेकर लोग उसे क्या–क्या नाम देते है?
5. राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत का क्या अर्थ है?
6. समतामूलक समाज से क्या अभिप्राय है?
7. 'एक संस्कृति–एक राज्य' का सिद्धांत का क्या अर्थ है?
8. जर्मनी व इटली का एकीकरण किस भावना के तहत हुआ था?
9. डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं?
10. आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निबटा जा सकता हैं?

प्रश्न संख्या 11 से 15 में सही या गलत की पहचान कीजिए:

11. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं
12. पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को अपनाया गया।
13. नवगठित राज्यों में एक राज्य में एक ही नस्ल के लोग रहते हैं।
14. रवीन्द्रनाथ टैगोर ओपेनिवेशिक शासन के धुर विरोधी थे।
15. राष्ट्रवाद का बड़े–बड़े राज्यों के पतन और एकीकरण में कोई योगदान नहीं रहा हैं।

दो अंकीय प्रश्नः—

1. ''राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है साथ ही विभाजित भी किया है'' कैसे?
2. ''राष्ट्रवाद साम्राज्यों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा है'' कैसे? कुछ उदाहरण दीजिए।
3. 'राष्ट्र' शब्द और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है?
4. 'सांझे विश्वास' किस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हैं।
5. साझी राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय है?
6. क्या 'राष्ट्रीय आत्मनिर्णय' की मांग समकालीन विश्व में विरोधाभासी है?
7. राष्ट्रीय पहचान के लिए समावेशी नीति से कार्य करने का क्या अर्थ है?
8. बहुलवाद से क्या अभिप्राय है?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. राष्ट्रवाद ने राज्यो को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। कैसे?
2. ''भूमंडलीकरण के दौर में आज भी राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है'' इस समस्या का समाधान कैसे संभव है?
3. ''एक संस्कृति एक राज्य'' इस नीति से क्या अभिप्राय है? क्या यह नीति प्रयोग में लाना संभव है?
4. आत्मनिर्णय के सिद्धांत के द्वारा जिन राष्ट्रों ने स्वाधीनता प्राप्त की, आज वे ही अपने भू–क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग का विरोध करते है? क्यों?
5. राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं?
6. 'राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और संस्कृति पहचान का आदर किया जाएं'। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
7. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एवं सूत्र में बंधा होता है यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गठते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं।

प्र.1 राष्ट्रवाद क्या हैं?

प्र.2. राष्ट्रवाद की सीमाएँ लिखिए।

प्र.3. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहा है?

प्र.4. राष्ट्र क्या है?

8. ''यद्यपि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, परंतु हर जगह एकात्मकता की वह जबर्दस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो''।

8.1 उपरोक्त कथन किसका है?

(A) महात्मा गाँधी (A) रविन्द्रनाथ टैगौर

(C) पंडित नेहरू (D) सरदार पटेल

8.2 लेखक किस विविधता और विभिन्नता की बात कर रहा है?

(A) धर्म, भाषा, जाति (B) राज्य, देश

(C) जमीन, जंगल (D) पड़ोसी देश

8.3 राजनीतिक दुर्भाग्य से लेखक का क्या अभिप्राय है?

(A) परतंत्रता (B) आजादी (C) राष्ट्रवाद (D) विश्वग्राम

8.4 भारत में क्या विविध मात्रा में

(A) विविधता (B) भाषाई विवाद (C) धार्मिक विवाद (D) उपर्युक्त सभी

9. ''राष्ट्रवाद मेरी आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मै हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा।

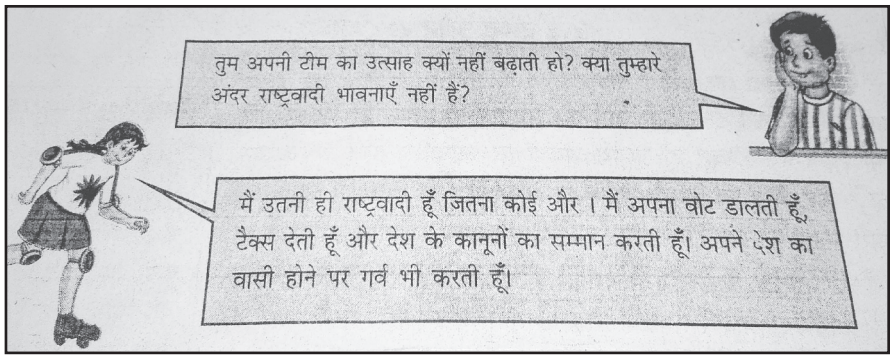

9.1 लेखक राष्ट्रवाद की बजाय मानवता को क्यों महत्व दे रहा है?

(A) मानवता भलाई के काम आती है (B) मानवता उत्तम है

(C) मानवता भ्रष्ट है (D) मानवता आवश्यक है

9.2 'देशभक्ति को मानवता पर विजयी न होने देने' का क्या अभिप्राय है?

(A) देशभक्ति ने साम्राज्यों का पतन किया है

(B) देशभक्ति भ्रष्ट बनाती है

(C) देशभक्ति मानव को कट्टर बनाती है

(D) देशभक्ति आवश्यक नहीं है

9.3 'हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा इस कथन में लेखक ने हीरा और शीशा किसे कहा है?

(A) मानवता व देशभक्ति (B) धर्म व देशभक्ति

(C) देशभक्ति व जाति (D) देशभक्ति

9.4 राष्ट्रवाद से कौन ज्यादा प्रभावित होता है

(A) पुरुष (B) महिला (C) युवा (D) वृद्ध

10.1 सामान्यतया लोग राष्ट्रवाद से क्या अर्थ लगाते हैं?

(A) राष्ट्रीयगायन (B) लड़ाई करना

(C) भ्रष्टाचार (D) चोरी करना

10.2 चित्र में राष्ट्रवाद किस प्रकार दिखाया गया है?

(A) वोट डालना (B) गाली देना

(C) झूठ बोलना (D) लड़ाई करना

10.3 एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं?

(A) समय पर सोना (B) समय पर टैक्स देना

(C) भ्रष्टाचार करना (D) झूठ बोलना

छः अंक वाले प्रश्नः

1. राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करो?
2. ''संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कारगर सिद्ध हुई है? कैसे।
3. राष्ट्रवाद के दायरें क्या–क्या हैं। (सीमाएं)।

उत्तरमाला

क

1. (iv) सामान्य धर्म
2. (i) वर्साय की संधि

3. (iii) रवींद्र नाथ ठाकुर

4. (iii) लेटिन

5. (ii) साम्यवाद

अभिकथन और कारण उत्तरः

1. A सत्य है, लेकिन R गलत है

2. A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, उम्मीदों और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता हैं।

2. एक ही समुदाय जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहता हैं।

3. राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के अन्दर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती हैं।

4. मातृभूमि या पितृभूमि या पवित्र भूमि।

5. जब राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं।

6. भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान वाले देश में समान नागरिकों और मित्रों की तरह सह अस्तित्वपूर्वक रह सकें।

7. एक राज्य में एक ही संस्कृति के लोग निवास करते हैं।

8. राष्ट्रवाद

9. जवाहरलाल नेहरू

10. राज्यों को और अधिक लोकतान्त्रिक और समतामूलक बनाकर

11. सही

12. सही

13. गलत

14. सही

15. गलत

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राष्ट्रवाद ने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ–साथ गहरे विद्वेषों को प्रोत्साहित किया है। इसने जनता को एकत्र किया है तो विभाजित भी किया है।

2. बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में यूरोप में अस्ट्रियाई– हंगेरियाई और रूसी साम्राज्यों के पतन तथा उनके साथ एशिया अैर अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारें में राष्ट्रवाद ही था।

3. राष्ट्रः– राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है यह परिवार से भिन्न है राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है।

राष्ट्रवादः– राष्ट्रवाद एक भावना है, देश प्रेम की भावना जो विकसित होती है साझे विश्वास, साझां इतिहास, साझें भू क्षेत्र साझे राजनीतिक आदर्श तथा साझी राजनीतिक पहचान के द्वारा।

4. साझे विश्वासः– राष्ट्र का निर्माण विश्वास के द्वारा होता है राष्ट्र ऐसी इमारते नहीं जिन्हें हम स्पर्श कर सकें, न ही ये ऐसी वस्तुएं है जिनका लोगों के विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। राष्ट्र की तुलना एक टीम से की जा सकती है।

5. साझी राजनीतिक पहचानः– अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भू–क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं इसलिए अच्छा होगा यदि हम राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में करे न कि सांस्कृतिक पदों में। लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।

6. राष्ट्रीय आत्मविश्वासः– उस वक्त विरोधाभासी लगता है जब हम उन राष्ट्रराज्यों को, जिन्होंने स्वंय संघर्षों के बल पर स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू–क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन कर रहे हैं।

7. समावेशी नीति का आशय है जो राष्ट्र राज्य के समस्त सदस्यों के महत्व एवं अद्वितीय योगदान को मंजूरी दे सके अर्थात् अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार।

8. बहुलवादः जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया गया तब नई व्यवस्था वह होगी जहां अनेक संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी–छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। आज के जर्मनी, इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था।

   किन्तु राष्ट्रवाद बड़े–बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। बीसवीं शताब्दी में यूरोप में आस्ट्रियाई–हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में 'राष्ट्रवाद' ही था।

2. भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है। ऐसी मांगों से निपटने का एक मात्र तरीका लोकतांत्रिक तरीका है। इससे निपटने में संबंधित देश विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय दें।

   परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु एकजातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. एक संस्कृति–एक राज्य की धारणा की शुरूआत 19 वीं सदी के यूरोप में सामने आई परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राज्यों की पुर्नव्यवस्था में इस विचार को परखा गया परंतु आत्म निर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था।

   आज भी इस नीति को प्रयोग में ला पाना संभव नहीं तभी बहुलवाद की प्रचलन है अर्थात् बहुत से समुदाय और संस्कृतियों के लोग एक ही देश में फल फूल सकें।

4. आत्मनिर्णयः क्योंकि इससे आबादी का देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की घटनाएं होती रहती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी नए राष्ट्र राज्य बने उसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बड़ी मात्रा में विस्थापन हुआ, लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से बाहर धकेल दिए गए जहां पीढ़ियों से उनका घर था।

5. (i) सांप्रदायिकता
   (ii) जातिवाद
   (iii) क्षेत्रवाद
   (iv) भाषावाद
   (v) नस्लवाद

6. जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान का आदरनहीं करते उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना कठिन होता है।

इसके लिए राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक व समतामूलक बनना होगा ताकि भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिक और मित्रों की तरह रह सकें।

7. 1. राष्ट्र बहुत हद तक काल्पनिक समुदाय होता है तो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है।

2. राष्ट्रवाद व्यक्ति को एक क्षेत्र तक सीमित कर देता है जिससे विश्वग्राम की भावना अधूरी रह जाती है और यह भूमण्डलीकरण में संभव नहीं हैं

3. राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के अन्दर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है।

4. एक ही समुदाय के लोग जो एक निश्चित भू–भाग में रहते हैं।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

8. (i) पं. जवाहर लाल नेहरू

(ii) धर्म, भाषा, जाति

(iii) परतंत्रता

(iv) विविधता

9. (I) मानवता भलाई के काम आती है।

(ii) देशभक्ति मानव को कटर वनाती है।

(iii) मानवता और देशभक्ति।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (i) साझां इतिहास
   (ii) साझें विश्वास
   (iii) साझां भू–क्षेत्र
   (iv) साझें राजनीतिक आदर्श
   (v) साझीं राजनीतिक पहचान

2. लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक व समावेशी होने के लिए संघर्षवादी ताकतों से निपटने में निपुण होती है बजाय तानाशाही सरकारों के। आज संसार एक विश्व ग्राम का स्वप्न देख रहा है ऐसे में संघर्षवादी शक्तियां उस स्वप्न में बाधा उत्पन्न करती है ऐसी भागों से लोकतांत्रिक ढंग से समाधान किया जा सकता है और इसमें संबंधित देश को अपना योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा।

   यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय पहचान के इनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. (i) क्षेत्रवाद
   (ii) नैतिक मूल्यों का पतन
   (iii) धार्मिक विविधता
   (iv) आर्थिक विषमता
   (v) भाषायी विषमता

अध्याय 15

धर्म निरपेक्षता

धर्म निरपेक्षता का अर्थ

बिना किसी भेद–भाव के सभी भारतीय नागरिकों को अपना–अपना धर्म मानने व प्रसार की स्वतंत्रता

- धर्मों के बीच वर्चस्वाद (मैं श्रेष्ठ की संस्कृति)
- धर्मों के अन्दर वर्चस्वाद (इसमें भी मैं ही श्रेष्ठ)

धर्म निरपेक्ष राज्य

राज्य का अपना कोई धर्म नहीं

धर्म निरपेक्ष का यूरोपीय मॉडल

अमेरिकी मॉडल
यूरोपीय मॉडल
–राज्य व धर्म की पृथकता

धर्म निरपेक्ष का भारतीय मॉडल

–मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त
– 42वें संशोधन द्वारा 1976 में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा
–राज्य व धर्म पूर्णतः पृथक नहीं

मॉडल की आलोचना

–धार्मिक पहचान का खतरा
–परिश्चम से आयातित व अन्य

मुख्य बिन्दुः

1. धर्म निरपेक्षता का अर्थ।
2. धर्मों के बीच वर्चस्ववाद
3. धर्म के अन्दर वर्चस्ववाद
4. धर्म निरपेक्ष राज्य
5. धर्म निरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल
6. धर्म निरपेक्षता का भारतीय मॉडल
7. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
8. भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना

धर्म निरपेक्षता का अर्थ हैः–

– बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना–अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता अर्थात् जब राज्य धर्म को लेकर कोई भेद–भाव न करें।

– भारत विभिन्नताओं का देश है, लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है। इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। संविधान के घोषणा–पत्र में धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध करना, धर्म के अन्दर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अन्दर समानता को बढ़ावा देना आदि की घोषणा करता है।

धर्मों के बीच वर्चस्ववादः–

– हर भरतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के

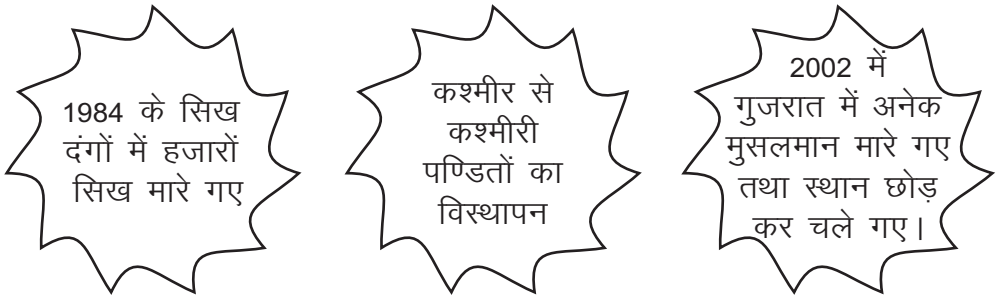

साथ रहने का अधिकार है, फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते है जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ा, क्योंकि हम स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं।

धर्म के अन्दर वर्चस्ववादः–

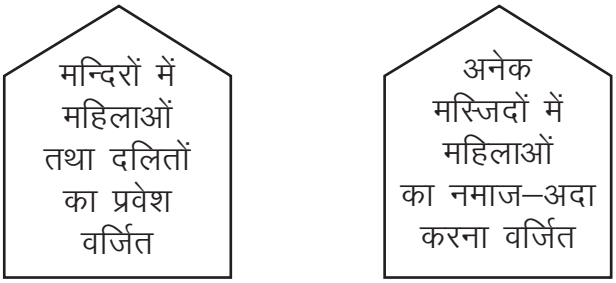

धर्म निरपेक्ष राज्यः–

- वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को अधिकारिक (कानूनी) मान्यता न दी गई हो।
- सर्व धर्म समभाव की अवधारणा को महत्व।
- धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना
- धार्मिक संस्थाओं एवं राज्यसत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी।
- किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज।
- ऐसे लक्ष्यों व सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आज़ादी को महत्त्व दें।

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडलः–

- अमेरिकी मॉडल–धर्म और राज्य सत्ता के संबंधविच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामले में व धर्म राजसत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
- ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है।
- धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिये कोई जगह नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडलः–

- भारतीय धर्म निरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता।

– अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आजादी देता है।
– भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु, धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है।
– भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार है तथा राज्यसत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती हैं।
– भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद 'पंथ निरपेक्ष' शब्द जोड़ दिया है।
– मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः–

– अनुच्छेद 25 से 28 तक

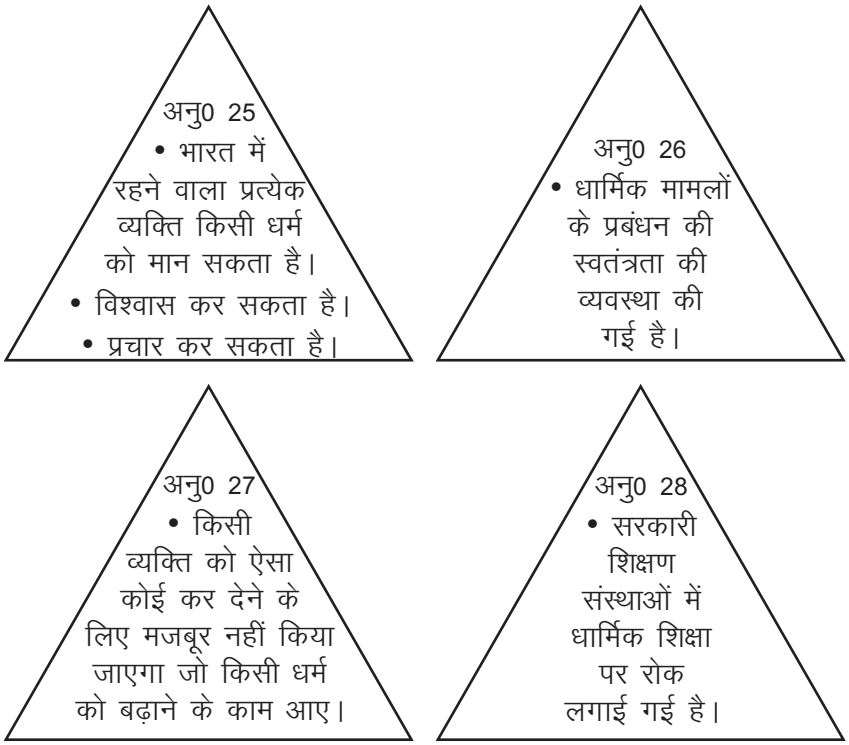

भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचनाएँः

– धर्म विरोधियों के अनुसार धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है।

– पश्चिम से आयातित है।

– अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है।

– वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है।

– अतिशय हस्तक्षेपकारी क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्यसत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है।

असंभव परियोजनाः–

– धर्म निरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है परन्तु यह परियोजना सच्चाई से दूर है जो असम्भव है।

– अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्म निरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती हैं। भारत में महान प्रयोग किए जा रहें है। जिसे पूरा विश्व चाव से देखता है। यूरोप अमेरिका तथा मध्यपूर्व के कुछ देश धर्म संस्कृति की विविधता से भारत जैसे दिखने लगे है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. कथनः अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी धार्मिक विश्वास को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है।

   कारणः राज्य धार्मिक प्रभाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता।

   A—कथन सही है कारण गलत।

   B—कथन गलत कारण सही है।

   C—दोनों सही हैं कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   D—दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है

2. धर्म निरपेक्षता क्या है।
3. धर्मनिरपेक्ष/पंथनिपेक्ष राज्य किसे कहते हैं?
4. क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य हैं?
5. ''अतातुर्क'' का क्या अर्थ है?
6. ''मुस्तफा कमाल पाशा'' ने अपना नाम क्या रखा था?

7. भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था?

8. भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई हैं?

9. धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक विशेषता लिखिए।

10. ''सांप्रदायिकता'' से क्या अभिप्राय है?

11. भारतीय लोकतंत्र को सांप्रदायिकता से क्या खतरा है?

12. भारत किस प्रकार का राज्य है?

(a) हिंदू राज्य (b) मुस्लिम राज्य

(c) धार्मिक राज्य (d) धर्मनिरपेक्ष राज्य

13. भारतीय संविधान के कौन–से अनुच्छेद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई?

(a) 29 से 38 (b) 25 से 28

(c) 19 से 22 (d) 14 से 18

14. धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है?

(a) जो किसी धर्म पर आधारित ना हो

(b) जो हिंदू धर्म पर आधारित हो

(c) जो बहुसंख्यक नागरिकों के धर्म पर आधारित हो

(d) उपरोक्त कोई नहीं

15. भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

(a) 44वां (b) 46वां

(c) 42वां (d) 52वां

16. धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता हैं:

(a) राज्य को कोई धर्म नहीं होता (b) धार्मिक स्वतंत्रता

(c) सभी धर्मों में समानता (d) उपर्युक्त सभी

17. आजाद भारत में ''सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण''। यह कथन किसका है?

(a) महात्मा गांधी का (b) डॉ बी.आर. अंबेडकर का

(c) जवाहरलाल नेहरू का (d) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का

18. भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का एक कारण है:

(a) राज्य का अपना कोई धर्म नहीं

(b) संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है

(c) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है

(d) भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करता है

19. धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा है?

(a) सांप्रदायिक पार्टियां (b) सांप्रदायिकता

(c) जातिवाद (d) उपर्युक्त सभी

20. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

''धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग चार से संबंधित है।''

21. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

जवाहर लाल नेहरू जी स्वयं किसी का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही, वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार, समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

21.1 नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?

(a) राज्य का अपना धर्म विशेष होगा

(b) राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा

(c) राज्य धर्म के लिए कानून बनाएगा

(d) उपर्युक्त कोई नहीं

21.2 नेहरू जी किस धर्म का अनुसरण करते थे?

(a) जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू धर्म का अनुसरण करते थे

(b) जवाहरलाल नेहरू जी बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे

(c) जवाहरलाल नेहरू जी ईसाई धर्म का अनुसरण करते थे

(d) जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे

21.3 नेहरू जी का तुर्की के अतातुर्क से संबंध थाः

(a) अतातुर्क के अनुयाई थे

(b) अतार्तुक के सहयोगी थे

(c) अतातुर्क के विचारों से भिन्न विचार रखते थे

(d) अतातुर्क के विरोध थे

21.4 धर्म और राज्य के बीच संबंधों को लेकर नेहरू जी के विचार थेः

(a) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में थे

(b) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे

(c) नेहरू जी धर्म और राज्य को दो अलग–अलग दृष्टिकोण से देखते थे

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

खाली स्थान भरोः

22. धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं, जो किसी ..... पर आधारित न हो?

23. धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी लोगों को धर्म की ..... प्राप्त होती है।

24. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ..... के अनुसार सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है।

25. 1976 में ..... संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को स्पष्ट शब्दों में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया।

26. नेहरू जी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के ..... थे।

27. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः

(a) भारत एक धर्म तांत्रिक राज्य है

(b) पाकिस्तान एकधर्म तांत्रिक राज्य है

(c) भारत में अलग–अलग जातियों और वर्गों के साथ अलग–अलग व्यवहार किया जाता है।

(d) 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लेटिन रूप में अपनाया गया

(e) सांप्रदायिकता समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है

दो अंकीय प्रश्नः—

1. धर्म शब्द का क्या अर्थ है?
2. धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के दो उपाय बताओ?
3. भारतीय धर्म निरपेक्षता की क्या विशेषता है?
4. धर्म में राज्य की सैद्धान्तिक दूरी से आप क्या समझते है?
5. धर्म निरपेक्षता की दो कमियां लिखो?
6. 20वीं शताब्दी में तुर्की में किस तरह धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया?
7. अंतधार्मिक वर्चस्व का अर्थ स्पष्ट करे?
8. पश्चिमी धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? ये वर्चस्ववाद का उदाहरण कैसे हैं?
9. किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्था बनाने की अनुमति होना क्या धर्म निरपेक्षता है? कारण बताइए?

चार अंकीय प्रश्नः—

1. धर्म निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा तथा पश्चिमी अवधारणा में क्या अन्तर है?
2. सम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है? इसे रोकने के उपाय बताइए?
3. भारत में धर्म निरपेक्षता अपनाने के क्या कारण है?
4. धर्म निरपेक्ष राज्य की आलोचना क्यों की जाती है?

छः अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
2. भारतीय धर्म निरपेक्षता का जोर धर्म और राज्यों के अलगाव पर नहीं अपितु उससे अधिक किन्हीं बातों पर है। इस कथन को समझाइए?
3. क्या धर्म निरपेक्षता नीचे लिखी बातों के लिए न्याय संगत है?
   (i) अल्पसंख्यक समुदाय के तीर्थ स्थल के लिए आर्थिक अनुदान देना?
   (ii) सरकारी कार्यालयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना?

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (c) दोनों सही है कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार/राज्य का यह कर्तव्य है कि विभिन्न धर्मों के बीच बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करना।
3. धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य वह होता है, जिसका अपना कोई धर्म/पंथ नहीं होता तथा जो अपने नागरिकों पर कोई धर्म/पंथ का पालन करने का दबाव नहीं डालता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धर्म–तांत्रिक होते हैं, और न ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं।
4. हां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका वर्णन आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
5. ''अतातुर्क'' का अर्थ होता है, ''तुर्कों का पिता''।
6. मुस्तफा कमाल पाशा ने अपना नाम बदलकर ''कमाल अतातुर्क'' रख लिया था।
7. भारतीय संविधान में पंथनिपरेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था।
8. भारतीय संविधान में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दी गई है।
9. धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। वह किसी धर्म विशेष का संरक्षण नहीं करना और न ही कानूनों का निर्माण धर्म के आधार पर करता है।
10. साम्प्रदायिकता से अभिप्राय मनुष्य की उस संकीर्ण सोच है जो धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर पूरे समाज व राष्ट्र के विरोधी तथा धर्म के हितों को महत्व देती है।
11. भारत में अराजकतावादी तत्त्वों द्वारा साम्प्रदायिक दंगे करवाये जाते हैं, तब भारत में लोकतंत्र प्रभावित होता है तथा इससे सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
12. (d) धर्मनिरपेक्ष राज्य

13. (b) 25 से 28

14. (a) जो किसी धर्म पर आधारित ना हो

15. (c) 42वां

16. (d) उपर्युक्त सभी

17. (c) जवाहरलाल नेहरू का

18. (c) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है

19. (d) उपर्युक्त सभी

20. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन से संबंधित है

21.1 (b) राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा

21.2 (d) जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे।

21.3 (c) अतातुर्क के विचारों से भिन्न विचार रखते थे।

21.4 (b) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे

खाली स्थान भरोः

22. धर्म

23. स्वतंत्रता

24. अनुच्छेद 25

25. 42वां संविधान संशोधन

26. दार्शनिक

27. (a) गलत (b) सही (c) गलत (d) सही (e) सही।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः—

1. कर्त्तव्य का पालन करना

   धर्म के अनेक पंथ सम्मिहित होते है।

2. i) राज्यसत्ता चलाने वाला किसी धर्म से सम्बन्धित न हो।

   ii) किसी धर्म की तरफदारी न करना।

3. बिना किसी धार्मिक भेदभाव के संविधान में समानता का अधिकार, सभी को अपना धर्म मानने की छूट, कानून के समक्ष समानता बगैर धर्म की परवाह के।

4. राज्य का अपना कोई धर्म नहीं।

5. i) वोट बैंक की राजनीति।

ii) एक असंभव परियोजना।

6. i) मुस्लमान की एक विशेष टोपी पहनने पर रोक।

ii) पश्चिमी पोशाक पहनने पर बल।

7. i) विशेष धर्म के अन्दर किसी विशेष समुदाय का बोल बाला या मनमानी करवाना।

ii) महिलाओं तथा दलितों का शोषण व भेदभाव

8. i) धर्म तथा राजसत्ता का सम्बन्ध अलग–अलग।

ii) दोनों एक दूसरें में हस्ताक्षेप नहीं करते।

iii) इंटरनेट का प्रयोग, पश्चिमी पोशाक का पहनना मैकडोन्लड का खाना पीना जैसी लाखों चीजों का प्रचलन वर्चस्ववाद कहलाता है।

9. हाँ, धर्म निरपेक्षता है क्योंकि अनुच्छेद 29 के अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।

अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यक तथा अन्य सभी अपनी रूचि की शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. i) भारत में धार्मिक सहनशीलता है जो पश्चिमी देशों में नहीं है।

ii) विभिन्नता के साथ भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यकों को सरंक्षण प्रदान।

2. अपने धर्म को अधिक महत्व देना दूसरे धर्म को हीन समझना।

i) भेदभाव करने वाली राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना।

ii) अधिकारियों को दण्डित करना

iii) शिक्षा सामग्री में बदलाव

iv) भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर रोक

3. विभिन्न भाषा, जाति, धर्म के लोगों ने बंधुता समानता एकता बनाए रखने के लिए।

4. i) धर्म निरपेक्षता एक असंभव परियोजना मानी जाती है।

ii) वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

iii) अल्पसंख्यकों संख्यकों को आर्थिक सहायता जो समानता के अधिकार का विरोध

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. 1. धर्म विरोधी,

   2. पश्चिम से आयतित,

   3. अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा,

   4. हस्तक्षेपकारी,

   5. वोट बैंक की राजनीति एक असंभव परियोजना।

2. लोगों में प्रेम, बंधुता, एकता की भावना पैदा करना, अखण्डता को बचाना, अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति भाषा का विकास।

3. i) हां, ये न्यायसंगत है, ताकि अल्पसंख्यक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें आर्थिक रूप से पिछड़ों की भावनाओं का आदर।

   ii) नहीं, ये धर्म निरपेक्षता के विरूद्ध है क्योंकि सरकारी कार्यालय किसी विशेष धर्म का अनुष्ठान करना अन्य धर्मों का विरोधी है।

PRACTICE PAPER

एक अंकीय प्रश्न

1. हमें संविधान क्यों चाहिए?
2. FPPS की फुल फार्म या पुरा नाम लिखों ।
3. राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता हैं?
4. राज्य सभा चुनावों में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है।
5. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है?
6. भारतीय चुनाव आंयोग को स्वतन्त्र क्यों बनाया गया हैं?
7. कार्यपालिका के प्रकार लिखो।
8. भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका अपनाई गई है?
9. राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ लिखो।
10. भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या राष्ट्रपति का कोई योगदान होता है?
11. भारत में स्थायी कार्य पालिका का चुनाव किस प्रकार होता है?
12. राज्यसभा में 12 सदस्य क्यों मनोनीत किये जाते हैं?
13. लोकसभा में किस प्रकार का बिल निजी बिल कहा जाता है?
14. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है?
15. राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है?
16. न्यायिक सक्रियता क्या होती है?
17. उच्चतम न्यायालय में हाल ही में किसी विषय पर फाईल की गई PIL का नाम लिखों।
18. संघवाद क्या होता है?
19. भारत में संघवाद कहाँ से लिया गया है?
20. समवर्ती सूची क्या होती है?

21. भारत में पहला नगर पंचायत कहाँ स्थापित हुआ था?
22. भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है?
23. फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था?
24. 'ऑन लिबर्टी' पुस्तक किसने लिखी?
25. स्थानीय सरकार को सवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया?
26. भारतीय संसद के भाग लिखों।
27. भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है?
28. 'लांग वाक टु फ्रीडम' पुस्तक किसने लिखी?
29. सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है?
30. नारीवाद से आप क्या समझते हैं?
31. कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है?
32. राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझओं।
33. धर्मनिरपेक्षता क्या होती है?
34. राष्ट्रवाद के 2 मान्यताए लिखो।
35. सबसे पहले लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग किसने की?

दो अंक वाले प्रश्न

1. विधायिका के प्रकार लिखों।
2. भारत में संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है?
3. राष्ट्र शब्द से क्या समझते हैं?
4. भारत का संविधान संघीय संविधान क्यों कहा जाता है?
5. कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है?
6. भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। स्पष्ट कीजिए?
7. सवैंधानिक उपचारों से आप क्या समझते हैं।

8. दो सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को लिखों।
9. स्वराज शब्द की व्याख्या करो।
10. नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती हैं?

कथन–कारण वाले प्रश्न

1. कथन – चुनाव आयुक्त बिना किसी दबाव के काम करता है

   कारण – चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है।

   (1) A व R दोनों सही है व R सही A की सही व्याख्या करता हैं।

   (2) A दोनों R सही है पर R, A की सही व्याख्या नही करता हैं।

   (3) A सही है व R गलत है।

   (4) A गलत है व R सही हैं।

2. कथन– राजनीति विज्ञान और राजनीति दो अलग–2 विचार धारा है।

   कारण – राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पहले होता है यह नैतिकता पर आधारित है जबकि राजनीति का मतलब अवसरवादिता और सुविधा है।

   (1) A व R दोनों गलत हैं

   (2) A व सही है व R गलत है व R, A की सही व्याख्या करता हैं।

   (3) A सही है व R गलत है।

   (4) A व R दोनो सही है पर त्ए। की सही व्याख्या नही करता है।

3. कथन – स्वतंत्रता व व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं

   कारण – भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार देता है

   (1) A सही है व R गलत है

   (2) A व R दोनो सही है और R, A की सही व्याख्या करता है।

   (3) A सही है व R गलत है

   (4) उपरोक्त सभी सही है।

4. कथन – राष्ट्रपति के लिए कानून के समक्ष समानता लागू नही होता।
   कारण – भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कहा विशेषधिकार दिये जाते है।
   (1) A व R दोनों सही है व R, A की सही व्याख्या करता है।
   (2) A सही है व R गलत है
   (3) A व R दोनों सही है लेकिन R, A की सही व्याख्या नही करता है।
   (4) दोनो गलत है।

चार अंकीय प्रश्न

1. संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यतायें कौनसी है?
2. भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
3. ''राजनीति हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है'' स्पष्ट कीजिए।
4. सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वतंत्रता में अन्तर लिखिए।
5. देश में समानता को किस प्रकार बढावा दिया जा सकता है? किन्ही चार कदमों का उल्लेख कीजिए।
6. 'आत्मनिर्णय के अधिकार' आन्दोलनों से किस प्रकार निपटा जा सकता है?
7. भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है?
8. सर्वोच्च न्यायलय द्वारा जारी की जाने वाली रिटो का उल्लेख करें।
9. स्थानीय शासन का क्या महत्व है?
10. न्याय में देरी भी अन्याय है'' इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करें।

छः अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, उदाहरण सहित लिखिए।
2. भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के छः सुझाव लिखिए।
3. राष्ट्रपति की शक्तियों को समझाइए।

4. हमें संसद के दो सदनों की क्या आवश्यकता है?
5. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
6. आप स्थानीय सरकार के बारे में क्या समझते हैं?
7. हम राजनीतिक सिद्वान्त क्यों पढ़ते हैं? समझाइए।
8. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध क्या होगें?
9. रॉल्स के न्याय सिद्वान्त की व्याख्या कीजिए।
10. अधिकार और कर्त्तव्य के बीच क्या सम्बन्ध हैं? समझाइए।

नोटः– अधिक प्रश्नों के लिए सर्पोट मेटेरियल देखे।

PRACTICE PAPER (2022-23)
Class-XI

निर्देश:

(i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रश्न संख्या 1–12 एक–एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।

(iii) प्रश्न संख्या 13–18 प्रत्येक 2 अंक के हैं। इन प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

(iv) प्रश्न संख्या 19–23 प्रत्येक के 4 अंक हैं। इन प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 100 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

(v) प्रश्न संख्या 24–26 पैसेज, काटूर्न और मानचित्र आधारित प्रश्न हैं। तदनुसार उत्तर दें।

(vi) प्रश्न संख्या 27–30 प्रत्येक के 6 अंक हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 170 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

खण्ड–अ

1. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन–सा प्रावधान वस्तुतः बिना किसी बहस के पारित किया गया था?

   (a) सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय

   (b) मौलिक अधिकार

   (c) राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांत

   (d) संसदीय लोकतंत्र

2. संविधान सभा के सदस्य थे:

   (a) सीधे निर्वाचित

(b) कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत

(c) अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित

(d) गवर्नर–जनरल और गवर्नर द्वारा नियुक्त

3. चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकरण है:

(a) प्रधानमंत्री

(b) राष्ट्रपति

(c) राज्यपाल

(d) मुख्य चुनाव आयुक्त

4. मतदान समाप्त होने के बाद, मतों की गिनती किसकी देखरेख में की जाती है।

(a) चुनाव आयोग

(b) मतदान अधिकारी

(c) रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक

(d) परीसीमन अधिकारी

5. इस दौरान संसद के सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(a) स्थगन प्रस्ताव

(b) प्रश्न घंटा

(c) अविश्वास प्रस्ताव

(d) शून्य घंटे

6. विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव को केवल लाया जा सकता है।

(a) राज्यसभा

(b) लोकसभा

(c) योजना आयोग

(d) अनुमान समिति

7. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके द्वारा प्राप्त किया गया है।

(a) जवाहर लाल नेहरू

(b) चरण सिंह

(c) वी पी सिंह

(d) लाल बहादुर शास्त्री

8. राष्ट्रपति को हटाया जा सकता हैः

(a) राज्यसभा

(b) लोकसभा

(c) चुनावी कॉलेज

(d) महाभियोग

9. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैः

(a) संसद

(b) प्रधानमंत्री

(c) राष्ट्रपति

(d) कैबिनेट

10. ..... सरकार आम लोगों के सबसे करीबी सरकार होती है।

(a) स्थानीय

(b) संघ

(c) राज्य

(d) प्रांतीय

11. हिंद स्वराज के लेखक की पहचान करें।

(a) जेएल नेहरू

(b) डॉ. राधा कृष्णनी

(c) महात्मा गांधी

(d) गोखले

12. डॉ. अम्बेडकर और गांधी निम्नलिखित में से किस पर सहमत नहीं थे–

(a) निजी क्षेत्र में आरक्षण

(b) आरक्षण

(c) न्यायपालिका की भूमिका

(d) कुटीर उद्योग की भूमिका

खण्ड–ब

13. पूर्ण स्वतन्त्रता से आप क्या समझते हैं?

14. आनुपातिक न्याय से आप क्या समझते हैं?

15. सार्वभौम अधिकारों से आप क्या समझते हैं?

16. रंगभेद क्या है? नागरिकता पर इसके प्रभाव की चर्चा करें।

17. बहुलवाद से आप क्या समझते हैं?

18. धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं लिखिए।

19. स्वतंत्रता के लिए प्रतिबन्ध क्यों आवश्यक हैं?

20. राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र की व्याख्या करें।

21. समानता के सकारात्मक पहलू के अनिवार्य तत्व क्या हैं?

22. आरक्षण सामाजिक न्याय में कैसे मदद करता है?

23. भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए।

खण्ड–स

24. नीचे दिए गए गद्यांश (एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ सं. 70) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

चुनाव आयोग के पास खुद के बहुत सीमित कर्मचारी हैं। यह प्रशासनिक तंत्र

की मदद से चुनाव आयोजित करता है। हालांकि, एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, चुनाव से संबंधित कायोऊ के संबंध में प्रशासन पर आयोग का नियंत्रण होता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, राज्य और केंद्र सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी ड्यूटी सौंपी जाती है और इस संबंध में चुनाव आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। चुनाव आयोग अधिकारियों का तबादलता कर सकता है या उनका तबादला रोक सकता है; गैर–पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने में विफल रहने पर यह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

1. चुनाव आयोग चुनाव कैसे आयोजित करता है?
2. चुनाव प्रक्रिया के दौरान, चुनाव संबंधी कार्य किसे सौंपा जाता है?
3. चुनाव आयोग की शक्तियां क्या हैं?
4. चुनाव आयोग कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे करता है?

25. नीचे दिए गए कार्टून (एनसीईआरटी पाठ्पुस्तक, पृष्ठ 108) को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

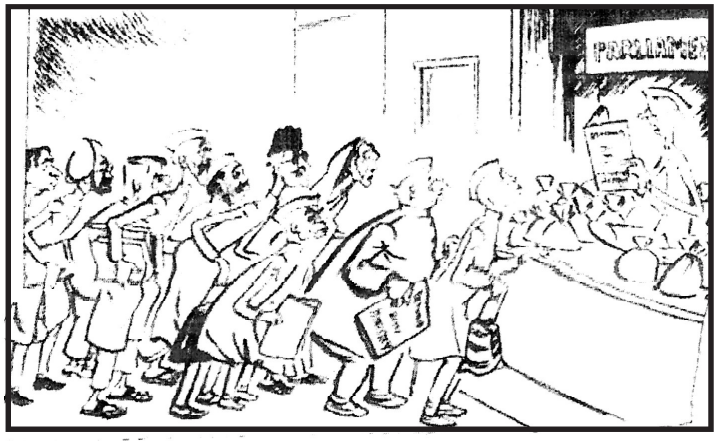

1. कार्टून क्या दर्शाता है?
2. संसद वित्तीय रूप से कार्यकालिका पर किस प्रकार नियंत्रण करती है?
3. संसद की वित्तीय शक्तियां क्या हैं?
4. कौन–सा सदन धन विधेयक पारित कर सकता है?

26. नीचे दिए गए गद्यांश (एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ 95) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

भारतीय नौकरशही आज एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, स्थानीय सरकारों के कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने वाले तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारी शामिल हैं। हमारे संविधान के निर्माता निष्पक्ष और पेशेवर नौकरशाही के महत्व से अवगत थे। वे यह भी चाहते थे कि सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को योग्यता के आधार पर निष्पक्ष रूप से चुना जाए। इसलिए, संघ लोक सेवा आयोग को भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया को संचालित करने का कार्य सौंपा गया है। इसी तरह के लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए भी प्रदान किए जाते हैं। लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। उनका निष्कासन या निलंबन सर्वोच्च न्यायलय कि किसी न्यायाधीश द्वारा की गई गहन जांच के अधिन है।

1. नौकरशाही से आप क्या समझते हैं?
2. भारतीय नौकरशाही कौन–कौन शामिल होते हैं?
3. लोक सेवकों की नियुक्ति कैसे की जाती है?
4. लोक सेवकों को कैसे हटाया जा सकता है?

खण्ड–द

27. न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों के संबंधित है? क्या इससे मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार करने में मदद मिली है?
28. भारतीय संविधान की चार विशेषताओं की सूची बनाएं जो राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करती हैं।
29. भारतीय धर्मनिरपेक्षता का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
30. राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है?

नोट्स